



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245901
CG-DL-E-17052023-245901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]
No. 123]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2023/वैशाख 25, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2023/VAISAKHA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसजी)-02/2022

विषय : भारत में 2 पीपीएम से अधिक मात्रा वाले अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (आरवीसीएम) सहित पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सेस्पेंशन रेजिन के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच।

फा. सं. 22/2/2022-डीजीटीआर.—अंतिम जांच परिणाम—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही।

क. प्रस्तावना

1. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष केम प्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें आगे “आवेदक” या “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) द्वारा रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) की धारा 9क के अन्तर्गत 15 जुलाई, 2022 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें भारत में 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (आरवीसीएम) मात्रा वाले

पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन रेजिन (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय लागू करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं और ऐसी स्थितियों के अन्तर्गत हो रहा है जिनसे भारत में “समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु” का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है।

2. और यतः, आवेदकों द्वारा दायर विधिवत् रूप से साक्षात्कृत याचिका और संबद्ध वस्तु के आयातों में हाल में, अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के रूप में परिणामी क्षति के संबंध में प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के मद्देनजर प्राधिकृत अधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 16 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2/2022 –डीजीटीआर के माध्यम से रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच शुरू की थी ताकि आयातों में कथित वृद्धि और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति के समाधान के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय लगाने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - क. नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसार दिनांक 16 सितंबर, 2022 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति केन्द्र सरकार अर्थात् वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, प्रमुख निर्यातक देशों के भारत में स्थित दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों और हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी।
 - ख. निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्तर देने के लिए प्रश्नावली उक्त नियमावली के नियम 6(4) के अन्तर्गत यथा-विहित ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे जांच शुरुआत की सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।
 - ग. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं को प्राधिकृत अधिकारी के पास पंजीकृत किया है:
 - i. ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, ताईवान
 - ii. ट्रेड एंड इकॉनामिक सेक्शन, भारत में यूरोपीय संघ का शिष्टमंडल
 - iii. ट्रेड इंटरेस्ट एंड रेमिडीज डिविजन, विदेश व्यापार विभाग, थाइलैंड
 - iv. जनरल अथॉरिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड, दि गवर्नमेंट ऑफ दि किंगडम ऑफ सऊदी अरब
 - v. डायरेक्टर ऑफ ट्रेड डिफेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री आफ ट्रेड इंडोनेशिया
 - vi. दि मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मलेशिया सरकार
 - vii. भारत में मेक्सिको का दूतावास, नई दिल्ली
 - viii. पीटी. नास बराका इंटरनेशनल
 - ix. एजीसी विनथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड
 - x. एलजीसी पेट्रोकेमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलजीसीपीआईएन)
 - xi. एलजी केम. लिमिटेड
 - xii. चाइना जनरल प्लास्टिक्स कार्पोरेशन
 - xiii. सीजीपीसी पोलिमेर कार्पोरेशन
 - xiv. चिपिंग जिनफा पोलिविनाइल क्लोराइड कंपनी, लिमि.

- xv. सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कं., लिमिटेड
 - xvi. सीएनएसआईजी जिलनताई क्लोर-एलकाली केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xvii. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन
 - xviii. इनर मंगोलिया इरडोस इलैक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जि ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - xix. इनर मंगोलिया जनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - xx. ओरडोस जनझेंग एनर्जी एंड केमिकल कंपनी, लिमिटेड
 - xxi. शांक्सी बेईयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
 - xxii. शानडोंग जिनपवफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - xxiii. तियानजिन बोहुआ केमिकल डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
 - xxiv. तियानजिन एलजी बोहई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xxv. जिनिजियांग झोंगतई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड
 - xxvi. यिविन तियानयुआन ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
 - xxvii. जिनजियांग झोंगतई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xxviii. पीटी. रझा केमेरलंग बेरकारया
 - xxix. केम वन – सियेगे सोशल
 - xxx. चाइन क्लोर – अलकाली इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - xxxix. तियानजिन एलजी बोहई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xxxii. हन्वा साल्युशंस कार्पोरेशन
 - xxxiii. सीपी औरोरा इम्पैक्स
 - xxxiv. मैसर्स सांखला इंडस्ट्रीज
 - xxxv. संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xxxvi. मिदास पोलीकेम एलएलपी”
 - xxxvii. कैनेडियन स्पेशलिटी विनयाल्स
 - xxxviii. दि प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
 - xxxix. आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर ऑफ इंडिया
 - xl. दि ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - xli. श्री एक्जिम
 - xlii. इंडियन विनाइल काउंसिल
- घ. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
- i. सीजीपीसी पोलिमर्स कार्पोरेशन
 - ii. चाइना जनरल प्लास्टिक्स कार्पोरेशन
 - iii. चिपिंग जिनफा पोलीविनाइल क्लोराइड कंपनी, लिमि.
 - iv. सीएनएसआईजी इनर मंगोलिया सोडियम इंडस्ट्री कं., लिमिटेड

- v. सीएनएसआईजी जिलनताई क्लोर-एलकाली केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - vi. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन
 - vii. इनर मंगोलिया इरडोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - viii. इनर मंगोलिया जनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - ix. ओरडोस जनझेंग एनर्जी एंड केमिकल कंपनी, लिमिटेड
 - x. शांक्सी बेईयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
 - xi. शानडोंग जिनफा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - xii. तियानजिन बोहुआ केमिकल डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
 - xiii. तियानजिन एलजी बोहई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xiv. जिनजियांग झोंगतई केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xv. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
 - xvi. पीटी. रझा केमेरलंग बेरकारया, इंडोनेशिया
 - xvii. हन्वा साल्युशंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (साउथ कोरिया)
- ड. इसके अलावा, निम्नलिखित पक्षकारों ने जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर दिया है:
- i. ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, ताईवान
 - ii. दि गवर्नमेंट ऑफ दि किंगडम ऑफ सऊदी अरब
 - iii. ट्रेड एंड इकॉनामिक सेक्शन, डेलिगेशन ऑफ दि यूरोपियन यूनियन टू इंडिया।
 - iv. ट्रेड इंटरेस्ट एंड रेमिडीज डिविजन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, थाईलैंड
 - v. जनरल अथॉरिटी ऑफ फारेन ट्रेड, दि गवर्नमेंट ऑफ दि किंगडम ऑफ सऊदी अरब
 - vi. डायरेक्टर ऑफ ट्रेड डिफेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडोनेशिया
 - vii. दि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया
 - viii. एम्बेसी ऑफ मेक्सिको इन इंडिया, नई दिल्ली
 - ix. एजीसी विनिथाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड
 - x. पीटी. नास बाराकास इंटरनेशनल
 - xi. सीवी औरोरा इम्पैक्स
 - xii. इंडियन विनाइल काउंसिल
 - xiii. चाइना क्लोर-अल्काली इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - xiv. आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया
 - xv. दि ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - xvi. दि प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
- च. दो आयातकों, अर्थात् श्री एक्जिम और संखला इंडस्ट्रीज ने अनुरोध या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

- छ. प्राधिकृत अधिकारी ने 1 जनवरी, 2022 – 30 जून, 2022 को सबसे हाल की अवधि माना है और जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2019 – 30 जून, 2022 शामिल हैं।
- ज. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के समस्त अगोपनीय अंश (एनसीवी) तक पहुंच प्रदान करने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय अंश का ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से आदान-प्रदान करने की सलाह दी गई थी।
- झ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी ने डिजिटल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 31 अक्टूबर, 2022 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को खंडन अनुरोधों के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध और खंडन अनुरोध प्रस्तुत किए थे:
- i. चाइना क्लोर-अल्काली इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - ii. सीएनएसआईजी जिलनताई क्लोर-एलकाली केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - iii. इनर मंगोलिया जनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
 - iv. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया
 - v. ओरडोस जनझेंग एनर्जी एंड केमिकल कंपनी, लिमिटेड
 - vi. आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर ऑफ इंडिया
 - vii. शांक्सी बेईयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
 - viii. ताइपेई इकाॅनामिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया
 - ix. दि ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 - x. दि प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
 - xi. ट्रेड एंड इकाॅनामिक सेक्शन, ईयू
 - xii. जिनजियांग झोंगतई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - xiii. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
- ञ. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने तक इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।
- ट. प्राधिकृत अधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो आवश्यक समझी गई और संभव सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकृत अधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

- ड. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है, या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने, ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- ढ. अंतिम जांच परिणाम के अगोपनीय अंश में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- ण. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर+76.92 रुपए है।
- त. महानिदेशक (सिस्टम्स) से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था।
- थ. प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जरिए लागू किया जा सकता है।

ग. लागू विधिक प्रावधान

4. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क में यदि वस्तुओं का भारत में ऐसी बड़ी हुई मात्राओं और ऐसी दशाओं में आयात किया जाता है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाती हों या उनसे इसका खतरा है तो मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय लागू करने का प्रावधान है।
5. रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 को वह रीति उपलब्ध कराने के लिए धारा 9क(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है, जिसमें मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने वाले आयातों की वस्तु की पहचान की जाए और ऐसी वस्तुओं के संबंध में आयातों में उछाल के कारण गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे को निर्धारित किया जाए।
6. टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा रक्षोपाय लागू करने के लिए नियमावली निर्धारित की गई है।
7. यह जांच अधिनियम और नियमावली के उक्त प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना के माध्यम से दर्ज किए गए हैं।

घ. सूचना का स्रोत

8. जांच की शुरुआत के समय आवेदकों ने अप्रैल, 2018 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की थी। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना जारी करते समय – यह निर्णय लिया कि जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2022 तक की होगी। घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में अप्रैल, 2019 से जून, 2022 की अवधि के लिए संगत सूचना (आयात और क्षति आंकड़े) प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने दिनांक 18 जूनवरी, 2023 के ईमेल द्वारा जुलाई-सितंबर 2022 की अवधि के लिए क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है; इसका एक अगोपनीय अंश 19 जनवरी, 2023 के उनके ईमेल द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। चूंकि आवेदकों का दावा था कि वर्तमान अचानक वृद्धि अवधि के दौरान उत्पाद के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा था, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर बढ़े हुए आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई-सितंबर, 2022 की अवधि हेतु क्षति संबंधी सूचना का विश्लेषण करना उचित समझा है।
9. प्राधिकृत अधिकारी ने 1-4-2018 से 30-06-2022 की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के सत्यापन हेतु महानिदेशक (सिस्टम्स) से आयात आंकड़े मंगाए थे। महानिदेशक (सिस्टम्स) के आंकड़े प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ महानिदेशक(सिस्टम्स) से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ड. विचाराधीन उत्पादन और समान वस्तु

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकृत अधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन इसके बारे में भ्रम उत्पन्न करते हैं।
- ख. आरवीसीएम मात्रा के आधार पर संबद्ध वस्तु के अलग करना गलत है क्योंकि पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड को वैश्विक रूप से आरवीसीएम मात्रा के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- ग. विभिन्न देशों के आरवीसीएम मात्रा के लिए अलग-अलग मानक हैं। चीन और अमरीकी वस्तु के मानक समान हैं जो 5 पीपीएम पर निर्धारित हैं।
- घ. 2 पीपीएम से अधिक और आरवीसीएम के 2 पीपीएम से कम के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें समान वस्तु माना गया है।
- ड. बल्क मास पोलिमराइजेशन, इमलसन पोलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के ज़रिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन को प्रौद्योगिकी के आधार पर बाहर रखना पूर्व जांचों में निर्धारण के अनुसार किसी उत्पाद के अपवर्जन का एक कारक नहीं हो सकता है।
- च. आरवीसीएम मात्रा को जांच रिपोर्ट या भारतीय सीमा शुल्क के समक्ष आयातकों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण प्रमाण-पत्र के आधार पर आकलित किया जाना चाहिए।
- छ. आवेदकों ने विरोधाभासी विवरण दिए हैं जिनमें वस्तु में आरवीसीएम मात्रा का पता लगाने के लिए विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर उन्होंने भरोसा किया है जबकि यह भी दावा किया है कि ऐसे प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- ज. प्रतिवादी निर्यातकों ने 2 पीपीएम आरवीसीएम से अधिक के पीवीसी सस्पेंशन का उत्पादन या निर्यात नहीं किया है, जैसा प्रस्तुत विश्लेषण प्रमाण-पत्र से देखा जा सकता है।
- झ. प्राधिकारी चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की वास्तविक आरवीसीएम मात्रा के सत्यापन के लिए मौके पर सत्यापन कर सकते हैं।
- ञ. वीसीएम मात्रा को चीन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानक के आधार पर आकलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि भारतीय सीमा शुल्क के पास आयातकों द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट या विश्लेषण प्रमाण-पत्र के आधार पर आकलित किया जाना चाहिए।
- ट. यद्यपि चीन समेत अन्य देशों ने आरवीसीएम मात्रा के लिए बेंचमार्क तय किए हैं जो 5 पीपीएम का बेंचमार्क है, तथापि चीन और अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित और निर्यातित वस्तु सामान्यतः 2 पीपीएम से कम की होती है।
- ठ. केवल इसलिए कि विनिर्देशन शीट में 5 पीपीएम से कम का उल्लेख है, यह स्वतः अर्थ नहीं हो जाता है कि आयातित उत्पाद 2 पीपीएम से अधिक का है।
- ड. यह भी अनुरोध किया गया था कि उपर्युक्त सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए डीजी सिस्टम्स डेटा की समीक्षा करने पर, यह नोट किया जाता है कि एचएस कोड (सीटीएच) केवल 39041020 है। जबकि, हम समझते हैं कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को कई एचएस कोड जैसे 39041090, 39042110, 39042190, 39042200, आदि के तहत आयात किया जाता है। विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा से नमूना स्क्रीनशॉट प्रदान किए जा रहे हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है क्योंकि ये एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, समान उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
- ख. यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को समान उत्पाद नहीं माना जाए तो भी यह “प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद” है जो विचाराधीन उत्पाद की विशेषताओं से काफी मिलता-जुलता है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक ने दायरा स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा है और यह अनुरोध केवल ट्रेड एंड इकानामिक सेक्शन, यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद मुख्यतः चीन जन.गण. से आयातित होता है जबकि 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अन्य देशों से आयातित और भारत में उत्पादित होता है।
- ङ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को भारत सरकार द्वारा बीआईएस मानक आईएस 17658:2021 बनाकर वर्गीकृत किया गया है। अन्य देशों द्वारा अधिसूचित मानक महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि इस उत्पाद को भारतीय मानकों के संबंध में परिभाषित किया जाता है।
- च. विनिर्देशन शीटों के अनुसार चीन जन.गण. से कुछ उत्पादकों के पास 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम मात्रा है परंतु अधिकांश उत्पादकों के पास 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम मात्रा है।
- छ. आरवीसीएम मात्रा पर आधारित वर्गीकरण न्यायोचित है क्योंकि यह उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभिन्न देशों तथा वेबसाइटों के मानक, विनिर्देशन शीट और विश्लेषण प्रमाण-पत्र में यह निहित है।
- ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोधाभासी अनुरोध किए हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि विचाराधीन उत्पाद को आरवीसीएम मात्रा के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तथापि, उन्होंने यह भी बताया है कि विभिन्न देशों ने आरवीसीएम मात्रा के लिए अलग-अलग मानक विहित किए हैं।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत विनिर्देशन शीट कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद दर्शाती है और न कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक।
- ञ. विश्लेषण प्रमाण-पत्र प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इसे किसी एक लॉट या उत्पादित बैच या पोतलदान की गई खेप के लिए जारी किया जाता है और न कि उत्पादक द्वारा आमतौर पर उत्पादित उत्पाद के लिए। यदि विश्लेषण प्रमाण-पत्र 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम दर्शाता है तो वह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का निश्चयात्मक साक्ष्य है। तथापि, 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम दर्शाने वाले विश्लेषण प्रमाण-पत्र का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि उत्पादक ने हमेशा 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी का उत्पादन किया है।
- ट. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम का पीवीसी सस्पेंशन रेजिन 2 पीपीएम से अधिक या 2 पीपीएम और 5 पीपीएम के बीच आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की तुलना में कम शुद्धता वाला उत्पाद होता है। चूंकि अधिकांश देशों को 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की जरूरत होती है, इसलिए कम शुद्धता वाले उत्पाद का विनिर्माण करने वाले किसी उत्पादक द्वारा उसकी विनिर्देशन शीट/विश्लेषण प्रमाण-पत्र में उसका उल्लेख करने की संभावना है।
- ठ. चीन के केवल थोड़े से उत्पादक जिनका चीन जन.गण. से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कुल आयात में 6.46 प्रतिशत और विचाराधीन उत्पाद के आयात में 7.78 प्रतिशत हिस्सा है, ने दावा किया है कि वे 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम के पीवीसी का उत्पादन करते हैं।
- ड. यद्यपि तियानजिन एलजी बोहाई केमिकल कंपनी ने एक नमूना विश्लेषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्यात किया है, तथापि कोई नमूना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह हमेशा 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी का निर्यात

करते हैं। किसी भी तरह, निर्यातक ने मामूली मात्रा का निर्यात किया है जिससे भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात प्रभावित नहीं होंगे।

- ढ. जिनजियांग झोंगताई केमिकल कंपनी लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद (2 पीपीएम से अधिक) का उत्पादन करता है, ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है जबकि उसकी सहयोगी कंपनी जिसने मामूली मात्रा का निर्यात किया है, ने भाग लिया है।
- ण. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आवेदकों ने यह सिद्ध करने के लिए उनके पास तर्कसंगत ढंग से उपलब्ध सूचना प्रदान की है कि अनेक उत्पादकों ने 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्यात किया है और ऐसे आयातों में उछाल आया है।
- त. बल्क मास पोलिमराइजेशन, इमलसन पोलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए उत्पादित पीवीसी, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन नहीं हैं और इन्हें पूर्ववर्ती जांच में अलग उत्पाद माना गया था। बल्क मास पोलिमराइजेशन को बाहर रखने के संबंध में घरेलू ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने दिनांक 01.4.2016 के अपने आदेश द्वारा अग्रिम फैसले में यह निर्णय दिया था कि पीवीसी मास रेजिन पोलिमराइजेशन ग्रेड पर दिनांक 13.06.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा पीवीसी-एसआर पर लागू पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा जो अधिसूचना सं. 14/1012/2012-डीजीएडी दिनांक 04.04.2014 के माध्यम से जारी निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर आधारित है।

ड.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

12. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (आरवीसीएम) वाला पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन रेजिन”

याचिकाकर्ताओं ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है –(क) 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन और (ख) 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन। याचिकाकर्ताओं ने बीआईएस मानकों का हवाला देते हुए अवशिष्ट वीसीएम मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को न्यायोचित ठहराया है। बीआईएस मानक आईएस 1765 8:2021 में निम्नानुसार उल्लेख है:

“पीवीसी-एसआर और पीवीसी-पीआर की आरवीसीएम मात्रा 2 पीपीएम से अधिक नहीं होगी, तथापि पीवीसी-एसआर की आरवीसीएम मात्रा मास/बल्क पोलिमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा निर्माण के समय 5 पीपीएम से अधिक नहीं होगी। आरवीसीएम मात्रा का परीक्षण आईएस 10151/आईएसओ 24538 के अनुसार किया जाएगा”।

बल्क मास पोलिमराइजेशन, इमलसन पोलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित प्रकार के पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं:

क. 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन

ख. क्रॉस-लिंक पोली विनाइल क्लोराइड

ग. क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी)

घ. विनाइल क्लोराइड विनाइल एसिटेड कोपोलिमर (वीसी-वीएसी)

ड. पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन

च. पोली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन”

13. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया है – (क) 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन और (ख) 2 पीपीएम से कम

अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन। जांच की शुरुआत के समय प्राधिकृत अधिकारी ने 2 पीपीएम से कम और 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात के रुझानों की अलग-अलग जांच की थी। प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया कि 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों में कोई अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि नहीं हुई थी। अतः यह नोट किया गया था कि 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात प्रथमदृष्टया रक्षोपाय जांच की शुरुआत और तत्पश्चात नियमावली के अन्तर्गत उपाय लागू करने की आवश्यक अपेक्षाओं को प्रथमदृष्टया पूरा नहीं करते हैं। अतः, प्राधिकृत अधिकारी ने 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया।

14. दूसरी ओर, प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया कि 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात पर्याप्त हाल के, पर्याप्त अचानक, काफी तीव्र और इतने अधिक¹ थे कि वर्तमान जांच की शुरुआत आवश्यक हो गई। अतः 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों में अचानक, तीव्र और भारी उछाल की मौजूदगी से स्वयं को प्रथमदृष्टया संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी ने केवल 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के संबंध में नियमावली के नियम 5 के अनुपालन में वर्तमान जांच की शुरुआत की है।

ड.3.1 विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए विधिक मानक

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय करार, विदेश व्यापार विकास अधिनियम और रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली उस रीति के संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं करती है जिसके तहत किसी जांच में “विचाराधीन उत्पाद” को परिभाषित किया जाए। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क में केवल “किसी वस्तु” का उल्लेख है जिसका बढ़ी हुई मात्रा में भारत में आयात हुआ है। इसी प्रकार रक्षोपाय करार केवल “किसी उत्पाद” का उल्लेख करता है और यह निर्धारित करता है कि रक्षोपाय स्रोत पर विचार किए बिना “आयातित किए जा रहे उत्पाद” पर लागू होने चाहिए।² डोमिनिकन गणराज्य- रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ विवाद³ में जांचकर्ता प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को पोलिप्रोपिलीन बैग (अंतिम उत्पाद) और पोलिप्रोपिलीन ट्युबलर फैब्रिक (पोलिप्रोपिलीन बैगों के लिए निविष्टि उत्पाद) के रूप में परिभाषित किया था। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में दो अलग-अलग उत्पाद खंड शामिल किए गए थे, तथापि पैनल ने माना था कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में कोई अनियमितता नहीं है क्योंकि “रक्षोपाय करार” में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस “उत्पाद”⁴ के चयन, वर्णन विश्लेषण या निर्धारण को शासित करते हों और “रक्षोपाय करार में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा या दायरे के संबंध में कोई विशिष्ट दायित्व लागू नहीं किए गए हैं।”⁵
16. डोमिनिकन गणराज्य – रक्षोपाय में पैनल के अवलोकनों को स्टील (तुर्की),⁶ संबंधी ईयू – रक्षोपाय में पैनल द्वारा दोहराया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ ने एक जांच के ज़रिए विभिन्न श्रेणी के उत्पाद की रेंज पर रक्षोपाय लागू किए थे। इस विवाद में पैनल ने नोट किया कि यूरोपीय आयोग द्वारा अपनाए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे की व्यापक परिभाषा में कोई विसंगति नहीं है। पैनल का अवलोकन था:

7.34. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस खंड में विचार किए गए प्रावधान में विचाराधीन उत्पाद के चयन को स्वयं निर्धारित करने के लिए किसी अनुशासन का प्रावधान नहीं करते हैं। ये प्रावधान विचाराधीन उत्पाद के चयन के लिए नियम निर्धारित नहीं करते हैं और उदाहरण के लिए ये किसी सदस्य को किसी एक जांच में अनेक उत्पादों को शामिल करने से नहीं रोकते हैं। इस प्रकार हम डोमिनिकन गणराज्य – रक्षोपाय मामले में पैनल की

¹ पैराग्राफ देखें 131, अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अर्जेन्टीना फुटबियर के आयातों पर रक्षोपाय –, डब्ल्यूटी/डीएस121/एबीआर/, 12 जनवरी, 2000 को स्वीकृत, (एतदपश्चात अर्जेन्टीना फुटबियर (ईसी))। अपीलीय निकाय ने यह अवलोकन किया कि रक्षोपाय लगाने की पूर्वापेक्षा यह है कि आयातों में – वृद्धि “पर्याप्त हाल की, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त अधिक” होनी चाहिए।

² पैराग्राफ 7.177, पैनल रिपोर्ट, डोमिनिकन गणराज्य – पोलिप्रोपिलीन बैग और ट्युबलर फैब्रिक के आयातों पर रक्षोपाय, डब्ल्यूटी/डीएस415/आर, डब्ल्यूटी/डीएस416/आर, डब्ल्यूटी/डीएस417/आर, डब्ल्यूटी/डीएस418/आर, और एडीडी.1, 22 फरवरी, 2012 को स्वीकृत (एतदपश्चात “डोमिनिकन गणराज्य – रक्षोपाय”)

³ तदैव,

⁴ तदैव, पैराग्राफ 7.177

⁵ तदैव, , पैराग्राफ 7.181

⁶ पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय संघ – कतिपय स्टील उत्पादों पर रक्षोपाय, डब्ल्यूटी/डीएस595/आर और एडीडी.1, 31 मई, 2022 को स्वीकृत (एतदपश्चात) “ईयू(तुर्की) स्टील पर रक्षोपाय -”।

इस बात से सहमत हैं कि यद्यपि रक्षोपाय संबंधी करार में प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद परिभाषित करना अपेक्षित है, तथापि इसमें “समान अथवा एक दूसरे से सीधे प्रतिस्पर्धा करने वाले केवल उन उत्पादों” संबंधी विचाराधीन उत्पाद को प्रतिबंधित करने जैसी अपेक्षाएं निर्धारित नहीं हैं।

17. डब्ल्यूटीओ की उक्त रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के पास विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने का विवेकाधिकार है, और रक्षोपाय करार प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए विचाराधीन उत्पाद के चयन को अनुशासित नहीं करता है। उक्त दो डब्ल्यूटीओ विवादों में पैनल ने यह माना था कि रक्षोपाय करार विचाराधीन उत्पाद की व्यापक परिभाषा अपनाने को प्रतिबंधित नहीं करता है। अतः, इसके तार्किक विस्तार में प्राधिकृत अधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की कोई सीमित परिभाषा अपनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
18. उक्त निर्णयों और विधान के मद्देनजर प्राधिकारी अधिकारी के पास पीयूसी को परिभाषित करने में विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आरवीसीएम मात्रा वर्गीकरण एक मापदंड है क्योंकि अन्य देशों के विनिर्देशनों सहित भारत में बीआईएस मानक इस मापदंड के आधार पर अंतर करते हैं। रक्षोपायों का उद्देश्य आयातों में ऐसे उद्घाल पर रोक लगाना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। वर्तमान जांच के तथ्यों में प्राधिकृत अधिकारी ने आरवीसीएम मात्रा के आधार पर उत्पाद में अंतर किया है और 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में पीयूसी को परिभाषित किया है क्योंकि केवल श्रेणी के आयातों में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि देखी गई थी। अतः, यह तर्क कि पीयूसी से 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को बाहर नहीं रखा जा सकता, स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
19. प्राधिकारी मानते हैं कि 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को शामिल करने से भारतीय उद्योग के उस वर्ग को अनावश्यक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा जिसे आयातों में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि के कारण गंभीर क्षति नहीं हो रही है। अतः, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन तक पीयूसी को सीमित करके विचाराधीन उत्पाद के एक संकीर्ण दायरे को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि ऐसे किसी वर्ग को कोई अत्यधिक संरक्षण प्राप्त न हो जो जांच के दायरे से बाहर है।

ई.3.2. रक्षोपाय करार के अन्तर्गत “समान और सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद ” और रक्षोपाय (क्यूआर) नियमावली 2012 के अन्तर्गत “समान वस्तु”

20. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी अब घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जांच की दिशा में कार्यवाही करते हैं और क्या उन्हें वर्तमान जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन पीयूसी के बाहर हैं, जबकि घरेलू उद्योग 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का विनिर्माण करता है, जबकि 2 पीपीएम से अधिक का नहीं करता है।
21. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार, रक्षोपाय जांच में ‘घरेलू उद्योग’ को विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक होना जरूरी नहीं है बल्कि वह ‘समान और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद,’ का उत्पादक हो सकता है। रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 का पाठ निम्नानुसार है:

कोई सदस्य किसी उत्पाद के लिए रक्षोपाय का आवेदन केवल तभी कर सकता है यदि उस सदस्य ने नीचे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार यह निर्धारित किया हो कि ऐसे उत्पाद को ऐसी समग्र या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष बढ़ी हुई मात्राओं में उसके क्षेत्र में और ऐसी दशाओं में आयात किया जा रहा है जिससे समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या गंभीर क्षति का खतरा है।

22. उक्त प्रावधान में आयातित वस्तु (अर्थात् विचाराधीन उत्पाद) का उल्लेख करते समय ‘ऐसे उत्पाद’ शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का उल्लेख करते हुए ‘समान और सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद’ का प्रयोग किया गया है दूसरे शब्दों में उत्पादों पर रक्षोपाय⁷ तब लगाया जा सकता है जबकि ऐसे उत्पाद के आयातों में वृद्धि से ‘समान और सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद’ का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो। यूएस-

⁷ पैनल रिपोर्ट, संयुक्त राज्य – बड़े आवासीय वाशरों के आयातों पर रक्षोपाय, डब्ल्यूटी/डीएस546/आर और एडीडी1, 28 अप्रैल, 2023 को स्वीकृत एतद्पश्चात्(“यूएसवाशर पर रक्षोपाय-”)

वाशर पर रक्षोपाय के विवाद में यह समुक्ति की है कि 'विचाराधीन उत्पाद' और 'समान और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद' के बीच समानता नहीं होनी चाहिए। रक्षोपाय करार में यह अधिदेशित नहीं है कि घरेलू उद्योग को केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक होना चाहिए बल्कि इसमें वे उत्पादक भी शामिल हो सकते हैं जो 'समान और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादन' कर रहे हों:

हम कोरिया से सहमत हैं कि घरेलू उद्योग की परिभाषा किसी जांचकर्ता प्राधिकारी के निर्धारण के बाद के स्तरों को प्रभावित करती है (जैसे गंभीर क्षति और कारण का निर्धारण)। तथापि रक्षोपाय संबंधी करार में अनुच्छेद 4.1(ग) में घरेलू उद्योग की एक विशिष्ट परिभाषा दी गई है और यह अपेक्षित है कि जांच के आगामी स्तर इस प्रावधान के अनुसार परिभाषित घरेलू उद्योग के आधार पर चलाए जाएं। न तो अनुच्छेद 4.1(ग) और न ही रक्षोपाय करार का कोई प्रावधान (जांच की आगामी कार्यवाही को शासित करने वाले प्रावधानों सहित जैसे अनुच्छेद 4.2(ख) और 4.2(ग)) पीयूसी और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु के बीच 'असमानताएं' के रूप में कोरिया द्वारा वर्णित मान्यता पर कोई अतिरिक्त अपेक्षा नहीं लगाते हैं। अनुच्छेद 4.1(ग) में अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग को उस वस्तु के उत्पादकों के आधार पर परिभाषित किया जाए जो पीयूसी के 'समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी' हो। समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की सीमा तक पीयूसी और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु के बीच 'समानता' के लिए अनुच्छेद 4.1(ग) के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है। वास्तव में, कोरिया के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि जांचकर्ता प्राधिकारी को समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के उत्पादकों को घरेलू उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना होगा जबकि समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद पीयूसी में शामिल वस्तुओं के अनिवार्य रूप से समान नहीं होते हैं (या कोरिया के शब्दों में कहें तो 'बराबरी' के नहीं होते) यह बात अनुच्छेद 4.1(ग) के पाठ के विपरीत है। हम मानते हैं कि यदि अनुच्छेद 4.1(ग) का उद्देश्य समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के आधार पर और न कि 'समानता' के आधार पर नहीं, घरेलू उद्योग को परिभाषित करने से जांचकर्ता प्राधिकारियों को रोकता है तो यह प्रावधान अलग ढंग से बनाया गया होता।”⁸

23. उक्त कानूनी प्रावधान को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(4) में भी मान्यता दी गई है, जिसमें घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“घरेलू उद्योग” से वस्तुओं के उत्पादक (कृषि वस्तुओं के उत्पादक सहित) अभिप्रेत हैं

- (i) भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु समग्र रूप से; या
- (ii) भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु जिनका समग्र उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो;

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय करार के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(4) के अनुसार, घरेलू उद्योग को भारत में 'समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु' का उत्पादक होना चाहिए (या तो उत्पादन का संपूर्ण या प्रमुख हिस्सा) विचाराधीन उत्पाद 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम मात्रा वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम मात्रा वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन है।

ड.3.3 घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्थापनीय है

25. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण करना कि क्या उत्पाद समान है, उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धी संबंध की प्रकृति और मात्रा का आधारभूत निर्धारण है।⁹ घरेलू उद्योग ने बताया है कि संबद्ध वस्तु का आमतौर पर पाइप और फिटिंग, फ्लैक्सीबल होस, फिल्म/शीट, बॉटल, प्रोफाइल, वायर और केबल, फुटवियर आदि जैसे विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग होता है। 2 पीपीएम से कम और अधिक अवशिष्ट बीसीएम वाले पीवीसी का विभिन्न वर्गों में उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। भारतीय उद्योग ऐसे किसी वर्ग को नहीं जानता है जो 2 पीपीएम से कम और अधिक अवशिष्ट बीसीएम वाले पीवीसी का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं करता है। इसी प्रकार, चीन जन.गण. से निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में भी उल्लेख है कि चीन जन.गण. द्वारा उत्पादित

⁸ तदैव, पैराग्राफ 7.51

⁹ पैराल रिपोर्ट, यूएस-वाशर संबंधी रक्षोपाय, पैराग्राफ 7.55.

संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है (2 पीपीएम से अधिक) और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और अन्य देशों से निर्यातित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2 पीपीएम से कम) में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. तथा अन्य देशों से आयातित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन आदि की दृष्टि से तुलनीय हैं। अवशिष्ट वीसीएम के 2 पीपीएम से कम और अवशिष्ट वीसीएम मात्रा के 2 पीपीएम से अधिक वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

26. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य पर सहमत हैं कि 2 पीपीएम से कम और 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और विभिन्न देशों से आपूर्ति किए गए 2 पीपीएम तक के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अवशिष्ट वीसीएम मात्रा में अंतर के बावजूद विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित और विभिन्न देशों से आपूर्ति किए गए 2 पीपीएम तक के रेजिन और 2 पीपीएम से अधिक रेजिन का समान प्रयोजनार्थ समान रूप से प्रयोग होता है और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर खपत होती है। आरवीसीएम मात्रा को छोड़कर 2 पीपीएम तक के रेजिन और 2 पीपीएम से अधिक के रेजिन के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद श्रेणियां भौतिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं।
27. यद्यपि 2 पीपीएम से कम और 2 पीपीएम से अधिक के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का एक दूसरे के स्थान पर और समान उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है, तथापि वर्तमान वृद्धि अवधि के दौरान दोनों उत्पादों के कीमत व्यवहार में अंतर था जिसकी वजह से केवल 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों में वृद्धि हुई। इस पर विचार करते हुए कि 2 पीपीएम तक और उससे अधिक आरवीसीएम वाले रेजिन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और कर रहे हैं, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत में आयातित 2 पीपीएम तक आरवीसीएम वाले रेजिन नियमावली के नियम 2 (ड.) के अनुसार भारत में आयात किए जा रहे 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के 'समान वस्तु' (और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी) हैं।
28. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) ने बताया कि चूंकि 2 पीपीएम से कम और 2 पीपीएम से अधिक के उत्पाद समान वस्तु हैं, इसलिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के लिए अवशिष्ट वीसीएम के किसी विभाजन के बिना समग्र रूप से आर्थिक विश्लेषण किया जाए। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में उछाल केवल 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के मामले में पाया गया है। अतः, प्राधिकृत अधिकारी ने 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से बाहर रखा है। प्राधिकृत अधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की जांच की है। जहां आवश्यक हो, प्राधिकृत अधिकारी ने 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात रुझानों और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव की भी जांच की है।

ई.3.4. निर्यातकों द्वारा सूचित आरवीसीएम मात्रा से संबंधित दावे

29. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि आरवीसीएम मात्रा को राष्ट्रीय मानको के बजाए विश्लेषण प्रमाण-पत्र के आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न देशों में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के लिए आरवीसीएम मात्रा के अलग अलग मानक विहित किए हैं। तथापि, उत्पादकों ने अपने आंतरिक मानकों और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी उत्पादन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव किया है। यह नोट किया गया है कि चीन सरकार ने 5 पीपीएम से कम आरवीसीएम को संगत मानक के रूप में अधिसूचित किया है। तथापि, यह नोट किया जाए कि यह मानक अनिवार्य नहीं है। यद्यपि चीन के कुछ उत्पादकों ने अपने उत्पाद को 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले रेजिन के रूप में अधिसूचित किया है, तथापि कुछ ने 5 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले रेजिन के रूप में अधिसूचित किया है। कोई उत्पादक अपने लिए उचित विनिर्देशन (सरकारी द्वारा विहित अनिवार्य रेंज के भीतर) को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।

30. प्राधिकृत अधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या विश्लेषण प्रमाण-पत्र को 2 श्रेणियों में उत्पादों के आयात को अलग करने के लिए क्षति अवधि के दौरान सूचित आयातों में आरबीसीएम मात्रा निर्धारित करने के लिए संगत दस्तावेज के रूप में अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने दिनांक 16.09.2022 की अधिसूचना द्वारा जांच की शुरुआत की थी। विभिन्न देशों में सभी संबंधित निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर देना अपेक्षित था और उनके इस दावे कि क्या वे 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्यात कर रहे हैं या अन्यथा के समर्थन में दस्तावेज देना अपेक्षित था। तथापि, चीन के केवल कुछ निर्यातकों ने अपने उत्तर दिए हैं।
31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत विनिर्देशन शीटों में उत्पाद के विभिन्न संगत तकनीकी मापदंडों संबंधी संगत सूचना है, जैसी उत्पादक द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई है। विनिर्देशन शीट एक ऐसा दस्तावेज होता है, उत्पादक द्वारा आमतौर पर जिसका प्रयोग बाजार में उत्पाद के उत्पादन और बिक्री हेतु उत्पाद के विनिर्देशनों को भावी ग्राहकों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता विनिर्देशन शीट में उत्पादकों द्वारा प्रकाशित विनिर्देशनों के आधार पर सामग्री खरीदते हैं जबकि विश्लेषण प्रमाण पत्र केवल उस उत्पाद का प्रदर्शन मात्र होता है जिसकी वास्तव में आपूर्ति की गई है। उपभोक्ता उत्पाद के घोषित या अधिसूचित विनिर्देशनों के आधार पर ऑर्डर देते हैं और कीमत संबंधी बातचीत करते हैं। विनिर्देशन शीट के साथ विश्लेषण प्रमाण-पत्र का मिलान नहीं होने पर क्रेता, उत्पादक से खरीदी गई सामग्री को अस्वीकार कर सकता है। तथापि, कोई क्रेता सामग्री की प्राप्ति को अस्वीकृत नहीं कर सकता, यदि विनिर्देशन शीट के अनुपालन में विशेषताएं हों। कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 5 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों की विशेषता बताने वाली विनिर्देशन शीटों का आवश्यक अर्थ यह नहीं है कि वे आयात आवश्यक रूप से 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम की पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के थे।
32. प्राधिकृत अधिकारी को मामले के रिकॉर्ड पर तथ्यों के आधार पर अपना निर्धारण करना आवश्यक है। जबकि कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि 5 पीपीएम से कम का मतलब 2 पीपीएम से अधिक नहीं है। जिन निर्यातकों ने 5 पीपीएम से कम आरबीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में अपने निर्यात की सूचना दी थी, उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने का अवसर दिया गया था कि उनके निर्यातक वास्तव में 2 पीपीएम तक आरबीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन थे। प्राधिकृत अधिकारी ने जहां भी प्रदान किया गया है, इस साक्ष्य को स्वीकार किया है।

ड.3.5 बल्क मास पोलिमराइजेशन के ज़रिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन के अपवर्जन संबंधी दावे

33. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पीयूसी का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है और बल्क मास पोलिमराइजेशन, इमल्सन पोलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के ज़रिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन को प्रौद्योगिकी के आधार पर बाहर रखना किसी उत्पाद को बाहर करने का कारण नहीं हो सकता है, जैसा पहले जांच में माना गया है।
34. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि शुरुआती अधिसूचना में पीयूसी की परिभाषा के अनुसार, मास/बल्क सस्पेंशन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था। जांच की शुरुआत के बाद, उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच की शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के आधार पर सूचना प्रदान की है। हालांकि, इस स्तर तक किसी भी पक्ष ने पीयूसी से बड़े पैमाने पर/बल्क पोलिमराइजेशन पीवीसी को बाहर करने का विरोध नहीं किया। यह केवल बाद की अवस्था में था कि हितबद्ध पक्षकार ने यह निवेदन किया है कि उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के आधार पर विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन इच्छुक पार्टियों ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन एक ही उत्पाद विशेषताओं के साथ एक ही है।
35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को नीचे दी गई शुरुआती अधिसूचना में ठीक से परिभाषित किया गया है:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “2 पीपीएम से अधिक अपशिष्ट विनाइल क्लोराइड मोनोमर (आरबीसीएम) वाला पोलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन रेजिन”

याचिकाकर्ताओं ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है—(क) 2 पीपीएम से अधिक अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन और (ख) 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन। याचिकाकर्ताओं ने बीआईएस मानकों का हवाला देते हुए अवशिष्ट वीसीएम मात्रा के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को न्यायोचित ठहराया है। बीआईएस मानक आईएस 1765 8:2021 में निम्नानुसार उल्लेख है:

“पीवीसी-एसआर और पीवीसी-पीआर की आरवीसीएम मात्रा 2 पीपीएम से अधिक नहीं होगी, तथापि पीवीसी-एससआर की आरवीसीएम मात्रा मास/बल्क पोलिमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा निर्माण के समय 5 पीपीएम से अधिक नहीं होगी। आरवीसीएम मात्रा का परीक्षण आईएस 10151/आईएसओ 24538 के अनुसार किया जाएगा”।

बल्क मास पोलिमराइजेशन, इमल्सन पोलिमराइजेशन और माइक्रो सस्पेंशन पोलिमराइजेशन प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित पीवीसी रेजिन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। निम्नलिखित प्रकार के पीवीसी रेजिन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं:

क. 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन

ख. क्रॉस-लिंक पोली विनाइल क्लोराइड

ग. क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी)

घ. विनाइल क्लोराइड विनाइल एसिटेड कोपोलिमर (वीसी-वीएसी)

ड. पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन

च. पोली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेजिन”

36. यद्यपि 2 पीपीएम से अधिक अपशिष्ट आरवीसीएम वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद है, तथापि 2 पीपीएम से कम अवशिष्ट वीसीएम वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन नियमावली के नियम 2(ड.) के अनुसार ‘समान वस्तु’ है और रक्षोपाय करार के अनुसार ‘समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद’ हैं।
37. प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया है कि कुछ सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात डेटा और डीजी सिस्टम्स डेटा के बीच एक बेमेल प्रतीत होता है। प्राधिकृत अधिकारी ने ईमेल दिनांक 28 अप्रैल 2023 के माध्यम से, इच्छुक पार्टियों को डेटा में बेमेल होने का कारण बताने और उनके डेटा को डीजी सिस्टम्स डेटा के साथ सहसंबंधित करने का अवसर प्रदान किया। उत्पादकों/निर्यातकों ने दिनांक 2 मई 2023 के उत्तर में कहा कि जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने केवल एक एचएस कोड पर विचार किया है, निर्यात चार एचएस कोडों अर्थात् 39041090, 39042110, 39042190 और 39042200 के तहत किए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी को चार एचएस कोड के तहत 2 मई 2023 की देर से आपूर्ति की गई थी, यानी लगभग जांच के अंतिम चरण में। हालांकि, उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों के पास इस अवधि से पहले पर्याप्त अवसर था क्योंकि शुरूआती अधिसूचना में एकल एचएस कोड का उल्लेख था, इच्छुक पार्टियों को आपूर्ति की गई याचिका के एनसीवी में एकल एचएस कोड का उल्लेख था। यहां तक कि न तो मौखिक सुनवाई में, न ही लिखित निवेदन या प्रत्युत्तर के माध्यम से, इस मुद्दे को कभी उठाया गया था। इसलिए, समयबद्ध जांच होने के कारण, प्राधिकृत अधिकारी जांच के इतने विलंबित चरण में इस तरह के दावे पर विचार नहीं करने के लिए विवश है। यह भी नोट किया जाता है कि उपरोक्त विवाद को उठाने वाली पार्टी ने पहले अपनी प्रतिक्रिया में दायर किया था कि वह केवल 2पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन पेस्ट राल का निर्यात कर रही है, हालांकि, बाद में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से, पार्टी ने दावा किया कि निदेशालय के पास दायर डेटा पीयूसी और लाइक आर्टिकल दोनों के बारे में जानकारी शामिल है। यह स्व-विरोधाभासी है और इसे देखते हुए इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत दावे/तर्क अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं।
38. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि इन उत्पादकों/निर्यातकों ने यह भी कहा है कि उन्होंने आरवीसीएम सामग्री से इतर पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के सभी लेन-देन की सूचना दी है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि निर्यातक ने पहले दावा किया था कि वह केवल 2 पीपीएम से नीचे के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन और निर्यात करता है जो स्वतः विरोधाभासी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और कुछ उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा

में बेमेल होने के कारण, और बेमेल के कारणों के संबंध में किसी भी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, प्राधिकृत अधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के अनुसार आयात डेटा पर विचार किया है।

च. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. जांच अवधि के दौरान आवेदकों के पास भारतीय उत्पादन में केवल 25-30 प्रतिशत हिस्सा है और क्षति अवधि के दौरान यह और भी कम है, जिससे यह संदेह होता है कि ऐसे उत्पादकों द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए इन आंकड़ों से छेड़छाड़ हो सकती है।
- ख. यह विचार किया जाए कि यद्यपि प्रमुख हिस्सा अन्य भारतीय उत्पादकों के पास है, तथापि, वे प्राधिकारी के समक्ष क्षति का दावा नहीं कर रहे हैं।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. घरेलू और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. रक्षोपाय लागू करने की याचिका केमप्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी जिनके पास भारत में घरेलू उत्पादन का [27] प्रतिशत हिस्सा है। चूंकि आवेदकों के उत्पादन का घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है, इसलिए वे घरेलू उद्योग हैं।
- ख. सभी अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् डीसीएम श्रीराम, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समर्थन पत्र प्रस्तुत किए हैं।
- ग. उपाय लागू करने का समर्थन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी किया है।
- घ. चूंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के कोई उत्पादक नहीं हैं, इसलिए केवल 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना जा सकता है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आवेदकों ने भारत में सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा समान वस्तु के उत्पादन से संबंधित वास्तविक सूचना प्रस्तुत की है। ऐसी सूचना घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने समर्थन पत्र में दी गई है।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत आवेदक किसी अन्य घरेलू उत्पादक को जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।
- छ. अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी के लिए केवल परिभाषित घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करना अपेक्षित है।

च.3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

- 41. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय करार, एफटी(डीआर) अधिनियम और रक्षोपाय (क्यूआर) नियमावली के अन्तर्गत 'स्थिति परीक्षण' का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, रक्षोपाय करार और एफटी(डीआर) अधिनियम में घरेलू उद्योग को समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादकों या ऐसे उत्पादकों जिनका समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का संचयी उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।¹⁰
- 42. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क4(ख) के अनुसार –
“(ख) घरेलू उद्योग से वस्तुओं के उत्पादक अभिप्रेत हैं (कृषि वस्तुओं के उत्पादकों सहित) –

¹⁰ अनुच्छेद 4.1(ग), रक्षोपाय करार और धारा 9क4(ख), विदेश व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम)।

(i) भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु समग्र रूप से; या

(ii) भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु जिनका समग्र उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो;

43. इसी प्रकार, रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(ग) के अनुसार घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “किसी सदस्य के क्षेत्र के भीतर प्रचालनरत समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद के उत्पादक समग्र रूप से या ऐसे उत्पादक जिनका समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद का संचयी उत्पादन उस उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो” ।

च.3.1. ‘घरेलू उद्योग’ की परिभाषा के लिए विधिक मानक

44. प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि यूएस-वाशर्स पर रक्षोपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह समुक्ति की थी कि घरेलू उद्योग या तो समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादों के समग्र रूप से उत्पादक या (ख) ऐसे उत्पादक जिनका समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद का संचयी उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन के ‘प्रमुख हिस्से’ के अर्थ के भीतर कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो।¹¹

च.3.2 वर्तमान जांच में कुल घरेलू उत्पादन का ‘प्रमुख हिस्सा’

45. वर्तमान आवेदन केमप्लास्ट कुडालोर विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदकों के अलावा भारत में तीन अन्य घरेलू उत्पादक हैं अर्थात् डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अन्य घरेलू उत्पादकों तथा घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन अर्थात् केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भारत में 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम वाले पीवीसी के आयातों पर रक्षोपाय लगाने के अनुरोध का समर्थन किया है। अतः आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन भारत में समान उत्पाद के 100 प्रतिशत उत्पादकों द्वारा समर्थित है। जांच की शुरुआत के समय प्राधिकारी ने नोट किया कि आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वे घरेलू उद्योग हैं।
46. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा अन्य उत्पादकों के पास है जो प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष नहीं है। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उनका कुल उत्पादन भारत में समान वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पाद का [***] है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकों के अलावा, ‘समान वस्तुओं’ के तीन अन्य घरेलू उत्पादक हैं, जिन्होंने याचिका का समर्थन किया है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं का भारत में ‘समान वस्तुओं’ के कुल 5 उत्पादकों में से [***] से अधिक उत्पादन है, इसलिए उनका उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में समान वस्तु (जैसे सामान)। इसके अलावा, आवेदन समान वस्तु (जैसे सामान) के अन्य सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा समर्थित है। आवेदन के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% समर्थन है, और इसलिए स्थायी परीक्षण को पूरा करता है।
47. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत की सूचना जारी की और सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच में भाग लेने और संगत सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी। रिकॉर्ड में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता का हिस्सा नहीं बनने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों के निष्पादन में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन के मुकाबले कोई खास अंतर रहा हो। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों को शामिल नहीं करने से क्षति के दावे में कोई वास्तविक विकृति आई है।
48. पूर्वोक्त के मद्देनजर और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता उक्त नियमावली के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

छ. गोपनीयता

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

¹¹ पैनल रिपोर्ट यूएस-वाशर्स पर रक्षोपाय, पैरा 7.75

49. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने याचिका के अगोपनीय अंश में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की बिल्कुल हाल की अवधि के लिए विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसकी वजह से हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने में असमर्थ हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

ग. आवेदक ने बिल्कुल हाल के आंकड़ों के साथ आवेदन के अगोपनीय अंश को प्रदान और परिचालित किया है।

छ.3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

51. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकृत अधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। नियमावली के नियम 6(7) के मद्देनजर सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों के अगोपनीय अंश को जांच में भाग लेने वाले अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने की सलाह दी गई थी।

52. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने बिल्कुल हाल की अवधि के लिए विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में आंकड़े नहीं दिए हैं। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 27 अक्टूबर, 2022 को अपने आर्थिक मापदंडों संबंधी आंकड़ों का अगोपनीय अंश परिचालित किया है। इन हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी देने का अवसर दिया गया था और इन टिप्पणियों पर वर्तमान निर्धारण में उचित ढंग से विचार किया गया था।

ज. विविध अनुरोध

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. विभिन्न मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. जांच की शुरुआत उचित नहीं है क्योंकि आवेदकों ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं और प्राधिकारी द्वारा अधूरी जांच की गई है।

ख. ओपीपीआई के लगभग 30 प्रतिशत सदस्य एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं, और उनके लिए अलग से भागीदारी करना मुश्किल है। भारत में पोलिमर की लगभग 45 प्रतिशत प्रोसेसिंग ओपीपीआई के सदस्यों द्वारा की जाती है।

ग. एआईपीएमए के 90 प्रतिशत सदस्य एमएसएमई क्षेत्र के हैं और वह प्रयोक्ताओं और आयातकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

घ. फ्लैक्सकाउंसिल चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातकों और अंतिम प्रयोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एसोसिएशन है और इस प्रकार, वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार है।

ड. सीसीएआईए जांच में भागीदारी करने में इच्छुक चीन के 11 उत्पादकों द्वारा संपर्क करने पर भागीदारी कर रही है।

च. चीन जन.गण. से उत्पादक/निर्यातक मुख्यतः 2 पीपीएम से कम की वस्तु का निर्यात कर रहे हैं और उन्होंने विश्लेषण प्रमाण-पत्र सहित अपने उत्तर में इस संबंध में पूरी तकनीकी सूचना दी है।

- छ. चूंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई विशिष्ट एचएस कोड नहीं है, इसलिए एचएस कोड के सामने यह दर्शाने के लिए 'ईएक्स' शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि ऐसे एचएस कोड का केवल अंश ही वर्तमान रक्षोपाय जांच में शामिल है।
- ज. यदि उपायों की सिफारिश की जाती है तो वह पिछले तीन वर्षों में आयातों के औसत पर आधारित होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि का पर्याप्त प्रभाव होना चाहिए।
- झ. मेक्सिको, सऊदी अरब और थाईलैंड सहित विकासशील देशों को प्रस्तावित उपाय के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. विविध मुद्दों के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी मापदंड पर ध्यान नहीं दिलाया है जो जांच की शुरुआत के लिए अपर्याप्त हो। प्राधिकृत अधिकारी ने बड़े हुए आयातों, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद वर्तमान जांच शुरू की है।
- ख. ओपीपीआई को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इस एसोसिएशन ने वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए अपने सदस्यों से अनुमति नहीं ली है। प्राधिकृत अधिकारी को ओपीपीआई द्वारा प्रस्तुत बैठक के कार्यवृत्त की जांच करनी चाहिए। विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक ओपीपीआई का सदस्य भी है और यह नहीं मानता है कि ओपीपीआई के सदस्यों द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित किया गया था।
- ग. एआईपीएम ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उसे सदस्यों द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा वर्तमान जांच में भागीदारी के लिए प्राधिकृत किया गया है। यद्यपि उसने दावा किया है कि उसके 90 प्रतिशत सदस्य एमएसएमई हैं परंतु उसने ऐसे सदस्यों की संख्या स्पष्ट नहीं की है जो वास्तव में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ता हैं।
- घ. प्लेक्सकाउंसिल को वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसने केवल कुछ मुख्य कार्यकारियों के व्यापारिक हित को साधने के लिए एमओए के अनुसार, अपने निदेशों का उल्लंघन करते हुए भागीदारी की है। प्लेक्सकाउंसिल का उद्देश्य भारत से निर्यात को बढ़ावा देना है और भारत में आयातों को प्रोत्साहित करना नहीं है। वर्तमान जांच में भागीदारी के लिए प्लेक्सकाउंसिल के सदस्यों द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है।
- ड. प्लेक्सकाउंसिल के सदस्य संबद्ध वस्तु के आयातक और व्यापारी नहीं हैं बल्कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के विनिर्माता और निर्यातक हैं। इस प्रकार, उसे वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।
- च. केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डीसीएम श्रीराम प्लेक्सकाउंसिल के सदस्य हैं और पुष्टि करते हैं कि वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए एसोसिएशन द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं हुआ था।
- छ. प्लेक्सकाउंसिल ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उसके सदस्य अपनी उत्पादन प्रक्रिया में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख निविष्ट के रूप में प्रयोग करते हैं।
- ज. सीसीआई ने अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत नहीं की है, यद्यपि चीन में 141 ज्ञात उत्पादक हैं, तथापि सीसीआई ने बताया है कि उसने केवल 11 उत्पादकों से संपर्क किया है। उसने वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए सदस्यों द्वारा पारित संकल्प प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए उसे हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए।
- झ. चूंकि कुछ भागीदार उत्पादकों ने दावा किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् 2पीपीएम से अधिक आरवीसीएम) का निर्यात नहीं करते हैं। तथापि, वे नियम 2(घ) के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं क्योंकि कानून में केवल विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों पर विचार करने की अनुमति है। इस प्रकार, अन्य पहलुओं संबंधी उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा सकता है। यही बात अन्य देशों की ऐसी सरकारों पर लागू

होती है जिन्होंने दावा किया है कि 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले किसी पीवीसी का वहां से निर्यात नहीं हुआ है।

- ज. चूंकि भागीदार निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे अपने प्रचालनों पर प्रस्तावित उपायों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव का दावा नहीं कर सकते हैं ताकि उन्हें जांच में हितबद्ध माना जा सके। यदि प्रचालनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे पक्षकार प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति लेकर भी भागीदारी कर सकते हैं।
- ट. यद्यपि अनेक एसोसिएशनों ने वर्तमान जांच में भागीदारी की है, तथापि उनमें से किसी ने भी यह सिद्ध नहीं किया है कि ऐसी भागीदारी को प्राधिकृत करते हुए कोई संकल्प पारित हुआ था या नियम 2(घ) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित उनके अधिकांश सदस्य विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक या आयातक हैं।
- ठ. आटोमोटिव टायर इम्पोर्टर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में न्यायाधिकरण ने माना था कि किसी एसोसिएशन को अपने को हितबद्ध पक्षकार सिद्ध करना होगा, चूंकि एसोसिएशनें यह दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं, इसलिए न्यायाधिकरण ने पाया कि उसे हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।
- ड. नियम 6(5) में प्रतिवादी एसोसिएशनों की भागीदारी की अनुमति नहीं है क्योंकि इसमें उल्लेख है कि औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता एसोसिएशनों को सुनवाई का अवसर तभी दिया जाएगा यदि उत्पाद को खुदरा स्तर पर बेचा गया है।
- ढ. भारत में एचएस कोड और उत्पाद वर्णन के संयुक्त पाठ के आधार पर कोई उपाय लागू किया जाता है, यदि कोई उत्पाद के दायरे के भीतर नहीं आता है और समान एचएस कोड के अधीन आयातित होता है तो वह स्वतः उपाय के दायरे से बाहर होता है।
- ण. सिफरिश किए जाने वाले कोटा पिछले तीन वर्षों के आयातों के औसत पर आधारित हों, परंतु उसने वृद्धि की अवधि अर्थात् 2021-22 की तिमाही 1 और बिल्कुल हाल की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए और मांग में वृद्धि पर विचार करना चाहिए।

ज.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

55. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि वर्तमान जांच शुरू नहीं करनी थी क्योंकि जांच शुरुआत के लिए कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच को विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और बड़े हुए आयातों, गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद शुरू किया गया था। आवेदन का अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। आवेदन में जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ समस्त संगत सूचना थी। जांच शुरुआत के बाद आवश्यक समझी गई सीमा तक समर्थक सूचना/साक्ष्य मांगे गए थे और वर्तमान निर्धारण में उन्हें अपनाया गया है।
56. आवेदकों ने बताया है कि एसोसिएशनों ने एसोसिएशनों से अनुमानित किसी प्रक्रिया (जैसे अपने सदस्यों से विचार लेना, वर्तमान जांच में भागीदारी के लिए सदस्यों के संकल्प दर्ज करने वाली बैठक के कार्यवृत्त और वर्तमान जांच के संबंध में उनके सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों) का पालन किए बिना वर्तमान जांच में भागीदारी की है। आवेदकों ने बताया है कि इन एसोसिएशन द्वारा व्यक्त विचारों पर कुछ चुनिंदा सदस्यों के विचारों के रूप में ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे उन एसोसिएशनों कुछ सदस्यों के विचार मानना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि यह मानते हुए कि ये एसोसिएशन सरकार में अच्छी तरह मान्यता प्राप्त हैं और विभिन्न मंचों के समक्ष भागीदारी करती हैं, यह प्रत्याशित है कि इन एसोसिएशनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जो उनके अधिकांश सदस्यों के विचार होंगे। अतः, प्राधिकृत अधिकारी ने इन एसोसिएशनों द्वारा व्यक्ति विचारों और चिंताओं का समाधान करना उचित समझा है।
57. आवेदकों ने प्लेक्सकाउंसिल की भागीदारी पर कड़ी आपत्ति की है। आवेदकों ने बताया है कि प्लेक्सकाउंसिल ने यह सिद्ध किए बना वर्तमान जांच में भागीदारी की है कि क्या उनके अधिकांश सदस्यों ने प्रस्तावित उपायों का विरोध करने की इच्छा प्रकट की थी, उनके सदस्य जहां तक भारत से निर्यातों का संबंध है, कैसे बुरी तरह प्रभावित

होंगे। आवेदकों ने यह तर्क भी दिया है कि प्लेक्सकाउंसिल में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उत्पाद के उपभोक्ता के रूप में अपने व्यापारिक हैं और इसलिए उन्होंने प्रस्तावित उपायों का विरोध करने के लिए उपलब्ध एसोसिएशन के मंच का प्रयोग किया है जो सदस्यों के अनुसार अनुचित है और इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्लेक्सकाउंसिल भारत से प्लास्टिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए गठित एक एसोसिएशन है। नियम 2(घ) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकार ने कोई निर्यातक या कोई विदेशी उत्पादक, निर्यातक देश की सरकार, भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक और कोई व्यापार या व्यवसाय एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद का उत्पादन या व्यापार करते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा उत्पाद के उपभोक्ताओं ने पहले ही अपनी एसोसिएशन अर्थात् आर्गेनेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर ऑफ इंडिया और दि आल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स का प्रतिनिधित्व किया है।

58. प्राधिकृत अधिकारी यह भी नोट करते हैं कि व्यापक दावे करने के अलावा प्लेक्सकाउंसिल ने भारत से निर्यातों पर प्रस्तावित उपायों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव दर्शाते हुए सूचना नहीं दी है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रस्तावित उपाय केवल 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम वाले रेजिन के संबंध में है और हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं तर्क दिया है कि 2 पीपीएम से कम और अधिक आरबीसीएम वाले रेजिन एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यदि अचानक वृद्धि की अवधि को अलग रखा जाए तो यह देखा गया है कि उत्पाद के लगभग 90 प्रतिशत आयात 2 पीपीएम तक के रेजिन के हैं। अतः, यदि उपाय लगाए जाते हैं तो उनसे प्लेक्सकाउंसिल के सदस्यों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, प्राधिकारी काउंसिल और अन्य एसोसिएशनों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों को नोट करते हैं और इन अनुरोधों पर न्याय के लिए आवश्यक विचार करने के बाद जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
59. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एचएस कोड के सामने यह दर्शाने के लिए “ईएक्स” शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि केवल एचएस कोड का अंश ही वर्तमान जांच में शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद विवरण और एचएस कोड पर विचार करने के बाद कोई उपाय लगाया जाएगा। यदि, कोई उत्पाद समान एचएस कोड के अन्तर्गत आयातित होता है जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आता है तो वह स्वतः लागू उपायों के दायरे से बाहर हो जाएगा। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के मद्देनजर और पर्याप्त सावधानी बरतते हुए प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि प्रस्तावित उपाय केवल 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन से संबंधित हैं। 2 पीपीएम तक आरबीसीएम वाले रेजिन प्रस्तावित उपायों के दायरे से बाहर हैं।
60. इस अनुरोध के संबंध में कि अधिकांश चीनी उत्पादक 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम के साथ संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं और अपने विक्षेपण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि 2 पीपीएम तक आरबीसीएम वाली संबद्ध वस्तुएं वर्तमान जांच की विषय वस्तु नहीं हैं और इस प्रकार 2 पीपीएम तक आरबीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी का उत्पादन/निर्यात करने वाले किसी भी उत्पादक को वर्तमान जांच में उपायों की उगाही से बाहर रखा जाएगा।
61. मात्रात्मक प्रतिबंधों के कोटा के बारे में प्राधिकृत अधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत खंड में इसका समाधान किया है।

झ. बड़ी हुई मात्रा में आयात

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. भारत में आयातों की मात्रा के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. केवल चीन से आयात में वृद्धि हुई है जबकि कुल आयातों में गिरावट आई है।
- ख. रक्षोपायों का प्रयोग केवल आपवादिक परिस्थिति में होता है और उनका उद्देश्य आयातों में समग्र वृद्धि को रोकना है। चूंकि केवल एक देश से आयात में वृद्धि हुई है जबकि समग्र आयातों में गिरावट आई है, इसलिए रक्षोपाय लगाने का मापदंड पूरा नहीं होता है।

- ग. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु के बड़े हुए आयातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है और जानबूझकर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की कहानी बनाई है।
- घ. आयातों में वृद्धि का दावा कल्पना पर आधारित है और वस्तुतः गलत है क्योंकि चीन के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना दर्शाती है कि उन्होंने 2 पीपीएम से अधिक की संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
- ड. पीवीसी सस्पेंशन के आयातों का विवरण आरवीसीएम मात्रा पर विचार किए बिना आवेदक ने प्रस्तुत किया है जिससे आयातों की मात्रा के लिए विचार किए गए उत्पाद के दायरे के बारे में अस्पष्टता हुई है।
- च. जापान और कोरिया से नौवहन में देरी के कारण तथा चीन से कम रास्ते के कारण चीन से आयातों में वृद्धि हुई है। यद्यपि चीन से उत्पाद लाने में 30 दिन लगते हैं परंतु जापान से इसमें 75 से 90 दिन ताईवान और कोरिया से 60-70 दिन लग रहे थे।
- छ. चूंकि आवेदकों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद केवल चीन में उत्पादित और वहां से निर्यातित है, इसलिए इंडोनेशिया से आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए।
- ज. दर्शाई गई वृद्धि केवल चीन जन.गण. से हुई है और इसलिए इंडोनेशिया से आयातों को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- झ. जांच अवधि के दौरान ताईवान से विचाराधीन उत्पाद के कोई निर्यात नहीं हुए थे और इसलिए ताईवान को बाहर रखा जाना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. भारत में आयातों की मात्रा के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु दोनों के लिए आयात आंकड़े दिए हैं। चूंकि दोनों उत्पाद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों, समान वस्तु और भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा समान वस्तु की बिक्री पर विचार करते हुए, मांग निर्धारित की गई है। तथापि, आयातों की मात्रा केवल विचाराधीन उत्पाद पर आधारित है।
- ख. इंडोनेशिया और ताईवान से आयातों को उत्पादक द्वारा यह सिद्ध करने पर बाहर रखा जाना चाहिए कि उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी रेजिन हैं, या उन देशों से आयात संबद्ध वस्तु के आयातों के 3 प्रतिशत से कम हैं।
- ग. भारत में आयातों में समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन के संबंध में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है।
- घ. उपाय लागू करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बिल्कुल हाल की अवधि में भारी वृद्धि हुई है। 2022-23 की पहली तिमाही में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात 2021-22 में कुल आयातों से अधिक हैं।
- ड. भारत में आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती तिमाहियों तथा पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिल्कुल हाल की अवधि में वृद्धि हुई है।
- च. विचाराधीन उत्पाद के आयात में भारत में कुल आयातों, भारत में खपत, घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों के कारण भारी वृद्धि हुई है।
- छ. बिल्कुल हाल की अवधि में समग्र रूप से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों में भी भारी वृद्धि हुई है।
- ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत विचाराधीन उत्पाद के आयात तथा पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के भारत में कुल आयातों में वृद्धि हुई है।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विरुद्ध केवल आयातों में वृद्धि रक्षोपास लगाने के लिए संगत है, और न कि उन देशों की संख्या जिनसे आयात में वृद्धि हुई है।

झ.3 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच

64. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधानों के अंतर्गत रक्षोपाय वहां लगाए जा सकते हैं, जहां किसी उत्पाद का आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा या ऐसी स्थिति में हो रहा हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने या गंभीर क्षति होने का खतरा हो। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार 'बढ़ी हुई मात्रा' में समग्र या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष रूप से आयातों में वृद्धि शामिल है।

झ.3.1 'बढ़ी हुई मात्रा का अर्थ'

65. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 धारा 9क(1) के अनुसार रक्षोपाय शुल्क को निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जा सकता है:

“(1) यदि केन्द्र सरकार उचित समझी गई जांच करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का ऐसी बढ़ी हुई मात्रा और ऐसी परिस्थितियों में भारत में आयात हुआ है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति या गंभीर क्षति होने का खतरा है, तो वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी वस्तु के आयात पर ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकती है जिन्हें वह उचित समझे”

66. इस प्रकार, आयातों में वृद्धि एफटी(डीआर) नियम और रक्षोपाय (क्यूआर) नियमावली के अंतर्गत रक्षोपाय लगाने के लिए मूल पूर्व शर्त है। इसके अलावा, रक्षोपाय लगाने के लिए यह निर्धारित करने हेतु कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात “ऐसी मात्रा में बढ़े हैं” नियमों में समग्र रूप से या घरेलू उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि का विश्लेषण करना अपेक्षित है। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली का नियम 2(ग) बढ़े हुए आयात को निम्नानुसार परिभाषित करता है।

“(ग) “बढ़ी हुई मात्रा” में समग्र रूप से अथवा घरेलू उत्पादन की दृष्टि से आयातों में वृद्धि शामिल है;”

67. रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 2.1 कोई रक्षोपाय लागू करने की अनुमति केवल तभी देता है यदि उत्पाद का आयात समग्र रूप से या सापेक्ष रूप से ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में होता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। आयात में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अर्जेन्टीना – फुटवियर (ईसी) मामले में, अपीलीय निकाय ने माना था कि आयात में वृद्धि हाल की, अचानक, तीव्र और पर्याप्त इतनी अधिक होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या उसका खतरा हो। संगत उद्धरण निम्नानुसार है:

“131.[]यह निर्धारण कि क्या “ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में” आयात की अपेक्षा पूरी हुई है, केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण से पूरी नहीं होगी दूसरे शब्दों में जांच के लिए केवल यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि इस वर्ष उत्पाद के आयात पिछले वर्ष – या पांच वर्ष पहले की तुलना में अधिक हैं। इसके अलावा, और बार-बार होने पर आयातों की मात्रा में केवल वृद्धि से बात नहीं बनेगी। “ऐसी बढ़ी हुई मात्राएं” अवश्य होनी चाहिए जिनसे रक्षोपाय लागू करने के लिए इस अपेक्षा को पूरा करने हेतु घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या उसका खतरा हो। और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) दोनों की भाषा में हम मानते हैं कि यह अपेक्षित है कि आयातों में वृद्धि “गंभीर क्षति” होने या उसका खतरा होने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से पर्याप्त हाल की, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त अधिक अवश्य होनी चाहिए।”

68. यूएस – व्हीट ग्लूटन संबंधी पैनल ने “ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में” वाक्य की व्याख्या निम्नानुसार की है:

“8.31 गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) और [रक्षोपाय करार (“एसए”) करार के] अनुच्छेद 2.1 में केवल आयातों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है बल्कि उसमें संबंधित उत्पाद के आयातों में ‘वृद्धि की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकृति के संबंध में विशिष्ट अपेक्षाएं दी गई हैं। गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) और एसए का अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षित है कि संबंधित सदस्य के क्षेत्र में किसी उत्पाद का आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा (समग्र या घरेलू उत्पाद के सापेक्ष) में किया जाए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो। इस प्रकार, आयातों में केवल वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी बल्कि हम अर्जेन्टीना – फुटवियर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि यह वृद्धि पर्याप्त रूप से हाल की, अचानक, तीव्र और मात्रात्मक तथा गुणात्मक, दोनों तरह से अत्यधिक होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो”

69. यूएस – लाइन पाइप मामले में, पैनल ने अपीली निकाय द्वारा समीक्षा नहीं किया गया यह विवरण पाया कि “इस निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में आयात आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हाल की अवधि में आयात में ‘वृद्धि’ हो सकती है, परंतु यह जांच अवधि के अंत तक बढ़ते रहना आवश्यक नहीं है या निर्धारण से तुरंत पहले होना आवश्यक नहीं है” :

“यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या बढ़े हुए आयातों के निष्कर्ष को 1998 के पहले सत्र से 1999 के पहले सत्र तक समग्र आयातों में गिरावट के आलोक में बनाए रखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम ‘हाल की’, के अर्थ के संबंध में अपनी चर्चा का स्मरण करते हैं और हमारा निष्कर्ष कि ‘हाल की’ का अर्थ वर्तमान का कोई विश्लेषण नहीं है। हमारा यह भी मत है कि यह तथ्य कि आयात में वृद्धि ‘हाल की’ होनी चाहिए, का यह अर्थ नहीं है कि वह जांचकर्ता प्राधिकारी के निर्धारण के तुरंत पहले की अवधि तक जारी रहनी चाहिए या जांच अवधि के बिल्कुल अंत तक जारी रहनी चाहिए। हमें अनुच्छेद 2.1 में अपने विचार का समर्थन मिलता है जिसमें उल्लेख है कि ‘ऐसा उत्पाद.ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में आयातित किया जा रहा है’ इस करार में ‘वृद्धिशील’ के बदले ‘बढ़ी हुई’ विशेषण का प्रयोग हुआ है। ‘बढ़ी हुई’ शब्द के प्रयोग से हमें पता चलता है कि ऐसी निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है कि आयात में इस समय भी वृद्धि हो रही है। बल्कि आयातों में हाल की अवधि में ‘वृद्धि’ हो सकती है परंतु यह जांच अवधि के अंत तक वृद्धि या निर्धारण के तुरंत पहले तक होना आवश्यक नहीं है। बशर्ते कि जांच किया गया उत्पाद जांच अवधि के अंत में ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में ‘आयातित किया जा रहा हो’, तो अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।”

70. विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण ऊपर उल्लिखित कानून और डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के आलोक में किया गया है।

झ.3.2 आरवीसीएम मात्रा के आधार पर आयात आंकड़ों को पृथक करने हेतु अपनाई गई पद्धति

71. प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि डीजी सिस्टम आयात डेटा से, अलग-अलग प्रविष्टियों से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की आरवीसीएम सामग्री की पहचान करना संभव नहीं है क्योंकि अलग-अलग प्रविष्टियों के आइटम विवरण में विशिष्ट आरवीसीएम सामग्री का उल्लेख नहीं है। इसलिए, प्राधिकृत अधिकारी डीजी सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कच्चे आयात डेटा को ऊपर और 2पीपीएम तक अलग करने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात की मात्रा, जो 2पीपीएम से अधिक है और मात्रा 2पीपीएम तक है, की मात्रा निर्धारित करने के लिए इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर भरोसा किया है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि कई इच्छुक पार्टियों ने प्रश्नावली का जवाब दाखिल करके और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके जांच में भाग लिया है। प्राधिकृत अधिकारी ने 2पीपीएम आरवीसीएम सामग्री तक पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्यात की दावा की गई मात्रा को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया है कि सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के आयात की ऐसी दावाकृत मात्रा डीजी सिस्टम आयात डेटा द्वारा दर्ज की जाती है।
72. प्राधिकृत अधिकारी ने भारत को निर्यात के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों से सूचना प्राप्त की है। उत्पादकों/निर्यातकों ने उनके द्वारा भारत को निर्यात किए गए 2पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की मात्रा का संकेत देते हुए जानकारी प्रदान की है। उत्पादकों/निर्यातकों ने 2पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्यात की अपनी दावाकृत मात्रा की पुष्टि करने के लिए ‘विनिर्देश शीट’ और ‘विश्लेषण के प्रमाण पत्र’ दाखिल किए हैं। विशिष्टता शीट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उपयोग आमतौर पर उत्पादकों द्वारा संभावित ग्राहकों को उस उत्पाद के विनिर्देशों के बारे में बताने के लिए किया जाता है जिसे निर्माता बाजार में उत्पादित और बेचता है। ग्राहक विनिर्देश शीट में उत्पादकों द्वारा प्रकाशित विनिर्देशों के आधार पर सामग्री खरीदते हैं, जबकि विश्लेषण का प्रमाण पत्र वास्तव में आपूर्ति किए गए उत्पाद का प्रतिबिंब है। उपभोक्ता ऑर्डर देते हैं और उत्पाद के घोषित या अधिसूचित विनिर्देशों के आधार पर कीमत तय करते हैं। विनिर्देश शीट के साथ विश्लेषण के प्रमाण पत्र का अनुपालन न करने पर खरीदार निर्माता से खरीदी गई सामग्री को अस्वीकार कर सकता है। हालाँकि, यदि विनिर्देश विनिर्देश शीट के अनुरूप हैं तो खरीदार सामग्री की प्राप्ति को अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्राधिकृत अधिकारी ने आरवीसीएम सामग्री के आधार पर पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात डेटा को वर्गीकृत करने के लिए विनिर्देश शीट और विश्लेषण के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है।

73. प्राधिकृत अधिकारी ने यह देखा है कि भारत को पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात की मुख्यतः दो शृंखला हैं:
- क. डायरेक्ट चैनल: जिससे संबद्ध माल के विदेशी उत्पादक सीधे भारत में ग्राहकों को अपना माल बेचते हैं।
- ख. इनडायरेक्ट चैनल: जहां विषय वस्तु के उत्पादक व्यापारी निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से भारत में ग्राहकों को अपना माल बेचते हैं।
74. प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से किए गए निर्यातों के संबंध में, और किए गए निर्यातों के लिए, सहयोगी उत्पादक जिन्होंने निर्यातक की प्रश्नावली का जवाब दायर किया है, प्राधिकृत अधिकारी अपने नमूने से 2पीपीएम आरवीसीएम सामग्री तक पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के निर्यात की मात्रा को सत्यापित करने में सक्षम हैं। विनिर्देश शीट या उसके लिए प्रस्तुत किए गए विश्लेषण का प्रमाण पत्र और उसे भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात से बाहर रखा गया है। जिन व्यापारी निर्यातकों/व्यापारियों ने सहयोग किया है और दावा किया है कि वे उक्त जांच में 2पीपीएम तक पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्यात कर रहे हैं और नमूना विनिर्देश शीट या विश्लेषण के प्रमाण पत्र के साथ इस हद तक अपना निर्यात डेटा प्रस्तुत किया है, अधिकृत अधिकारी ने 2पीपीएम तक के ऐसे निर्यात पर विचार किया है और उसे भारत में पीयूसी के आयात से अलग रखा है।
75. हालांकि, कुछ भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने संकेत दिया है कि उन्होंने अन्य व्यापारी निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से भारत को 2पीपीएम आरवीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की बिक्री की है जो अप्रत्यक्ष बिक्री चैनल के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, इन व्यापारियों ने सहयोग नहीं किया है और इन व्यापारियों की ओर से उत्पादक/निर्यातक दावा कर रहे हैं कि निर्यात 2पीपीएम तक के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के हैं। हालांकि, इन अन्य व्यापारियों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकृत अधिकारी यह पुष्टि नहीं कर सकता है कि इन व्यापारियों द्वारा किए गए निर्यात एक ही उत्पाद के हैं, क्योंकि व्यापारी विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पादों का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें भाग लेने वाले और गैर-भाग लेने वाले उत्पादक शामिल हैं। पीयूसी के साथ-साथ समान वस्तु चूंकि पीवीसी निलंबन के लिए चीनी राष्ट्रीय मानक 5पीपीएम से नीचे है और इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अप्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से ऐसे सभी निर्यातों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पीयूसी के आयात के रूप में माना है।
76. विचाराधीन उत्पाद और 2 पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात की मात्रा का आकलन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने मूल देश में स्थापित मानकों, विनिर्देश शीट और साक्ष्य के आधार पर डेटा को सॉर्ट किया है। निर्माता/निर्यातक द्वारा भारत को वास्तव में आपूर्ति किए गए उत्पाद का। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, संबंधित सरकारों ने 5 पीपीएम से कम आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के मानक निर्दिष्ट किए हैं। तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी ने ऐसे देशों से सभी निर्यातों पर विचार किया है जो विचाराधीन उत्पाद हैं, जब तक कि किसी इच्छुक पार्टी द्वारा विनिर्देश शीट, विश्लेषण के प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के रूप में कोई विपरीत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
77. यूएसए से आयात के मामले में, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और चूंकि यूएसए का राष्ट्रीय मानक चीन पीआर के समान है, प्राधिकृत अधिकारी ने पीयूसी आधार के कुल आयात में यूएसए से इन आयातों को शामिल किया है। उपलब्ध तथ्यों पर।
78. ताइवान के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी ने रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के आधार पर आयात की आरवीसीएम सामग्री का निर्धारण किया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने ताइवान के भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के दावों को स्वीकार कर लिया है और ताइवान से पीयूसी के आयात की कुल मात्रा की गणना करते समय 2पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन मानते हुए आयात की ऐसी मात्रा को घटा दिया है। भारत। रूस के मामले में, घरेलू उद्योग ने यह दावा करने के लिए कि रूस के उत्पादक 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करते हैं और यदि कोई उत्पादक अपने विनिर्देशन में उल्लेख कर रहा है, रूस में स्थित एक उत्पादक के विनिर्देश शीट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। शीट कि यह 2 पीपीएम से ऊपर पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन करता है जो कि एफसीएटी से संबंधित है कि रूसी राष्ट्रीय मानक भी 2 पीपीएम से ऊपर पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उत्पादन की अनुमति देता है और उपलब्ध तथ्यों के विपरीत स्थापित करने के लिए किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने विषय जांच में भाग

नहीं लिया है। , प्राधिकृत अधिकारी ने रूस से ऐसे आयातों पर विचार किया है जो 2पीपीएम से ऊपर पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अर्थात् विचाराधीन उत्पाद है।

79. आगे यह नोट किया जाता है कि मात्रात्मक प्रतिबंध केवल 2PPM से अधिक RVCM सामग्री वाले PVC सस्पेंशन रेजिन के आयात के विरुद्ध है, इसलिए भले ही निर्माता 2PPM से कम RVCM सामग्री वाले PVC सस्पेंशन रेजिन का उत्पादन और निर्यात कर रहे हों, आपके उपाय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
80. सऊदी अरब, थाईलैंड और मैक्सिको की सरकारों ने कहा है कि सुरक्षा समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार, "एक विकासशील देश के सदस्य में उत्पन्न होने वाले उत्पाद के खिलाफ सुरक्षा उपायों को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि आयात में संबंधित उत्पाद के आयात का हिस्सा सदस्य 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।"। प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9ए(1) के प्रावधान के अनुसार, किसी विकासशील देश से आने वाली किसी भी वस्तु पर इस तरह का कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि आयात का हिस्सा उस देश से ऐसी वस्तुएँ तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होती हैं या जहाँ ऐसी वस्तुएँ एक से अधिक विकासशील देशों से उत्पन्न होती हैं, तब तक, जब तक कि ऐसे सभी देशों से कुल मिलाकर कुल आयात नौ प्रतिशत से अधिक न हो भारत में इस तरह के सामान। यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग सऊदी अरब, थाईलैंड और मैक्सिको की सरकारों द्वारा किए गए दावे के विपरीत कोई साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा है, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने उपर्युक्त देशों की सरकारों के दावे को स्वीकार किया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की गणना करते समय इन देशों से आयातों को बाहर रखा गया है।
81. प्राधिकृत अधिकारी ने डीजी सिस्टम डेटा पर भरोसा किया है और इस जांच के लिए विश्लेषण करने के लिए भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए निर्यात आंकड़ों को स्वीकार किया है और जहां भी निर्माता/निर्यातक के डेटा और डीजी सिस्टम के डेटा के बीच डेटा बेमेल था, प्राधिकृत अधिकारी ने भरोसा किया है और डीजी सिस्टम डेटा पर इसकी परीक्षा और विश्लेषण आधारित।

झ.3.3 समग्र रूप से आयातों में वृद्धि

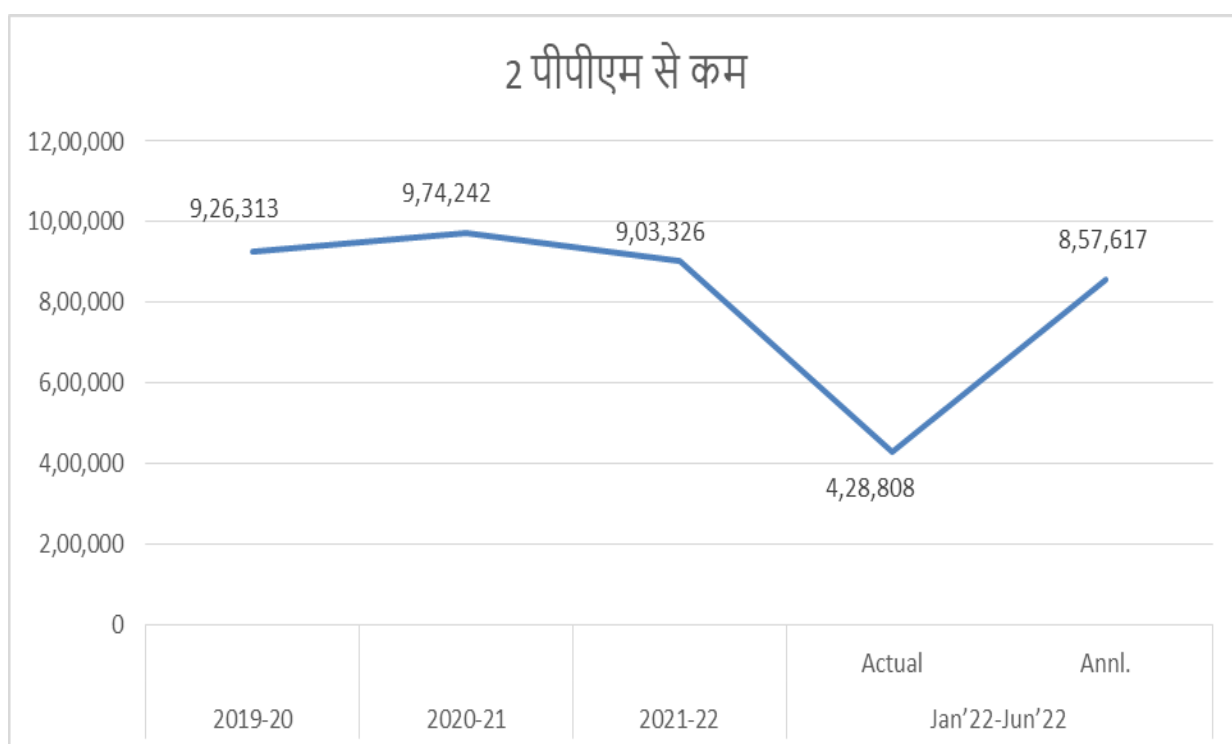
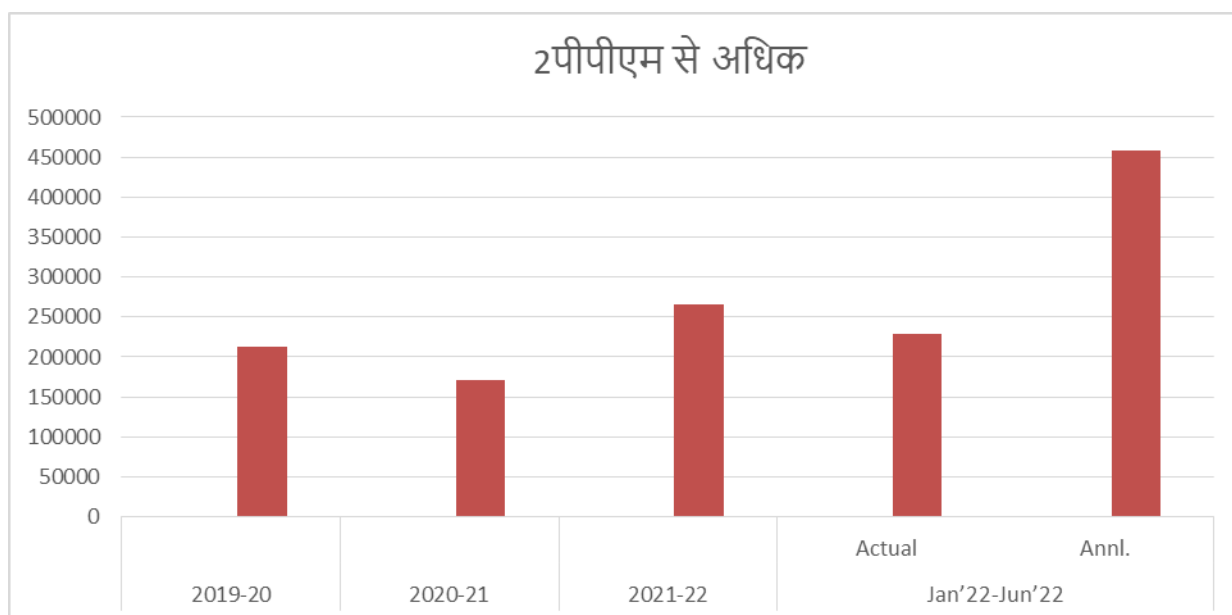
82. आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद को अनेक वर्षों से भारत में आयात किया जा रहा है, तथापि, बिल्कुल हाल की अवधि में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है।
83. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल आयात में वृद्धि नहीं हुई है। उनके गिरावट आई है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2 में रक्षोपाय लगाने की स्थितियां बताई गई हैं। करार का अनुच्छेद 2.1 सदस्य के क्षेत्र में उत्पाद के आयात में वृद्धि को स्पष्ट करता है।

“कोई सदस्य किसी उत्पाद के लिए केवल तभी रक्षोपाय लागू कर सकता है यदि उस सदस्य ने नीचे निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में यह निर्धारित किया है कि ऐसे उत्पाद का समग्र या घरेलू उत्पादन से संबंधित बढ़ी हुई मात्राओं और ऐसी दशाओं में उसके क्षेत्र में आयात हो रहा है जिससे समान या प्रतिस्पर्धी उत्पाद का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है।”

84. करार के अनुच्छेद 2.1 में उल्लेख है कि कोई सदस्य रक्षोपायों हेतु तब आवेदन कर सकता है जब ‘ऐसे उत्पाद’ को बढ़ी हुई मात्राओं और ऐसी दशा में उसके क्षेत्र में आयात किया जा रहा हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या उसका खतरा हो। चूंकि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद केवल 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम मात्रा वाला पीवीसी सस्पेंशन रेजिन इसलिए रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाओं के अनुसार केवल विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा की जांच करनी होगी तथापि, प्राधिकृत अधिकारी ने जहां आवश्यक हो, 2 पीपीएम से कम सहित भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कुल आयातों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने 2 पीपीएम तक या उससे अधिक दोनों आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों की अलग-अलग जांच की है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
पीयूसी (2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन)	एमटी	29,843	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
समान वस्तु (2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन)	एमटी	11,09,420	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808
कुल आयात	एमटी	11,39,263	11,39,263	11,45,767	11,69,293	6,58,006
आयातों में वृद्धि						
पीयूसी	एमटी			(41,424)	94,442	
समान वस्तु	एमटी			47,929	(70,916)	
कुल आयात	एमटी			6,505	23,526	



85. विचाराधीन उत्पाद का आयात (अर्थात् 2पीपीएम से अधिक आरबीसीएम सामग्री के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन) बहुत ही कम अवधि में समग्र रूप से काफी बढ़ा है। पीयूसी का आयात वर्ष 2021-22 के दौरान और जनवरी से जून 2022 में अचानक बढ़ गया है। आयात की मात्रा 2019-20 से 2020-21 तक दोगुनी हो गई है;

आयात की मात्रा 2020-21 से तीन गुना से अधिक हो गई है। पीयूसी के समग्र आयात में आधार वर्ष से लगभग 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में हाल ही में अचानक, तेज और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

86. दूसरी ओर, यह देखा गया है कि 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की आयात मात्रा में गिरावट आई है। वास्तव में, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के कुल आयातों में वृद्धि केवल पीयूसी के आयात में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है और इसलिए ये उपाय के दायरे से बाहर हैं।
87. प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए कि क्या इसमें पूर्ववर्ती संगत अवधि की तुलना में जनवरी, 2022 – जून, 2022 में वृद्धि के अभाव में, जनवरी 2020-जून 2020, जनवरी 2021-जून, 2021 के आयातों का विश्लेषण किया है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न अवधि में आयात की मात्रा दर्शाई गई है।

विवरण	यूओएम	जन.'20-जून'20	जन'21-जून'21	जन'22-जून'22
2 पीपीएम से अधिक	एमटी	1,13,329	1,99,689	2,29,197
2 पीपीएम से कम	एमटी	4,40,445	4,89,983	4,28,808

88. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, यानी जनवरी 2021-जून 2021 की तुलना में सबसे हाल की अवधि में लगभग 15% गुना बढ़ गया है और जनवरी 2020- की तुलना में% बढ़ गया है। जून 2020. जनवरी 2022 से जून 2022 की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में एक बार फिर काफी वृद्धि हुई है। जनवरी 2021-जून 2021 की अवधि के दौरान 2पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का आयात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कमोबेश समान रहा है। जनवरी 2022-जून 2022 की अवधि में इन सामानों के आयात की मात्रा में गिरावट आई है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल की अवधि में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

झ.3.4 सापेक्ष रूप से आयात

89. इस बात की जांच की गई थी कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात भारतीय उत्पादन, भारत में मांग, भारत में घरेलू उत्पादकों की बिक्री, भारत में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कुल आयात के संबंध में आयातों में वृद्धि दर्शाते हैं।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
पीयूसी का आयात	एमटी	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
कुल भारतीय उत्पादन (समान वस्तु)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	99	52	105
भारत में मांग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	101	56	112
भारत में कुल आयात	एमटी	11,39,263	11,45,767	11,69,293	6,58,006	13,16,011
घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	100	54	109
निम्न के संबंध में पीयूसी का आयात						
Ø भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	127	207	207

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
Ø भारतीय मांग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	122	189	189
Ø कुल आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	121	184	184
Ø घरेलू उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	129	200	200

90. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध आयातों में सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बिल्कुल हाल की अवधि में *** प्रतिशत की संगत और अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों में सकल घरेलू मांग के संबंध में आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बिल्कुल हाल की अवधि में *** प्रतिशत की संगत और अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- ग. भारत में कुल आयात के संबद्ध में सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बिल्कुल हाल की अवधि में *** प्रतिशत की संगत और अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों में सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में आधार वर्ष में ***प्रतिशत से बिल्कुल हाल की अवधि में *** प्रतिशत की संगत और अत्यधिक वृद्धि हुई है।

91. अतः यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों में भारत में आयात, भारतीय उत्पादन, सकल घरेलू खपत और घरेलू उत्पादकों की बिक्री के संबंध में संगत रूप से और भारी वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन से आयातों में अन्य देशों से विलंब और उच्चतर यात्रा अवधि के कारण वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में न केवल कुल आयातों के संबंध में बल्कि भारतीय उत्पादन, मांग और घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों के संबंध में भी वृद्धि हुई है।

ज. अप्रत्याशित घटनाक्रम

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. अप्रत्याशित घटनाक्रम के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आयातों में वृद्धि के लिए अप्रत्याशित घटनाक्रम केवल चीन से संबंधित है।
- ख. अप्रत्याशित घटनाक्रम और आयातों में वृद्धि के बीच कोई संबंध नहीं है, जो इंडिया – लोहा और इस्पात उत्पाद में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा पुष्ट किया जाना अपेक्षित है।
- ग. आयातों में वृद्धि फरवरी, 2022 में चीन जन.गण., यूएसए और थाइलैंड से विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) के होमोपोलिमर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के कारण हुई है और न कि अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

93. अप्रत्याशित घटनाक्रम के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आयातों में वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध, बढ़ती हुई वैश्विक मालभाड़ा दरों और चीन में स्थिर आंतरिक मालभाड़ा लागत तथा चीन जन.गण. में खपत और उत्पादन के बीच असमानता जैसे अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण हुई है।

- ख. रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है और पेट्रोकेमिकल की उत्पादन लागत (वीसीएम सहित) में वृद्धि हुई है। वीसीएम के प्रयोग से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। चीन के उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण हेतु कोयले का प्रयोग करते हैं जो चीन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध है। तदनुसार, चीन जन.गण. में उत्पादन लागत नहीं बढ़ी।
- ग. यद्यपि वैश्विक मालभाड़ा दरों में वृद्धि हुई जिसके चलते आयातित कच्ची सामग्री की खरीद लागत में वृद्धि हुई परंतु चीन के उत्पादक ऐसी कीमत वृद्धि से सुरक्षित थे क्योंकि उन्हें घरेलू रूप से कोयला उपलब्ध था।
- घ. विचाराधीन उत्पाद की अधिकांश मांग चीन जन.गण. के पूर्वी भाग में है जिसमें अनेक लॉकडाउन हुए जिनकी वजह से मांग में गिरावट आई, तथापि पश्चिमी भाग में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन होता है जिसमें इतने लॉकडाउन नहीं हुए। इससे चीन जन.गण. में निर्यात योग्य अधिशेष में वृद्धि हुई।
- ड. चूंकि विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश उत्पाद चीन जन.गण. में स्थित हैं, इसलिए अप्रत्याशित घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से चीन जन.गण. से संबंधित है। वास्तव में, आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद को केवल चीन जन.गण. से आयात किया गया।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों द्वारा माने गए अप्रत्याशित घटनाक्रम की वास्तविक पहलुओं पर प्रश्न नहीं उठाया है। यद्यपि, चीन, यूएसए और थाइलैंड से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो गया है, तथापि केवल चीन से आयात बढ़े और अन्य देशों से नहीं।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत आयातों में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के कारण नहीं हुई है बल्कि ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुई जो उत्पादकों के कतिपय समूह पर लागू होती है जो 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम वाले पीवीसी के विनिर्माण में शामिल हैं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि चीन तथा अन्य देशों से 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी के आयातों में गिरावट आई है।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

94. गैट के अनुच्छेद XIX के अन्तर्गत जांच करने वाले प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वे 'अप्रत्याशित घटनाक्रमों' की जांच करें जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को परिणामी गंभीर क्षति हुई। इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 9(1) में यह भी प्रावधान है कि बड़े हुए आयात निम्नानुसार अप्रत्याशित घटनाक्रमों के (:ही होना चाहिए परिणाम के रूप में

“अधिकृत अधिकारी इस जांच की शुरुआत की तिथि से आठ महीने के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे केन्द्र सरकार अनुमति दे, इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, जांच के अधीन वस्तुओं के बड़े आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा पहुंचाने का खतरा उत्पन्न किया है और बड़े आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है”

95. अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में वृद्धि उन घटनाक्रमों के आधार पर ही होनी चाहिए जो अप्रत्याशित थे अथवा जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया गया था। इसके अलावा, यह घटनाक्रम दायित्व सौंपे जाने अर्थात् विभिन्न डब्ल्यूटीओ करारों के अन्तर्गत प्रतिबद्धताओं का पालन करने का संकल्प तथा शुल्क रियायत देने का संकल्प लेते हुए डब्ल्यूटीओ में आरोहण के समय अप्रत्याशित रहे होंगे।
96. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसके फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई, रूस-यूक्रेन संघर्ष-, वैश्विक भाड़ा दरों में वृद्धि और चीन में बेचे न गए अतिरिक्त उत्पादन थे। प्राधिकारी ने नीचे पहचान किए गए घटनाक्रमों की पहचान की है।

अ.3.1 रूस-यूक्रेन संघर्ष

97. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन की लागत में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप, एथीलीन मार्ग के द्वारा निर्मित पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि तेल की कीमतों में जनवरी 2022 से जून 2022 की अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
98. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण या तो एथीलीन मार्ग से अथवा कार्बाइड मार्ग से किया जा सकता है। जबकि वैश्विक स्तर पर अधिकांश उत्पादक एथीलीन रूट के माध्यम से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण करते हैं, चीन में कुछ उत्पादकों और अनेक देशों (जिसमें भारत शामिल है) कार्बाइड मार्ग के माध्यम से भी निर्माण करते हैं। जबकि, एथीलीन मार्ग के द्वारा उत्पादन करने वाले निर्माताओं के उत्पादन की लागत में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई, कार्बाइड मार्ग के माध्यम से ऐसे निर्माताओं के उत्पादन की लागत और जहां देश के भीतर घरेलू स्तर पर कोयला उपलब्ध था, रूस-यूक्रेन संघर्ष के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ था। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों से कम लागत पर चीन में घरेलू स्तर पर उपलब्ध है जिसके फलस्वरूप आगे चीन में ऐसे निर्माताओं के उत्पादन की लगतार कमतर लागत रही। आवेदकों द्वारा किए गए दावे का खंडन चीन में उत्पादकों, चीन की सरकार और ऐसे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं किया गया है।
99. अधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि 2 पीपीएम से अधिक के आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का प्राथमिक रूप से निर्माण कार्बाइड मार्ग के माध्यम से किया जाता है (जहां कोयला की कीमतें स्थिर रही हैं) जबकि 2 पीपीएम से कम आरवीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का प्राथमिक रूप से निर्माण एथीलीन मार्ग के माध्यम से किया जाता है (जहां कीमतें रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित हो गई हैं)। वीसीएम लागतों में वृद्धि के फलस्वरूप, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कीमत में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि 2 पीपीएम से अधिक रेजिन के इन उत्पादकों ने इन लागत वृद्धि का सामना नहीं किया।

ज.3.2 वैश्विक भाड़े दरों में वृद्धि

100. घरेलू उद्योग ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बाद मालभाड़ा दरों में काफी वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया था कि घरेलू उद्योग एथीलीन रूट के माध्यम से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण करता है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का कच्चा माल अर्थात् प्रमुख रूप से आयात "वीसीएम" किया जाता है। यह तर्क दिया गया है कि वैश्विक मालभाड़ा दरों में पर्याप्त वृद्धि के कारण भारत में कच्चे माल की लागत अर्थात् में वृद्धि हुई "वीसीएम", जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि 2 पीपीएम से ऊपर के राल के उत्पादक हालांकि उत्पादन लागत में इस तरह की वृद्धि से अछूते थे, क्योंकि यह उत्पाद कोयले से उत्पादित किया गया था, जो कोयले के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से काफी कम कीमत पर संबंधित उत्पादकों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध था। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी को घरेलू उद्योग का यह दावा विश्वसनीय नहीं लगता है क्योंकि मालभाड़ा दरों में किसी भी वृद्धि, जिसने कथित रूप से आवेदकों की कच्ची सामग्री की लागत को प्रभावित किया है, ने भारत में आयातित विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य को समान रूप से प्रभावित किया होगा - जिससे घरेलू उद्योग पर ऐसे आयातों के हानिकारक प्रभावों को निष्क्रिय किया जा सके। अतः प्राधिकृत अधिकारी आवेदकों के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ज.3.3 चीन जन.गण.में बिक्री न किए गए अत्यधिक उत्पादक

101. आवेदकों ने अनुरोध किया कि (क) कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के कारण चीन में विचाराधीन उत्पाद की खपत और उत्पादन के बीच असमानता थी (ख) इस उत्पाद का मुख्य रूप से खपत चीन के पूर्वी भाग में किया जाता है जिसने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की बहुत अधिक संख्या का सामना किया जबकि विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख रूप से उत्पादन चीन के पश्चिमी भाग में किया जाता है जिसमें उतना लॉकडाउन का सामना नहीं किया जितना पूर्वी भाग में किया गया था। इसके फलस्वरूप, डाउनस्ट्रीम के उद्योग को बंद करना पड़ा जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन में अनुपातित कटौती के बिना चीन में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई।

102. इस असंतुलन के कारण, इस उत्पाद के उत्पादन में मांग में गिरावट के अनुपात में कमी नहीं आई जिसके फलस्वरूप इथीलीन मार्ग के माध्यम से उत्पादकों की लागत से बहुत कमतर कीमत पर इन उत्पादकों के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध रही। इसके अलावा, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप, मालसूची जमा हो जाएगी, यदि उसे बाजार में नहीं बेचा जाए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि निश्चित सीमाओं से अधिक मालसूची का जमा होना किसी उत्पादक के लिए एक विकल्प भी नहीं है और इस कारण से उत्पादकों को निरंतर रूप से इस उत्पाद की बिक्री करनी होती है।
103. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के कारण हुई है। हालांकि यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क यूएसए, थाइलैंड और चीन से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों पर लागू नहीं थी और वह 2 पीपीएम तक के और उससे ऊपर दोनों की आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों पर लागू थी। हालांकि यह देखा गया है कि 2 पीपीएम से अधिक के आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी के आयातों में वृद्धि हुई है, जबकि 2 पीपीएम से नीचे के आयातों में गिरावट आई है। यदि पीवीसी के आयातों में वृद्धि का कारण पीवीसी सस्पेंशन रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क का समाप्त होना था तब इसका यह आशय होगा कि 2 पीपीएम से कम की आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों में समरूप वृद्धि भी हुई होगी, हालांकि ऐसा मामला नहीं है। किसी भी स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों के दावे का उनके द्वारा पहचान की गई अप्रत्याशित घटनाक्रमों के संबंध में खंडन नहीं किया है। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के कारण आयातों में वृद्धि हुई है।
104. रिकॉर्ड पर तथ्यों पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पीवीसी के आयातों में अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है।

ट. गंभीर क्षति और/गंभीर क्षति का खतरा

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- क. आवेदकों ने उन कारकों को दर्शाया है जो गंभीर क्षति के खतरे को दर्शा सकते हैं लेकिन वह चीन से आयातों तक सीमित है।
 - ख. आवेदकों का गंभीर क्षति का दावा हाल की जांचों में कार्यकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और प्रकाशित सूचना के विपरीत है।
 - ग. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में मात्रा और कीमत, दोनों के मामले में गंभीर क्षति अथवा क्षति के खतरे के नहीं होने को दर्शाते हुए विशेष रूप से 2021-2022 और 22-में सुधार हुआ है। इस प्रकार 23, क्षति अथवा क्षति के खतरे का कोई निष्कर्ष कायम रहने योग्य नहीं होगा, जैसा यूएसलाइन पाइप में - माना गया था। अपीलीय निकाय द्वारा
 - घ. क्षमता, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मालसूची में गिरावट आई है और हानि लाभ में परिवर्तित हो गई है।
 - ड. जांच की अवधि के बाद भी, यह उद्योग बहुत अच्छा कर रहा है और आवेदकों को क्षति का कोई खतरा नहीं है।
 - च. कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और आवेदकों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
 - छ. जबकि जांच की अवधि को अप्रैल 1 से जून 30, 2022 माना गया है, आवेदक तिमाही बार आंकड़ों पर विश्वास कर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच की अवधि को योग के रूप में और न कि खंडों के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

- ज. चूंकि जुलाई से सितंबर, 2022 के लिए आंकड़े जांच की अवधि से परे हैं, अतः उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी केवल जांच की अवधि के लिए क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए बाध्य हैं।
- झ. जांच की अवधि में परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर इसकी शुरुआत के बाद विचार नहीं किया जा सकता है।
- ञ. जनवरी से जून, 2022 के लिए संपूर्ण रूप से सूचना पर तिमाही सूचना के बजाए अवश्य विश्वास किया जाना चाहिए।
- ट. जुलाई से सितंबर, 2022 के लिए सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका स्रोत, आधार अथवा समर्थन में साक्ष्य स्पष्ट नहीं है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

106. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. घरेलू उद्योग ने गंभीर क्षति जो आसन्न थी और जिसे पहले ही देखा जा सकता था और जो वास्तविक गंभीर क्षति नहीं है, का विरोध करने वाली याचिका दायर की थी।
- ख. आवेदन दायर करने के बाद, घरेलू उद्योग ने पहले ही विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण क्षति उठाना शुरू कर दिया है।
- ग. जबकि वीसीएम की कीमत में फरवरी, 2022 से वृद्धि हुई है, विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग उस स्थिति में जिसमें इसके उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, अपनी कीमतों को कम कर कम कीमत पर आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य रहा है। बड़े ग्राहकों को औसत कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है।
- च. चीन के उत्पादकों द्वारा उद्धृत कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से बहुत कम है जो आगे घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करेगा/उस पर दबाव डालेगा।
- छ. विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा समान वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत से कम है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की कीमतों के बीच अंतर बढ़ गया, विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई।
- ज. चूंकि भारत में मांगपूर्ति में अंतर-, विश्व में अधिक क्षमताएं हैं अतः विदेशी निर्यातक बहुत अधिक : में भारतीय बाजार को भेजते हैं। इस प्रकार के आयातों की कम कीमतें भारतीय उत्पादकों पर मात्रा कीमत दबाव पैदा करती है।
- झ. घरेलू उद्योग को नियमित आधार पर कच्चे माल को उठाने के लिए दीर्घावधि संविदागत दायित्वों के आधार पर आदर्शतम क्षमता उपयोग पर इन संयंत्रों को चलाने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया और उद्योग की बाध्यताओं के कारण मात्रा संबंधी मानदंडों के संदर्भ में हानि उठानी पड़ी है क्योंकि वीसीएम को सामान्य कंटेनरों के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है तथा वीसीएम की ढुलाई करने के लिए विशेष रूप से निर्मित जहाजों को बंदरगाहों के बीच अपने नियत रोटेशन को बनाए रखना होता है। कच्चे माल को चुनने में गलती होने की स्थिति में, भविष्य में कच्चे माल की खरीद करने में वित्तीय बोझ तथा अनिश्चितता होगी और यह वैश्विक पीवीसी उद्योग में बहुत अधिक प्रभाव पैदा करेगा क्योंकि जहाज अन्य बंदरगाहों तक नियमित रोटेशन बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा, वीसीएम का भंडारण विशिष्ट टैंकों में किया जाता है और मालसूची की सीमा है जिसे उत्पादक द्वारा माना जा सकता है।

- ज. घरेलू उद्योग की मालसूची में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ट. यदि घरेलू उद्योग ने कीमतों में कटौती की होती तब उसे बाजार की हानि हुई होती।
- ठ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने भी भारत में अन्य आयातों के बाजार के बाजार को (समान उत्पाद का) अपने कब्जे में ले लिया है।
- ड. जबकि घरेलू उद्योग के लाभ में 2020-में हानि से सुधार हुआ है 21, उनके बिल्कुल हाल की अवधि में बहुत हद तक गिरावट आई है। जब तिमाही आधार पर देखा जाता है, तब लाभ में 2021-की तीसरी 22 2021 तिमाही की तुलना में- की चौथी तिमाही में 22***प्रतिशत तथा 2021-की चौथी तिमाही की 22 2022 तुलना में- में पहली तिमाही में 23***प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- ढ. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत एक आवेदक को 2022-की पहली तिमाही के दौरान 23 2022 घाटा हुआ है और दोनों आवेदकों को-की दूसरी तिमाही में 23० हानि हुई।
- ण. नकद लाभ तथा लाभ के मार्जिन में बिल्कुल हाल की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- त. बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में लाभ में 2022- की पहली तिमाही में 23[***] प्रतिशत बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में लाभ में 2021-22 की तीसरी तिमाही में [***] प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- थ. घरेलू उद्योग को क्षति विचाराधीन उत्पाद की कम कीमत पर आयातों और न कि किसी अन्य कारकों के कारण हुई है।

ट.3 प्राधिकारी की जांच

107. अधिकृत अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या इस उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस अधिनियम की धारा 9क(4) के अनुसार, गंभीर क्षति का आशय घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक समग्र क्षति को उत्पन्न करने वाली क्षति से है जबकि गंभीर क्षति के खतरे का आशय गंभीर क्षति के स्पष्ट और आसन्न खतरे से है। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली का नियम 8(क) में क्षति के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है:

“अधिकृत अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अभवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेंगे:

(क) इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए जांच में कि बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रही है, अधिकृत अधिकारी उस उद्योग की स्थिति विशेषकर पूर्ण और सापेक्ष रूप में संबंधित वस्तुओं के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, बढ़े हुए आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले एक वस्तुनिष्ठ और मात्रा बताने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे;”

108. उपर्युक्त कानूनी सिद्धांत को देखते हुए क्षति से संबंधित मापदंडों का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।
109. विचाराधीन उत्पाद अर्थात् 2 पीपीएम से अधिक की मात्रा वाले आरवीसीएम के साथ पीवीसी संस्पेशन रेजिन और समान वस्तु अर्थात् 2 पीपीएम से अधिक की मात्रा वाले आरवीसीएम के साथ पीवीसी संस्पेशन रेजिन का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर और एक ही उद्देश्यों से किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति के आकलन के उद्देश्य से 2 पीपीएम तक और उससे अधिक दोनों के आयातों पर पृथक् रूप से विचार किया है और जांच की है कि क्या 2 पीपीएम से अधिक के पीवीसी संस्पेशन रेजिन के आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा पहुंचाने का खतरा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या 2 पीपीएम से कम रेजिन के आयात दावा की गई क्षति का एक कारण हो सकता था।

ट.3.1 मांग/खपत का आकलन

110. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए गए समान उत्पाद की घरेलू बिक्री और भारत में समान उत्पाद के आयात और भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के योग के रूप में किया गया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग - बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति - बिक्री	सूचीबद्ध	100	103	116	63	126
अन्य उत्पादक	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	94	51	102
पीयूसी का आयात	एमटी	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
समान वस्तु का आयात	एमटी	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808	8,57,617
मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99%	101%	56%	112%

111. यह देखा गया है कि उत्पाद की मांग पूरी और हाल की अवधि में बढ़ी है। इसके अलावा, हाल की अवधि में मांग (वार्षिक आधार पर) आधार वर्ष की मांग की तुलना में अधिक थी। तथापि, संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि जबकि मांग में आधार वर्ष की तुलना में हाल की अवधि में *** एमटी की वृद्धि हुई है, संबद्ध आयातों में *** एमटी की वृद्धि हुई है, जिसकी मात्रा मांग में वृद्धि का लगभग ***%। इस प्रकार, खपत में वृद्धि काफी हद तक संबद्ध उत्पाद के आयातों द्वारा समाहित की गई थी।

ट.3.2 इस अवधि के दौरान कीमतों की कर्मिक वृद्धि

112. पूरी अवधि के दौरान पीवीसी रेजिन के संबद्ध और गैर-विषयगत आयातों की आयात कीमत की जांच की गई। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है। यह देखा गया है कि हाल की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की पहुंच कीमत के बीच अंतर आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इसके अलावा, 2021-22 के बाद से पीयूसी और समान वस्तु के बीच कीमत अंतर में वृद्धि हुई है और यह पैटर्न हाल की अवधि में जारी रहा है।

पहुंच कीमत	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
पीयूसी	₹/एमटी	65,754	81,281	1,21,784	1,27,503
समान वस्तु	₹/एमटी	68,504	80,141	1,23,615	1,31,951
अंतर	₹/एमटी	-2,749	1,140	-1,831	-4,448

ट.3.3 कीमत में कटौती

113. इसकी जांच की गई थी कि क्या संबद्ध उत्पाद का आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और जिसके कारण बाजार में कीमत में कटौती हुई।

विवरण	यूनिट	पीयूसी	समान वस्तु
निवल बिक्री से प्राप्ति	₹/एमटी	***	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,27,503	1,31,951
कीमत में कटौती	₹/एमटी	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	5-15%	1-5%

114. यह देखा गया है कि पीयूसी और समान वस्तु, दोनों के संबंध में कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कीमत में कटौती समान वस्तु के संबंध में कीमत में कटौती से अधिक है। इसके

अलावा, अधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कटौती को अलग से नहीं देखा जा सकता है और इसके बजाए उसकी जांच अन्य कारकों के अनुरूप की जानी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु के संबंध में कीमत में कम लगातार कटौती के बावजूद, समान वस्तु के आयातों का बाजार हिस्सा और संपूर्ण तथा सापेक्ष मात्रा में गिरावट आई है। उपर्युक्त के अलावा, जैसा कि स्पष्ट रूप से नोट किया गया है, आयातों का उछाल दो से अधिक पीपीएम की वीसीएम मात्रा वाले पीवीसी रेजिन के क्षेत्र में ही है और इस कारण से जब कीमत में कटौती का सह-संबंध मात्रा और क्षति संबंधी अन्य मानदंडों से है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि 2 पीपीएम से कम के पीवीसी रेजिन के कारण घरेलू उद्योग के समग्र प्रदर्शन को क्षति पहुंच रही है। हालांकि, पीयूसी के मामले में, कीमत में कटौती पर्याप्त है और इस उछाल को पहले ही नोट कर लिया गया है और इस कारण से यह नोट किया जाता है कि पीयूसी घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति का वास्तविक कारण है।

ट.3.4 कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

115. प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या संबद्ध उत्पादों के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास हो रहा था अथवा वे कम हो रहे थे।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	162	166
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	185	194

116. यह देखा गया है कि हाल की अवधि (जनवरी-जून, 2022) में, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित समान वस्तु की बिक्री की लागत में *** प्रति एमटी की वृद्धि हुई है, बिक्री मूल्य में *** की गिरावट आई है। प्रति मीट्रिक टन। हालांकि, आयातित पीयूसी के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है, यह नोट किया जाता है कि इस तरह की वृद्धि के बावजूद, पीयूसी की पहुंच कीमत बिक्री की लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भी कम है। इस प्रकार आयात कीमतों को कम कर रहे हैं और मूल्य वृद्धि को रोक रहे हैं जो पीयूसी के ऐसे कम कीमत वाले आयातों के अभाव में अन्यथा हुआ होता।

117. आवेदकों ने आगे यह अनुरोध किया है कि बड़े ग्राहकों तक औसत बिक्री कीमत विचाराधीन उत्पाद के कम कीमत पर आयातों के कारण कमी आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अक्तूबर, 2021 के बाद, सबसे बड़े ग्राहकों को दोनों आवेदकों की बिक्री कीमत में काफी हद तक गिरावट आई है।

ट.3.5 बाजार हिस्सा

118. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों, समान वस्तु के आयातों और घरेलू उत्पादों का बाजार हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	114	114
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	92	89
संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	98	96
संबद्ध उत्पाद का आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	122	189
समान वस्तु का आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	97	82

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
कुल मांग	%	***	***	***	***

119. यह देखा गया है कि हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है, जबकि समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों और विचाराधीन उत्पाद के अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के बाजार हिस्से में हाल की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत घटाकर अपना बाजार हिस्सा बनाए रखा है। घरेलू उत्पादक खपत में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहे हैं जो पीयूसी के आयातों द्वारा बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया गया है।
120. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार कीमत उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति के आलोक में देखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वीसीएम की खरीद में बहुत विशेष और अलगअलग स्थितियां आवश्यक होती हैं। वीसीएम की दुलाई विशेष वैसल्स में की जाती है। ये समर्पित वैसल - होते हैं जो वीसीएम की दुलाई में ही कार्य में लगाए जाते हैं। इस कारण से, यह संभव नहीं है कि वीसीएम की खरीद को रोका जाए। वीसीएम की खरीद संबंधी निर्णय पीवीसी की बिक्री मात्रा अथवा बिक्री कीमत से संबद्ध नहीं है। खरीद बिक्री पर आश्रित नहीं होती है। वीसीएम के सीमित आपूर्तिकर्ता हैं और एक प्रकारात्मक खरीद बहुत अधिक मात्रा में होती है, जबकि पीवीसी की बिक्री कम मात्रा में होती है। वीसीएम की अलगअलग खरीद - की वृहद को देखते हुए, खरीद की योजना अच्छे तरीके से और बहुत पहले बनाई जाती है। इसके विपरीत, बिक्री की मात्रा तात्कालिक आधार पर अधिकांशतः महीने के भीतर आपूर्ति के लिए है। इसके अलावा, किसी भी उत्पादक के पास वीसीएम और पीवीसी, दोनों के लिए बहुत सीमित भंडारण सुविधा होती है। इस कारण से, वीसीएम की खपत और पीवीसी का उत्पादन एक मजबूरी है। इसके अलावा, एक बार उत्पादन हो जाने पर, कोई भी उत्पादक लंबी समय अवधि तक पीवीसी की मालसूची नहीं रख सकता है। पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उत्पादकों के पास वीसीएम और पीवीसी, दोनों की बहुत सीमित मात्रा में भंडारण सुविधाएं हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के लिए कीमतों को रोकना और या तो वीसीएम अथवा पीवीसी के लिए मालसूची के जमा होने की स्थिति का सामना करने का विकल्प नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास वीसीएम की खरीद को रोकने का कोई विकल्प नहीं होता है।

ट.3.6. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

121. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री का विश्लेषण किया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	103	52	103
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	115	58	117
क्षमता उपयोग	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	112	113	113
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	63	126

122. यह देखा गया है कि इन मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन खराब नहीं हुआ है। आवेदकों ने यह निवेदन किया है कि उद्योग की प्रकृति के कारण घरेलू उद्योग के परिमाण मानदंड प्रभावित नहीं हुए हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि कुल मांग में वृद्धि का एक बहुत ही नगण्य भाग दर्शाती है। जबकि हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की कुल मांग में 10% की वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि में घरेलू उद्योग की बिक्री का हिस्सा कुल मांग में वृद्धि का लगभग 1% है। इसी समय, मांग में इस वृद्धि में

पीयूसी के आयात में वृद्धि का हिस्सा लगभग 80% था। इस प्रकार, मांग में वृद्धि को पीयूसी के आयातों द्वारा बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया गया था जिसके कारण घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था।

ट.3.7. मालसूची

123. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	35	197	197

124. यह देखा गया है कि सबसे हाल की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची में काफी वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे हाल की अवधि में ***% वृद्धि दर्शाती है। भले ही घरेलू उद्योग की बिक्री 'सबसे हाल की अवधि' में थोड़ी बढ़ी है, पीयूसी के आयात में वृद्धि के कारण, घरेलू उद्योग मांग में पूर्ण वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण घरेलू माल की सूची उद्योग जमा हो गए हैं। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया कि घरेलू उद्योग इस प्रकार महत्वपूर्ण स्तर की मालसूची नहीं रख सकता है

ट.3.8 रोजगार और उत्पादकता

125. घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	118	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी.सं/	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	97	97
प्रति दिन उत्पादकता	एमटीदिन/	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	115	117

126. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ।

ट.3.9 लाभ/हानि

127. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22
लाभहानि/	₹/एमटी	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	288	386	246
नकद लाभ	₹/एमटी	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	612	788	546
बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में लाभ	₹/एमटी	(***)	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	221	208	134

128. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में घाटा हो रहा था। आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग घाटा उठा रहा था, हालांकि घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 से जून 2022 तक मुनाफा कमा रहा था। हालांकि, यह देखा

गया है कि हाल की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। जो घरेलू उद्योग को आसन्न क्षति का संकेत है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी आधार वर्ष में बिक्री की लागत से कम थी जिसके कारण घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में घाटा हुआ। आगे यह भी देखा गया है कि जहां 2020-21 और 2021-22 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है, वहीं हाल की अवधि में प्रति यूनिट लाभ, प्रति यूनिट नकद लाभ और बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में मुनाफे में गिरावट आई है। 2020-21 और 2021-22 की तुलना में।

129. चूंकि आवेदकों ने तर्क दिया था कि हाल की अवधि में आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा था और घरेलू उद्योग के लाभ मानदंड हाल की अवधि में गिरावट दिखा रहे थे, सबसे हाल की अवधि में लाभ की जांच की गई थी। सबसे हालिया अवधि (जनवरी-जून, 2022) में तिमाही आधार पर प्रदर्शन पर विचार करके आगे।
130. यह जांच की गई थी कि क्या बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क(4) में यह प्रावधान है कि गंभीर क्षति का खतरा का आशय गंभीर क्षति के खपत और आसन्न खतरे से है। रक्षोपाय संबंधी करार में भी यह प्रावधान है कि “गंभीर क्षति का खतरा” को गंभीर क्षति समझा जाएगा जो स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे के मौजूद होने का निर्धारण तथ्यों के आधार पर और न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना पर होगी।

ट. 3.10 आयातों में वृद्धि की दर

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में इस अवधि के दौरान बहुत अधिक दर से वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जन.'22-जून'22	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	एमटी	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
वृद्धि की दर	%	-	-19%	55%	-	72%
आधार वर्ष की तुलना में	%	-	-19%	25%	-	115%

132. यह देखा गया है कि आयातों की मात्रा में पूर्व वर्ष और बिल्कुल हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, आयात 2019-20 की तुलना में बिल्कुल हाल की अवधि में लगभग दुगुनी हो गई है। इस प्रकार, आयातों में वृद्धि की दर बहुत अधिक थी।

ट.3.11. 2 पीपीएम तक की आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट

133. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की आयात कीमत में प्रवृत्ति की जांच की।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.- जून'22
पहुंच कीमत					
पीयूसी	₹/एमटी	65,754	81,281	1,21,784	1,27,503
समान वस्तु	₹/एमटी	68,504	80,141	1,23,615	1,31,951
अंतर	₹/एमटी	-2,749	1,140	-1,831	-4,448
आयात की मात्रा					
पीयूसी	एमटी	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197
समान वस्तु	एमटी	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जन.- जून'22
सकल आयातों की तुलना में पीयूसी आयातों का हिस्सा	%	19%	15%	23%	35%

134. यह देखा गया है कि समान वस्तु और विचाराधीन उत्पाद के बीच कीमत के अंतर में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि पहले भारत में समान वस्तु के आयातों का प्रमुख हिस्सा था, पहुंच मूल्य के बीच अंतर में वृद्धि के कारण, पीयूसी के आयातों ने भारत में अधिकांश आयातों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, जब आपूर्तिकर्ताओं की संख्या और आपूर्ति करने वाले देश।

ट.3.12. कीमत में कटौती

135. जैसा कि इस जांच परिणाम के संगत खंड में नोट किया गया है, कीमत में कटौती सकारात्मक और बहुत अधिक है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी बाजार कीमत को बनाए रखने में कीमत को कम करने के लिए बाध्य हुए हैं।
136. उपर्युक्त पैरा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राहकों ने अपेक्षकृत सस्ते संबद्ध उत्पाद को अपना लिया जिसके फलस्वरूप इसकी मांग में वृद्धि हुई और गैर संबद्ध आयातों में गिरावट आई।

ट.3.13. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट।

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22	July-Sept 22
बिक्री की लागत	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	113	162	166	135
विक्रय मूल्य	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	130	185	183	(130)
लाभ हानि	₹/MT	(***)	***	***	***	(***)
		(100)	287	386	246	(266)

137. प्राधिकृत अधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की भी जांच की है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा गया है, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत आधार वर्ष के दौरान बिक्री कीमत से अधिक थी। बाद के वर्षों में (अर्थात् 2020-21 से जून 2022 तक), बिक्री की लागत बिक्री मूल्य से कम थी और घरेलू उद्योग लाभप्रद प्रतीत होता है। हालांकि, यह देखा गया है कि 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान - जो कि आयात में उछाल के तुरंत बाद की अवधि है - घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत बिक्री मूल्य से अधिक है, और इसलिए घरेलू उद्योग घाटे में चल रहा है। पीओआई के बाद की अवधि के दौरान जांच की गई। ये नुकसान इस तथ्य के बावजूद हुए हैं कि 2022 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान बिक्री की लागत की तुलना में 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान बिक्री की लागत में लगभग ***% की कमी आई है। यह भी देखा गया है कि जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट आई है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आयात में वृद्धि का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि के कारण गंभीर क्षति का एक स्पष्ट और आसन्न खतरा मौजूद है।

ट.3.14. अप्रत्याशित घटनाओं की निरंतर मौजूदगी

138. जैसा कि इस जांच परिणाम के संगत भाग में नोट किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न भारत में उत्पादन और खपत में असमानता, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई है। यह नोट किया जाता है कि ये दोनों कारक बाजार में अभी भी मौजूद हैं।

ट 3.15. अप्रत्याशित विकास का निरंतर अस्तित्व

139. जैसा कि इस निष्कर्ष के प्रासंगिक खंड में उल्लेख किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि अप्रत्याशित विकास के कारण है, जिसमें कोविड-19 के कारण चीन में उत्पादन और खपत में असमानता, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शामिल है। यह ध्यान दिया जाता है कि ये दोनों कारक बाजार में प्रबल बने हुए हैं।

140. पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि ने न केवल घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है बल्कि आगे क्षति उत्पन्न करने का खतरा भी पैदा कर रहा है।
- क. आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष रूप में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में वृद्धि की दर बहुत अधिक है और आयातों में आधार वर्ष की तुलना में बीस गुणा तक वृद्धि हुई है।
- ग. इस उत्पाद की वैश्विक अधिक आपूर्ति है। चीन के उत्पादकों के पास बहुत (संबद्ध वस्तुओं का-संबद्ध और गैर) अधिक अतिरिक्त क्षमता है।
- घ. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही है और इसने घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी प्रभाव डाला है और कीमत में वृद्धि को रोक दिया है, जो बाजार में हुई होती।
- ङ. प्रमुख ग्राहकों को घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- च. संबद्ध आयातों की कीमत सी की कीमत की तुलना में बहुत पीपीएम तक आरवीसीएम मात्रा वाले पीवी 2 अधिक हद तक कम है।
- छ. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उत्पादकों और अन्य आयातों ने बाजार खो दिया है।
- ज. जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में गिरावट नहीं आई, घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता में तीव्र गिरावट और मालसूची के संचयन का सामना करना पड़ रहा था।
- झ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है और यह आगे जुलाई-सितंबर, 2022 की बाद की अवधि में गिरकर हानि में चली गई।

ठ. कारणात्मक संबंध

141. इस नियमावली के नियम 8(ख) के अनुसार, प्राधिकारी से इस तथ्य का निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या बड़े हुए आयात गंभीर क्षति अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा होने का कारण था। इस संबंध में, कोरिया – डेयरी में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा टिप्पणियों, जो “आरोपण” का निर्धारण करने के लिए मूल दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, को नोट किया गया है। इस कारण से, कारणात्मक संबंध के आकलन के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले एक वस्तुनिष्ठ और परिमाण योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया तथा यह पता लगाया कि क्या संबद्ध उत्पादों के बड़े हुए आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के कारणों और गंभीर क्षति के खतरे में से एक था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह भी पता लगाया कि क्या बड़े हुए आयातों के अलावा कारक घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण था। जबकि ऐसा कोई निर्धारित “अन्य कारक” नहीं है जिन्हें प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी ने इस तथ्य को माना कि क्या 2 पीपीएम तक पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों, प्रौद्योगिकी में विकास, निर्यात कार्य निष्पादन, उत्पादकता, मांग में संकुचन, उत्पाद का संभावित पाटन, जैसे कारक घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण था।

ठ.1.1 2 पीपीएम तक आरवीसीएम वाले पीवीसी रेजिन के आयातों की मात्रा और मूल्य

142. यह नोट किया गया है कि समान वस्तु के आयातों की मात्रा में उसके बाजार हिस्से के साथ इस अवधि के दौरान मामूली से गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और समान वस्तु की आयातों की कीमत की तुलना में कम है। जैसा कि ऊपर में नोट किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कीमत में कटौती समान वस्तु के संबंध में कीमत में कटौती से अधिक है। इसके अलावा, अधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कटौती को अलग से नहीं देखा जा सकता है और इसके बजाए इसकी जांच अन्य कारकों के अनुरूप की जानी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु के संबंध में एक लघु सकारात्मक कीमत में कटौती के बावजूद, समान वस्तु के बाजार हिस्से और आयातों के पूर्ण तथा सापेक्ष मात्रा में गिरावट आई है। इस कारण से, समान वस्तु के संबंध में कीमत में कटौती का घरेलू उद्योग की बिक्री पर प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, पीयूसी के मामले में, कीमत में कटौती अधिक है क्योंकि इसके फलस्वरूप, इसके अपने बाजार हिस्से और बिक्री मात्राओं में सुधार हुआ है।

ठ.1.2 इस उत्पाद का संभावित पाटन

143. इस उत्पाद के संभावित पाटन का कोई साक्ष्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए गणना उपलब्ध कराई कि पिछले एक वर्ष की अवधि (पाटन मामले की संभावित जांच अवधि) अथवा पिछले छह महीने की अवधि (पाटन के मामले की न्यूनतम जांच अवधि) के लिए भी क्षति मार्जिन नकारात्मक था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क नहीं दिया कि इस उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण था।

ठ.1.3 मांग में संकुचन

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में कोई संकुचन नहीं है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस आधार पर कोई क्षति नहीं हुई है।

ठ.1.4 खपत का पैटर्न

145. ऐसा कोई दावा नहीं है कि इन वस्तुओं के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन हुआ है।

ठ.1.5 प्रतस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार है।

ठ.1.6 प्रौद्योगिकी में विकास

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

ठ.1.7 उत्पादकता

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से, घरेलू उद्योग को इस आधार पर कोई क्षति नहीं हुई है।

ठ.1.8 घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण केवल घरेलू प्रदर्शन तक सीमित है और निर्यात प्रदर्शन का प्रभाव उससे बाहर रखा गया है।

ठ.1.9 अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

150. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इस कारण से, उत्पादित और बेची गई अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

151. नियमावली और निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों और भारतीय उद्योग द्वारा सामना की जा रही गंभीर क्षति के खतरे अथवा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की है। प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

क. भारत में समान वस्तु के उत्पादन, घरेलू खपत, कुल आयात, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और आयातों के संबंध में तथा पूर्ण रूप से बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि रही है।

ख. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में उछाल इतना अधिक था कि पीवीसी सस्टेंशन रेजिन के समग्र आयातों में तब भी वृद्धि दर्शाई है जब 2 पीपीएम तक के रेजिन के आयातों में हाल की अवधि में गिरावट दर्शाई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद के बाजार हिस्से में भारत में वृद्धि हुई है।

घ. संबद्ध रेजिन की कीमतों में तीव्र गिरावट हुई थी। इन कीमतों में एक माह से कम की अवधि में भी बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि में सामना करने के बावजूद कीमतों को कम करने के लिए बाध्य था।

ड. जब कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों को कोई हानि नहीं हुई है, लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में गिरावट दर्ज की है। बिक्री कीमत के एक प्रतिशत के रूप में लाभ, नकद लाभ और बिक्री कीमत के प्रतिशत

के रूप में लाभ में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। लाभ में यह गिरावट इतनी अधिक थी कि घरेलू उद्योग को जुलाई-सितंबर, 2022 की अवधि में वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा।

च. घरेलू उद्योग की मालसूची में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।

152. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार आया है। हालांकि, इस जांच ने यह दर्शाया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, जिनकी कीमत गैर-संबद्ध पीवीसी आयातों की तुलना में बहुत कम थी। गैर-संबद्ध आयातों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक कीमत को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि गैर-संबद्ध वस्तुओं का आयात कीमत में तीव्र गिरावट और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में परिणामस्वरूप गिरावट का प्रमुख कारण नहीं हो सकता था। प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के द्वारा कीमत में कटौती है जिसमें घरेलू उद्योग को बिल्कुल हाल की अवधि में उसकी कीमतों और मार्जिन को कम करने के लिए बाध्य किया है। कीमतों में कमी के कारण, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग में क्षति आयातों में वृद्धि के कारण हुई है।

ड. समायोजन योजना

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

153. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समायोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- क. आवेदकों ने एक परियोजना रिपोर्ट के साथ अर्थक्षम समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है और यह योजना अनुमानों के आधार पर केवल एक पेज का है।
- ख. रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश एक उपयुक्त समायोजन योजना के नहीं रहने पर नहीं की जा सकती है, जैसा कि पैथेलिक एनहाइड्राइड, स्टेनलेस स्टील का कोल्ड रोलड फैलेट उत्पाद, अनराउट एल्युमिनियम का नॉन एलायड इंगोट्स और फैलेक्सबील स्लैबस्टॉक पोलीयोल के मामले में प्राधिकारी की कार्य-पद्धति रही है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

154. घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- क. केमप्लास्ट की योजना [***] जैसे विभिन्न उपाय पर उत्पादन की लागत को कम करने की है।
- ख. डीसीडब्ल्यू की योजना [***] तक शुल्क लाने की है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, आवेदकों ने एक अर्थक्षम समायोजना प्रस्तुत की है।
- घ. चूंकि आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण चीन में उत्पादन की लागत कमतर होने के कारण है, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजना में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से उत्पादन की लागत को कम करने के लिए उपाय शामिल है।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, समायोजन योजना के लिए अपेक्षित कोई विशिष्ट प्रपत्र अथवा लंबाई नहीं है और कानूनी अपेक्षा आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सकारात्मक समायोजन योजना के लिए है, जैसा कि कोरिया डेयरी उत्पादों में पैनल द्वारा माना गया है। -

ड.3 अधिकृत अधिकारी की जांच

155. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में रक्षोपाय शुल्कों को लगाने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा एक समायोजन योजना अपेक्षित है। इस संबंध में, रक्षोपाय संबंधी करार में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“संरचनात्मक समायोजन के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के बजाए उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता की पहचान करना”

156. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 5.1 में प्रावधान है कि सदस्य गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका निवारण करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए केवल आवश्यक सीमा तक ही रक्षोपाय शुल्क लागू करेगा। रक्षोपाय संबंधी करार का अनुच्छेद 7.1 डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश को केवल ऐसी समयावधि के लिए ही रक्षोपाय शुल्क लागू करने का अधिकार प्रदान करता है जो गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका निवारण करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। अनुच्छेद 7.4 यह अधिकार प्रदान करता है कि ऐसी स्थिति में जहां अनुच्छेद 12 के पैरा 1 के प्रावधानों के अन्तर्गत यथा-अधिसूचित रक्षोपाय शुल्क की प्रत्याशित समय अवधि एक साल से अधिक हो, में समायोजन को आसान बनाने के उद्देश्य से, इस शुल्क को लागू करने वाला सदस्य आवेदन की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर इसे प्रगामी रूप से उदार बनाएगा। ये प्रावधान मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 9(1), नियम 10, नियम 13 और नियम 4(घ)(ii) के साथ एक ही मामले के संबंध में हैं। इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 5(2) में निम्नानुसार प्रावधान है:

“(2) उप नियम (1) में संदर्भित आवेदन इन नियमों के साथ परिशिष्ट के रूप में फार्म में किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित लगाया जाएगा –

(ख) आयातों के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए एक सकारात्मक समायोजन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों अथवा की जाने के लिए बनाई गई योजना अथवा दोनों के संबंध में विवरण”

157. वर्तमान मामले में आवेदकों ने बड़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित विकास के साथ समायोजित करने के लिए समायोजन योजना प्रस्तुत की है। दोनों आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी उत्पादन लागत को कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से समायोजन योजना प्रस्तुत की है। चूंकि आयात में वृद्धि वैश्विक स्तर पर उत्पादकों की उत्पादन लागत पर अप्रत्याशित परिस्थितियों के प्रभाव के कारण हुई है, सिवाय उनके जो संबद्ध पीवीसी रेजिन के उत्पादन में लगे हुए हैं, प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि उत्पादन की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक समायोजन योजना उचित और व्यावहारिक होनी चाहिए। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी ने केवल एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विचार किया है, यह देखते हुए कि कोविड-19 का प्रभाव कम हो रहा है और चीन पीआर सहित दुनिया सामान्य स्थिति की बहाली के रास्ते पर है। इसके अलावा, देश रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को समायोजित करने के उपाय भी कर रहे हैं। इसलिए, प्राधिकृत अधिकारी केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मात्रात्मक उपाय लागू करने की सिफारिश कर रहा है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि उपाय केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया है, आवेदकों द्वारा लाए गए समायोजन योजना की उपयुक्तता के संबंध में निर्धारण करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ढ. जन हित

ढ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जन हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- क. ओपीपीआई, जो भारत में प्लास्टिक प्रोसेसरों और प्लास्टिक कच्चा माल निर्माताओं का एक संघ है, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन पर रक्षोपाय शुल्कों को लगाने का कठोरतापूर्वक विरोध करता है क्योंकि इसके फलस्वरूप छोटी यूनिटों द्वारा निर्मित तैयार वस्तु महंगी और अप्रतिस्पर्धी बन जाएगी।
 - ख. मांग-आपूर्ति में अंतर है और शुल्कों को लगाए जाने से बाजार की हानि होगी जिससे घरेलू उत्पादकों को एकाधिकारवादी लाभ मिलेगा जो केवल कुल मांग का केवल 50 प्रतिशत पूरा कर सकते हैं।
 - ग. यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तब मांग और आपूर्ति में असंतुलन अंतिम उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी करेगा जिससे अंतिम प्रयोक्ताओं की बिक्री और मांग कम हो जाएगी।
 - घ. शुल्कों को लगाया जाना जनजित के विरुद्ध होगा क्योंकि यह घरेलू उत्पादकों को कार्टल बनाने, बाजार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने और बाजार प्रवेश के लिए अवरोध पैदा करने की अनुमति देगा, यह प्रयोक्ताओं को नियमित आपूर्ति में कटौती करेगा, कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति देगा और इसके फलस्वरूप मार्केट में असमानता आएगी।

- ड. शुल्कों को लगाए जाने से हजारों अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा जो एमएसएमई हैं और एक प्रमुख रोजगार सृजक हैं, इसके फलस्वरूप खंडित लघु उद्योग के लिए कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होगी।
- च. पीवीसी के लिए कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला इन्वर्टेड है और उपायों को लगाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पीवीसी के कुछ उत्पादक और हजारों अंतिम प्रयोक्ता हैं।
- छ. आवेदकों की प्रतिस्पर्धीरोधी कार्य-पद्धतियों ने अंतिम प्रयोक्ताओं की स्थिति को और नाजुक बना दिया है। आवेदक अनेक उत्पादों के लिए शुल्क की मांग कर व्यापार उपचारात्मक शुल्कों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
- ज. चूंकि शुल्कों को लगाना जनहित में नहीं है, अतः इस जांच को अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा मिथाइल एसिटोसेट में किया गया है।
- झ. शुल्क को लगाए जाने के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी।
- ञ. निर्माण और कृषि संबंधी क्षेत्र में पाइप की मांग में कोविड के बाद धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी जो लगाए गए किसी शुल्कों द्वारा प्रभावित होगा।

ढ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

159. घरेलू उद्योग द्वारा जन हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. जन हित को कुल मिलाकर उत्पादकों, उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों के आलोक में ही देखा जाना चाहिए।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, इन शुल्कों को लगाए जाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये शुल्क मात्रात्मक प्रतिबंध पर लगाए जाने के लिए और न कि रक्षोपाय शुल्कों के लिए हैं।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, डाउनस्ट्रीम उद्योग विगत में अर्थात् आयातों में उछाल के पूर्व प्रतिस्पर्धी रहे, जब यह संबद्ध वस्तुओं की खरीद बहुत उच्चतर स्तर पर कर रहा था।
- घ. फरवरी, 2022 तक लागू पाटनरोधी शुल्क ने डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा निर्यातों अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगा।
- ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग को एकाधिकारवादी लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि भारत में पांच उत्पादक और भारतीय बाजार में अनेक प्रतिस्पर्धी निर्यातक हैं।
- च. रक्षोपाय शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बाधित नहीं होगी क्योंकि इन शुल्कों को 2पीपीएम से अधिक आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों पर ही लागू किया जाएगा तथा समान वस्तु का स्वतंत्र रूप से आयात भारत में किया जाएगा। बिल्कुल हाल की अवधि और अप्रैल-जून, 2021 के पूर्व 96 प्रतिशत आयात 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का था, जो जारी रहेगा।
- छ. चीन जन.गण. से भी 2 पीपीएम से कम आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के उत्पादक शुल्कों की सिफारिश करने के बाद स्वतंत्र रूप से इसका निर्यात कर पाएंगे।
- ज. मात्रात्मक प्रतिबंधों की सिफारिश भारत में वर्तमान तथा भावी मांग को ध्यान में रख सकता है।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, इस उछाल की अवधि के पूर्व भारत में मांग-आपूर्ति का कोई संतुलन नहीं था। यह शुल्क उछाल की अवधि के पूर्व की स्थिति के समान स्थिति को सुनिश्चित करेगा।
- ञ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों द्वारा प्रतिस्पर्धीरोधी कार्य-पद्धतियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

- ट. इन प्रयोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उद्दाल के पूर्व कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण हानि नहीं हुई है। इस कारण से, रक्षोपाय शुल्कों को लगाए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- ठ. व्यापार उपचारात्मक शुल्कों के अध्वधीन अधिकांश उत्पादों का मूल्य चेन इन्वर्टेड है, चूंकि प्रयोक्ताओं की संख्या आवश्यक रूप से उत्पादकों की संख्या से अधिक है। अतः यह उत्पादकों को सही निवारण से वंचित नहीं कर सकता है।
- ड. प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किया गया कोई भी शुल्क एक विस्तृत जांच के बाद और न कि घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर है। इस प्रकार व्यापार उपचारात्मक शुल्कों का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है।
- ढ. चूंकि 2 पीपीएम से अधिक के आरबीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का आयात पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अतः शुल्कों को लगाए जाने से ऐसे आयात विनियमित होंगे और अनावश्यक नुकसान से पर्यावरण को संरक्षित करेंगे।

ढ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

160. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 में निम्नानुसार उल्लेख है:

“कोई भी सदस्य पूर्व में स्थापित तथा गैट 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप सार्वजनिक की गई प्रक्रियाओं के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच का पालन करते हुए ही रक्षोपाय शुल्क लागू कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्कसंगत आम सूचना और सार्वजनिक सुनवाई तथा अन्य उपयुक्त साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षकारों की प्रस्तुति का उत्तर देने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कि क्या रक्षोपाय शुल्क को लागू करना जनहित में होगा, अवसर सहित साक्ष्य और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी अपने जांच परिणामों और तथ्य तथा कानून के सभी संगत मुद्दों पर पहुंचे हुए तर्कसंगत निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।”

161. उपर्युक्त को देखते हुए, इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा। यद्यपि अनुच्छेद 3.1 मूल्यांकन के तरीके पर कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है, हालांकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों पर रक्षोपाय शुल्कों के प्रभाव का मूल्यांकन तथा अलग अलग हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिस्पर्धी हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।
162. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के संबंध में कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच मात्रात्मक प्रतिबंध शुल्कों को लगाए जाने के संबंध में है और यह कि वह कुछ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन अर्थात् 2 पीपीएम से अधिक के आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी पर लगाया जाएगा। इस प्रकार 2 पीपीएम तक के आरबीसीएम मात्रा वाले पीवीसी का आयात को स्वतंत्र रूप से आयात किया जाना जारी रहेगा। चूंकि किसी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश वर्तमान जांच के अनुसरण में नहीं की जाएगी, इन प्रयोक्ताओं को नहीं रोका जाएगा। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि फरवरी, 2022 तक चीन जन.गण., थाइलैंड और यूएसए के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था। किसी पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क की इसी अवधि के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार, कीमतों में किसी भी वृद्धि से प्रयोक्ता संभवतः अप्रतिस्पर्धी नहीं होंगे।
163. भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये शुल्क केवल उन उत्पादकों पर लगाए जाएंगे जो 2 पीपीएम से अधिक आरबीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्यात करते हैं और भारत में समान वस्तु के आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्दाल की अवधि से पूर्व, करीब 90 प्रतिशत आयात समान वस्तु के हुए थे और इस प्रकार मांग-आपूर्ति में किसी अंतर को इस प्रकार के आयातों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, सिफारिश किया गया शुल्क वर्तमान मांग-आपूर्ति में अंतर और भावी मांग में प्रत्याशित वृद्धि पर विचार करेगा। इस प्रकार, रक्षोपाय शुल्कों को लगाए जाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बाधित नहीं होगी।

164. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि उपायों को लागू करने से घरेलू उद्योग को एक कार्टेल बनाने और भारत में एक एकाधिकार प्रतियोगिता बनाने की अनुमति मिलेगी। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि भारत में समान वस्तुओं के अनेक उत्पादक हैं। इसके अलावा, घरेलू उत्पादक न केवल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं बल्कि भारत में समान वस्तु के आयात के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां 35-45% खपत गैर-विषयगत आयातों द्वारा पूरी की जा रही थी और इस तरह के लेख के आयात के लिए कोई उपाय अनुशंसित नहीं किया जा रहा है, भारत में घरेलू उत्पादकों और आयातों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।
165. भारत में घरेलू उद्योग की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में, प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी प्रथाओं के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। इसके अलावा, इस बात पर विचार करते हुए कि वर्तमान घरेलू उद्योग प्रासंगिक अवधि के दौरान भारत में केवल 10-20% मांग को पूरा करता है। यह भी नोट किया जाता है कि दो आवेदकों के अलावा तीन अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। इस प्रकार, घरेलू बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार के निर्माण की संभावना नहीं है।

ण. निष्कर्ष

166. ऊपर में की गई जांच और विश्लेषण के आधार पर, अधिकृत अधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- (i). विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्ण और सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
 - (ii). विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुई है।
 - (iii). विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे और इससे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा। घरेलू उद्योग को अपना ग्राहक आधार बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
 - (v). विचाराधीन उत्पाद के आयातों के बाजार हिस्से में भारत में वृद्धि हुई है।
 - (vi). घरेलू उद्योग ने सबसे हाल की अवधि में गंभीर क्षति उठाना शुरू किया है क्यों लाभ, नकद लाभ और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में लाभ में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की मालसूची में बिल्कुल हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
 - (vii). घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण हुई है।
 - (viii). मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय शुल्कों को लगाना जन हित में होगा। यह घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति को रोकेगा जबकि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर मामूली और सहन करने वाला प्रभाव होगा क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की मांग भारत में समान वस्तु के आयात के रूप में पूरा किया जाना जारी रहेगा।
 - (ix) सबसे हालिया अवधि के दौरान भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग [***] मीट्रिक टन है। हाल की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग का लगभग [***%] थी, जबकि 2पीपीएम तक आरबीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का आयात लगभग [***%] हाल की अवधि के दौरान भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग का। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की किसी भी संभावित मांग-आपूर्ति के अंतर को उन देशों से आयात द्वारा भरा जा सकता है जिन्हें माप के आवेदन से बाहर रखा गया है, या 2PPM तक RVCAM सामग्री वाले PVC सस्पेंशन रेजिन के आयात से।

त. सिफारिशें

167. उपर्युक्त विश्लेषण को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि:

- (i). विचाराधीन उत्पाद अर्थात् 2पीपीएम से अधिक के आरवीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का आयात भारत में ऐसे बड़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे प्रतिस्पर्धी उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू उद्योग के निर्माण को गंभीर क्षति होगी अथवा होने का खतरा उत्पन्न होगा।
- (ii). घरेलू उद्योग ने बिल्कुल हाल की अवधि में गंभीर क्षति उठाना शुरू किया है।
- (iii). मौजूदा परिस्थितियां घरेलू उद्योग को और अधिक गंभीर क्षति से बचाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने को उचित ठहराती हैं।

168. तदनुसार, प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क की सिफारिश करते हैं:

- (i). विचाराधीन उत्पाद के आयात विनियमित होते हैं और नीचे दी गई तालिका में यथा-उल्लिखित स्तरों से आगे की अनुमति नहीं दी जाती है। इस मात्रा को जांच की अवधि के दौरान तीन प्रतिनिधिक वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में आयातों के औसत के आधार पर रक्षोपाय शुल्क (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली के नियम 9(1) के संदर्भ में निकाला गया है। इसके अलावा, नीचे दी गई तालिका में सिफारिश की गई कोटा भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर और अप्रैल, 2019 से जून, 2022 (39 महीने) की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद है।
- (ii). विचाराधीन उत्पाद, यदि उसका उत्पादन अन्य विकासशील देशों में किया जाता हो (नीचे तालिका में उल्लिखित देशों को छोड़कर), सिफारिश किए गए शुल्कों के अध्यधीन नहीं होगा क्योंकि इस जांच ने अन्य विकासशील देशों से किसी आयात को प्रकट नहीं किया है। विकसित देशों में उत्पादित उत्पाद विश्लेषण प्रमाण-पत्र की आयात किए गए उत्पाद की आरवीसीएम मात्रा 2 पीपीएम से कम है, के रूप में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अध्यधीन शुल्कों की सिफारिश करने के अध्यधीन नहीं होगी।
- (iii). विदेश व्यापार महानिदेशालय ('डीजीएफटी') ने दिनांक 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना जिसका फाइल नं. 01/92/180/106/AM-11/पीसी-VI/पीआरए है, जारी किया था जिसमें इसने एफटीडीआर अधिनियम, 1922 की धारा 9क(4)(क) के अन्तर्गत विकसित देशों की एक सूची अधिसूचित की थी। यह अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पर आधारित थी। हालांकि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि विकासशील देशों की सूची को बाद में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से संशोधित किया गया है। चूंकि चीन जन.गण. को छोड़कर दिनांक 5 फरवरी, 2016 की उक्त अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) में सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयात किसी एक देश में 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, इस प्रकार के विकासशील देशों (चीन जन.गण. को छोड़कर) के मूल के '2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन' के आयात विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(i) के संदर्भ में मात्रात्मक प्रतिबंध आकर्षित नहीं करेंगे।
- (iv). प्राधिकारी 2 पीपीएम से अधिक आरवीसीएम के साथ पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयातों पर ही मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हैं। 2 पीपीएम तक के आरवीसीएम वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का निर्माण करने वाले उत्पादक/निर्यातक किसी प्रतिबंध के अध्यधीन नहीं होंगे। जबकि प्राधिकारी ने विनिर्देश शीट, सीएओ और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर इस तथ्य का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विश्वास किया है कि क्या उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् 2 पीपीएम रेजिन से अधिक) अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु (अर्थात् 2 पीपीएम तक के रेजिन) का निर्यात कार्यान्वयन के उद्देश्यों से उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से किया था, यह उपयुक्त होगा कि विश्लेषण प्रमाण-पत्र के आधार इस उत्पाद के विनिवेश पर विचार किया जाए, जिसे इस तथ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए कि क्या यह आयात विचाराधीन उत्पाद का अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का है, प्रत्येक आयात खेप के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- (v). इन आयातों की अनुमति कोटा की इलेक्ट्रॉनिक/वास्तविक समय निगरानी को आसान बनाने के लिए ही ईडीआई पोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। इस कोटा की निगरानी तिमाही आधार पर की जाएगी। किसी

भी तिमाही में अनुमति दी गई कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के योग से अधिक नहीं होगा। किसी एक तिमाही के लिए किसी अप्रयुक्त कोटा को अगली तिमाही में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, किसी भी तिमाही के लिए अत्यधिक रूप से अप्रयुक्त कोटा की कटौती अगली तिमाही के लिए कोटा से किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध आयातक और निर्यातक इन मात्राओं को निर्बाध रूप से विनियमित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, इस तरीके से कोटा का आबंटन सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता, आयातक और निर्यातक को कोई अनुचित कठिनाई नहीं होती है। यदि आवश्यक हो, तो ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंधों को शासित करने के लिए आगे तौर तरीकों को संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जा सकता है।

- (vi). तदनुसार, अधिकृत अधिकारी, विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(I) के अनुसार एफटीडीआर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हैं।

कोटा (एमटी में)

तिमाही	प्रथम	दूसरी	तीसरी	चौथी
कुल पीयूसी*	54,203	54,920	55,646	56,382
चीन से आयात	20,494	20,765	21,039	21,317
ताईवान से आयात	15,100	15,299	15,502	15,707
यूएसए से आयात	9,690	9,818	9,948	10,079
अन्य विकासशील देशों से आयात	नीचे दी गई सूची के अनुसार रक्षोपाय शुल्कों लगाए जाने से निम्नलिखित देशों को छूट दी गई**			
अन्य विकसित देशों से आयात	2 पीपीएम से अधिक के विचाराधीन उत्पाद के आयातों की कोई जानकारी नहीं है			

*2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान तथा इस रिपोर्ट के पैरा 12(जे) में दी गई परिभाषा के अनुसार आयातों के आधार पर

** प्राधिकृत अधिकारी ने सबसे हालिया अवधि से पहले के तीन वर्षों के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा का औसत लेकर कोटा निर्धारित किया है। जो आंकड़ा आया है उसे तिमाही आधार पर विभाजित किया गया है।

169. सबसे हालिया अवधि के दौरान भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग [***] मीट्रिक टन है। हाल की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग का लगभग [***%] रही, जबकि 2 पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का आयात सबसे हालिया अवधि के दौरान भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कुल घरेलू मांग का लगभग [***%] और पिछले वर्षों में [35% - 45%] की सीमा में भिन्नता है। प्राधिकृत अधिकारी नोट करता है कि भारत में पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की किसी भी संभावित मांग-आपूर्ति के अंतर को उन देशों से आयात करके पूरा किया जा सकता है जिन्हें उपाय के आवेदन से बाहर रखा गया है, या 2 पीपीएम तक आरवीसीएम सामग्री वाले पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात से।

** दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी) के अनुसार विकसित देशों की सूची

1. अफगानिस्तान
2. अल्बानिया
3. अल्जीरिया
4. अंगोला
5. आर्मेनिया

6. अजरबैजान
7. बंगलादेश
8. बेलारूस
9. बेलिजे
10. बेनिन
11. भूटान
12. बोलिविया (प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ)
13. बोसानिया और हेरजेगोविना
14. बोत्स्वाना
15. ब्राजील
16. बुल्गारिया
17. बुर्किना फास्को
18. बुरुंडी
19. काबो वेरदे
20. कम्बोडिया
21. कैमरून
22. सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
23. चाड
24. कोलम्बिया
25. कोमोरोस
26. कांगो
27. कोस्टा रिका
28. कोटे डी' लवाइरे
29. क्यूबा
30. कोरिया गणराज्य
31. कांगो गणराज्य
32. डजिबोटी
33. डोमिनिका
34. डोमिनिकन गणराज्य
35. इक्वाडोर
36. मिस्र
37. अल सल्वाडोर

38. इरिट्रिया
39. इथोपिया
40. फिजी
41. गाबोन
42. गाम्बिया
43. जार्जिया
44. घाना
45. ग्रेनाडा
46. गुवाटेमाला
47. गुइनिया
48. गुइनिया बिसाऊ
49. गुयाना
50. हैती
51. होंडुरस
52. इंडोनेशिया
53. ईरान (इस्लामिक गणराज्य)
54. इराक
55. जैमैका
56. जार्डन
57. कजाकिस्तान
58. केन्या
59. किरिबाती
60. किरगिस्तान
61. लाओ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
62. लेबनान
63. लेसोथो
64. लाइबेरिया
65. लीबिया
66. मडागास्कर
67. मलावी
68. मलेशिया
69. मालदीव

70. माली
71. मार्शल आइसलैंड
72. मारिटानिया
73. मारीशस
74. मेक्सिको
75. माइक्रोनेशिया (फेडरल स्टेट ऑफ)
76. गोलियामं
77. मोनेटेनेग्रो
78. मोरक्को
79. मोजाम्बिक
80. म्यांनमार
81. नामिबिया
82. नेपाल
83. निकारगुआ
84. निगर
85. नाइजीरिया
86. पाकिस्तान
87. पलाऊ
88. पालेस्टाइन
89. पनामा
90. पापुआ न्यू गुइनिया
91. पारागुए
92. पेरू
93. फिलीपीन्स
94. मालडोवा गणराज्य
95. मानियारो
96. रवांडा
97. सेंट लूसिया
98. सेंट विसेंट और दि ग्रेनाडाइंस
99. सामोआ
100. साओ टोमे एंड प्रिंसिप
101. सेनेगल

102. सर्बिया
103. साइरा लिओन
104. सोलोमन आइसलैंड
105. सोमालिया
106. साउथ अफ्रीका
107. साउथ सूडान
108. श्री लंका
109. सूडान
110. सूरीनाम
111. स्विट्जरलैंड
112. सीरिया अरब रिपब्लिक
113. तजाकिस्तान
114. थाइलैंड
115. दि फारमर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया
116. टिमर-लेस्ते
117. टोंगो
118. टोंगा
119. ट्युनिशिया
120. तुर्की
121. तुर्कमेनिस्तान
122. टुवालु
123. युगांडा
124. यूक्रेन
125. यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया
126. उज़्बेकिस्तान
127. वनाउटु
128. वियतनाम
129. यमन
130. जाम्बिया
131. जिम्बाब्वे

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 15th May, 2023

Case No. – (SG) – 02/2022**Subject : Safeguard investigation concerning imports of Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Resins with Residual Vinyl Chloride Monomer (RVCM) Content above 2 PPM into India****F. No. 22/2/2022-DGTR.**—Final Findings – Proceeding under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012**A. INTRODUCTION**

1. An application dated 15th July 2022 was filed before the Authorised Officer under Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (hereinafter also referred to as the “Act”) read with the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 (hereinafter also referred to as the “Rules”) by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited (hereinafter also referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) seeking imposition of safeguard measure in the form of quantitative restrictions on imports of Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Resins with Residual Vinyl Chloride Monomer (RVCM) Content above 2 PPM (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India. The applicants have alleged that the product under consideration is being imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that is producing “like or directly competitive goods” in India.
2. And whereas, in view of the duly substantiated petition filed by the applicants and sufficient *prima facie* evidence submitted regarding the recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the subject goods and consequent injury in the form of serious injury and threat of serious injury to the domestic industry, the Authorised Officer initiated the safeguard (quantitative restrictions) investigation vide Notification No. 22/2/2022-DGTR dated 16th September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine the alleged increase in imports and consequent injury to the domestic industry, and the need for imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions to address such injury.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed by the Authorised Officer with regard to the subject investigation:
 - a. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the Rules, a copy of the initiation notification dated 16th September 2022 and a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants was forwarded to the Central Government, i.e., the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India and the interested parties.
 - b. The questionnaire to be answered by the exporters/importers / domestic producers was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the Public Notice of Initiation, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules.
 - c. In response to the initiation notification, the following interested parties registered themselves with the Authorised Officer
 - i. Taipei Economic and Cultural Center in India, Taiwan
 - ii. Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India
 - iii. Trade Interests and Remedies Division, Department of Foreign Trade, Thailand,
 - iv. General Authority of Foreign Trade, The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
 - v. Director of Trade Defense, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade Indonesia
 - vi. The Ministry of International Trade & Industry, Government of Malaysia
 - vii. Embassy of Mexico in India, New Delhi
 - viii. Pt. Nas Barakah International

-
- ix. AGC Vinythai Public Company Limited
 - x. LGC Petrochemical India Pvt. Ltd (LGCPIN)
 - xi. LG Chem Ltd
 - xii. China General Plastics Corporation
 - xiii. CGPC Polymer Corporation
 - xiv. Chiping Xinfu Polyvinyl Chloride Co., Ltd,
 - xv. CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.
 - xvi. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
 - xvii. Formosa Plastics Corporation
 - xviii. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
 - xix. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
 - xx. Ordos Junzheng Energy & Chemical Co., Ltd.
 - xxi. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.
 - xxii. Shandong Xinfu Import & Export Co., Ltd.
 - xxiii. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.
 - xxiv. Tianjin LG Bohai Chemical Company Limited
 - xxv. XINJIANG ZHONGTAI Import and Export Co., Ltd.
 - xxvi. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.
 - xxvii. Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.
 - xxviii. PT. Rajha Cemerlang Berkarya
 - xxix. KEM ONE - Siège social
 - xxx. China Chlor-Alkali Industry Association
 - xxxi. Tianjin LG Bohai Chemical Company Limited
 - xxxii. Hanwha Solutions Corporation
 - xxxiii. CV Aurora Impex
 - xxxiv. M/s Sankhla Industries
 - xxxv. Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - xxxvi. Midas Polychem LLP”
 - xxxvii. Canadian Speciality Vinyls
 - xxxviii. The Plastics Export Promotion Council
 - xxxix. Organization of Plastic Processor of India
 - xl. The All India Plastics Manufacturers’ Association
 - xli. Sree Exim
 - xlii. Indian Vinyl Council
- d. In response to the initiation notification, the following producers / exporters filed a response to exporters’ questionnaire
- i. CGPC Polymers Corporation
 - ii. China General Plastics Corporation
 - iii. Chiping Xinfu Polyvinyl Chloride Co., Ltd.
 - iv. CNSIG Inner Mongolia Sodium Industry Co., Ltd.
 - v. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.

- vi. Farnosa Plastics Corporation
 - vii. Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.
 - viii. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.
 - ix. Ordos Junzheng Energy & Chemical Co., Ltd.
 - x. Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.
 - xi. Shandong Zinfa Import & Export Co., Ltd.
 - xii. Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.
 - xiii. Tianjin LG Bohai Chemical Company Limited
 - xiv. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd.
 - xv. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.
 - xvi. PT. Rajha Cemerlang Berkarya, Indonesia
 - xvii. Hanwha Solutions Corporation, Republic of Korea (South Korea)
- e. Further, the following parties have made submissions in response to the initiation notification:
- i. Taipei Economic and Cultural Center in India, Taiwan
 - ii. The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
 - iii. Trade and Economic Section, Delegation of the European Union to India
 - iv. Trade Interests and Remedies Division, Department of Foreign Trade, Thailand,
 - v. General Authority of Foreign Trade, The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
 - vi. Director of Trade Defense, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade Indonesia
 - vii. The Ministry of International Trade & Industry, Government of Malaysia
 - viii. Embassy of Mexico in India, New Delhi
 - ix. AGC Vinythai Public Company Limited
 - x. Pt. Nas Barakah International
 - xi. CV Aurora Impex
 - xii. Indian Vinyl Council
 - xiii. China Chlor-Alkali Industry Association
 - xiv. Organization of Plastics Processors of India
 - xv. The All India Plastics Manufacturers' Association
 - xvi. The Plastics Export Promotion Council
- f. Two importers, namely Sree Exim and Sankhla Industries have filed submissions or response to importers' questionnaire issued by the Authorised Officer.
- g. The Authorised Officer has considered the most recent period as 1st January 2022 – 30th June 2022 and the period of investigation covered 1st April 2019 – 30th June 2022.
- h. A list of interested parties was published on the DGTR website to enable access of all non-confidential version (NCV) submissions made by all interested parties. All interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email.
- i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authorised Officer provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 31st October 2022 through Digital Video Conferencing. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. The following interested parties had filed written submissions and rejoinder submissions post the oral hearing
- i. China Chlor-Alkali Industry Association
 - ii. CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
 - iii. Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.

- iv. Ministry of Trade Republic of Indonesia
- v. Ordos Junzheng Energy & Chemical Co., Ltd.
- vi. Organization of Plastic Processor of India
- vii. Shaanxi Beiyun Chemical Industry Group Co., Ltd.
- viii. Taipei Economic and Cultural Center in India
- ix. The All India Plastics Manufacturers' Association
- x. The Plastics Export Promotion Council
- xi. Trade and Economic Section, EU
- xii. Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd.
- xiii. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.
- j. The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are substantiated with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authorised Officer in these final findings.
- k. The Authorised Officer, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent deemed necessary and possible.
- l. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authorised Officer has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- m. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authorised Officer has considered such party as non-cooperative and has recorded these final findings on the basis of the facts available.
- n. *** in the non-confidential version of the final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authorised Officer under the Rules.
- o. The exchange rates adopted by the Authorised Officer for the subject investigation is US\$ 1 = ₹ 76.92
- p. Request was made to the Director General (Systems) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and the period of investigation.
- q. The recommendations of the Authorised Officer may be imposed by the Central Government through Ministry of Commerce & Industry vide notification in the official gazette under sub-section (1) of Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

C. APPLICABLE LEGAL PROVISIONS

- 4. Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 provides for the imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions if goods are imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
- 5. The Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 have been notified under powers conferred by Section 9A(3) to provide for the manner in which goods, the import of which shall be subject to quantitative restrictions, may be identified and the manner in which serious injury or threat of serious injury due to surge in imports in relation to such goods may be determined.
- 6. Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade and the WTO Agreement on Safeguards establishes the rules for the application of safeguard measures by the WTO Members.
- 7. The investigation has been conducted in accordance with the said provisions of the Act and the Rules and the final findings are recorded through this notification.

D. SOURCE OF INFORMATION

- 8. At the time of the initiation of investigation, the applicants had submitted information regarding increased imports and injury to the domestic industry for the period April 2018 to March 2022. However, the Authorised

Officer decided – while issuing the initiation notification – that the period of investigation will be from 1st April, 2019 to 30th June 2022. The domestic industry has provided relevant information (imports and injury data) for the period April 2019 to June 2022 in response to the initiation notification. The domestic industry has also provided injury information for the period July-September 2022 vide email dated 18th January 2023; a non-confidential version of the same was circulated to all interested parties vide their email dated 19th January 2023. Since the applicants claimed that increased imports of the product during the present surge period were threatening serious injury to the domestic industry, the Authorised Officer has considered it appropriate to analyse the injury information for the period July-September 2022 in order to evaluate the effect of increased imports on the performance of the domestic industry.

9. The Authorised Officer called import data from Director General (Systems) data in order to verify the data submitted by the domestic industry for the period 01.04.2018 to 30.06.2022. The Director General (Systems) data was received and considered. The Authorised Officer has relied on the import data received from the Director General (Systems) for the purpose of the present investigation.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

E.1.Submissions by the other interested parties

10. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and the like article.
- a. The Authorised Officer must clarify the scope of the product under consideration since the initiation notification and the application create a confusion regarding the same.
 - b. Segregation of subject goods based on RVCM content is incorrect as PVC Suspension Grade is not categorized based on RVCM content globally.
 - c. Different countries have different standards for RVCM content. Chinese and American goods have the same standard, which is fixed at 5 PPM.
 - d. PVC Suspension Resins with more than 2 PPM and less than 2 PPM of RVCM are directly competing and have been treated as like article.
 - e. Exclusion of PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process, based on technology cannot be a factor for exclusion of a product, as held in past investigations.
 - f. RVCM content should be assessed based on test report or certificate of analysis submitted by importers with the Indian Customs.
 - g. The applicants have made contradictory statements, wherein they have relied on certificate of analysis to identify RVCM content in goods, while also claiming that such certificate should not be considered.
 - h. Responding exporters have not produced or exported PVC Suspension above 2 PPM of RVCM, as can be seen from the certificate of analysis filed.
 - i. The Authorised Officer may conduct onsite verification to verify actual RVCM content in goods produced by Chinese producers.
 - j. VCM content should not be assessed based on national standard fixed by China but should be assessed based on test report or certificate of analysis submitted by importers with Indian Customs.
 - k. While countries have fixed benchmark for RVCM content, including China which has fixed benchmark of 5 PPM, the goods produced and exported by Chinese and other producers is usually less than 2 PPM.
 - l. Merely because the specification sheet says less than 5 PPM, it does not automatically mean that the imported product is of more than 2 PPM.
 - m. It was also submitted that upon reviewing the DG Systems data provided by the Authorised Officer for all the above cited producers/exporters, it is noted that the HS Code (CTH) is 39041020 only. Whereas, we understand that PVC Suspension Resin is imported under multiple HS Codes such as 39041090, 39042110, 39042190, 39042200, etc. Sample screenshots from various publicly available data are being provided.

E.2.Submissions by the domestic industry

11. The following submissions were made by the applicants with regard to the scope of the product under consideration and like article.

- a. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported into India as they both compete in the same market, are used to manufacture the same products, and are used by customers interchangeably.
- b. Even if the product produced by the domestic industry is not considered as like product, it is still a 'directly competitive product' which closely resembles the characteristics of the product under consideration.
- c. Contrary to the submissions of the other interested parties, the scope of the product under consideration needs no clarification. None of the producers from the European Union have asked for clarification of the scope and the submission has been made only by the Trade and Economic Section, European Union.
- d. The product under consideration is mainly imported from China PR, whereas PVC Suspension Resins with residual VCM upto 2 PPM is imported from other countries and produced in India.
- e. Contrary to the submissions of the other interested parties, PVC Suspension Resins have been classified by the Government of India by forming BIS Standards IS 17658:2021. The standards notified by other countries are not important as the product has been defined with regard to the Indian standards.
- f. As per the specification sheets, some producers from China PR have RVCM content upto 2 PPM but most of the producers have RVCM content above 2 PPM.
- g. Categorization based on RVCM content is justified as it plays an important role for the product, as evident from the fact that standards of various countries, as well as websites, specification sheets and certificate of analysis contain it.
- h. The other interested parties have made contradictory submissions as they have stated that the product under consideration cannot be categorized based on RVCM content. However, they have also stated that the different countries have prescribed different standards for RVCM content.
- i. Contrary to the submissions of the other interested parties, specification sheets show the products produced by the company and not the standards established by the Government.
- j. Certificate of analysis is not relevant as it is issued for only one lot or batch produced or consignment shipped, and not the product generally produced by the producer. In case a certificate of analysis shows RVCM above 2 PPM, it is definitive evidence of production of product under consideration. However, a certificate of analysis showing RVCM upto 2 PPM cannot imply that the producer has always produced PVC with RVCM upto 2 PPM.
- k. Contrary to the submissions of the other interested parties, PVC Suspension Resins with RVCM upto 2 PPM is a product with lower impurity as compared to PVC Suspension Resins with RVCM above 2 PPM or between 2 PPM and 5 PPM. Since most of the countries require PVC Suspension Resins with RVCM upto 2 PPM, any producer manufacturing a product with lower impurity is likely to mention the same in its specification sheet / certificate of analysis.
- l. Only a handful of Chinese producers which account for 6.46% of total imports of PVC Suspension Resins from China PR and 7.78% of imports of the product under consideration have claimed that they produce PVC with RVCM upto 2 PPM.
- m. While Tianjin LG Bohai Chemical Co. has filed a sample certificate of analysis wherein it exported PVC Suspension Resins with RVCM upto 2 PPM, a sample is not enough to establish that it always exports PVC with RVCM upto 2 PPM. In any case, the exporter has exported miniscule volumes which will not impact the total imports of product under consideration in India.
- n. Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Limited, which produces the product under consideration (above 2 PPM), has not participated in the present investigation while its subsidiary which has exported negligible volumes has participated.
- o. Contrary to the submissions of other interested parties, the applicants have provided the information reasonably available to them in order to prove that a number of producers are exporting PVC suspension resins with RVCM above 2 PPM and such imports have surged.
- p. PVC produced through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process are not PVC suspension resins and were treated as different products in previous investigation. As regards exclusion of bulk mass polymerization, the domestic industry has submitted that the Authorised Officer for Advance Rulings vide its order dated 01.04.2016 decided that the PVC Mass Resin Polymerization Grade will not attract anti -dumping duties imposed of PVC-SR vide Customs Notification dated 13.06.2014 which is based on the recommendations of the Designated Authorised Officer issued vide notification no.14/1012/2012-DGAD dated 04.04.2014.

E.3. Examination of the Authorised Officer

12. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

"The product under consideration in the present investigation is "Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Resins with Residual Vinyl Chloride Monomer (RVCM) above 2 PPM".

The petitioners have categorized PVC suspension resin into two categories - (a) PVC suspension resin with residual VCM above 2 PPM and (b) PVC suspension resin with residual VCM below 2 PPM. The petitioners have justified the definition of the product under consideration on the basis of Residual VCM content by referring to the BIS standards. The BIS standard IS 1765 8: 2021 states as follows:

"RVCM content of PVC-SR and PVC-PR shall not exceed 2 PPM, However, RVCM content of PVC-SR shall not exceed 5 PPM when manufactured by mass/bulk polymerization process. RVCM content shall be tested in accordance with IS 10151 /ISO 24538."

PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration. The following types of PVC resins are specifically excluded from the scope of the product under consideration:

- a. PVC Suspension Resins with Residual VCM below 2 PPM*
- b. Cross-linked Poly Vinyl Chloride*
- c. Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC)*
- d. Vinyl Chloride Vinyl Acetate Copolymer (VC-Vac)*
- e. Poly Vinyl Chloride Paste Resin*
- f. Poly Vinyl Chloride Blending Resin"*

13. The Authorised Officer notes that the applicants have requested classification of PVC Suspension Resin into two categories - (a) PVC Suspension Resin with residual VCM **above** 2 PPM and (b) PVC suspension resin with residual VCM **upto** 2 PPM. At the stage of the initiation of the investigation, the Authorised Officer examined the import trends of PVC Suspension Resins with residual VCM **upto** 2 PPM and **above** 2 PPM separately. The Authorised Officer noticed that there was no sudden, sharp and significant increase in imports of PVC Suspension Resins with residual VCM **upto** 2 PPM. Therefore, it was noticed that imports of PVC Suspension Resins with residual VCM **upto** 2 PPM did not *prima facie* satisfy the requirements necessary for the initiation of a safeguard investigation and subsequent imposition measure under the Rules. The Authorised Officer therefore decided to exclude PVC Suspension Resins with Residual VCM **upto** 2 PPM from the scope of the PUC.
14. On the other hand, the Authorised Officer noticed that imports of PVC Suspension Resins with residual VCM **above** 2 PPM were recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough¹ to warrant the initiation of the current investigation. Therefore, having *prima facie* satisfied himself regarding the existence of sudden, sharp and significant surge in imports of PVC Suspension Resins with RVCM **above** 2 PPM, the Authorised Officer has initiated the present investigation pursuant to Rule 5 of the Rules with respect to PVC Suspension Resins with residual VCM **above** 2 PPM only.

E.3.1. Legal Standard for the defining scope of the product under consideration

15. The Authorised Officer notes that the Agreement on Safeguards, the Foreign Trade Development Act and the Safeguards (Quantitative Restrictions) Rules do not provide any guidance on the manner in which the 'product under consideration' for any investigation must be defined. Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 only refers to "*any goods*" that are imported into India in increased quantities. Similarly, the Safeguards Agreement refers only to "*a product*" and stipulates that the safeguard measures must be applied to the "product being imported" irrespective of its source.² In the WTO dispute of Dominican Republic –Safeguard Measures,³ the investigating Authorised Officer therein had defined the product under consideration as polypropylene bags (the end product) and polypropylene tubular fabric (the input product for polypropylene bags). Although two different product segments were included within the definition of the product under consideration, the Panel held that there are no irregularities in the definition of the product under

¹ See Paragraph 131, Appellate Body Report, *Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear*, [WT/DS121/AB/R](#), adopted 12 January 2000, (hereinafter *Argentina – Footwear (EC)*). The Appellate Body observed that a pre-requisite for the imposition of the safeguard measure is that the increase in imports must be "*recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough*".

² Paragraph 7.177, Panel Report, *Dominican Republic – Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric*, [WT/DS415/R](#), [WT/DS416/R](#), [WT/DS417/R](#), [WT/DS418/R](#), and Add.1, adopted 22 February 2012 (hereinafter "*Dominican Republic – Safeguard Measures*")

³ *Ibid.*

consideration since there “is no provision in the Agreement on Safeguards that governs the selection, description, analysis or determination of this “product””⁴ and “the Agreement on Safeguards does not impose specific obligations with respect to the definition or the scope of the product under investigation.”⁵

16. The observations of the Panel in Dominican Republic – Safeguard Measures were re-iterated by the Panel in EU – Safeguard Measures on Steel (Turkey),⁶ wherein the European Union imposed safeguard measures on a range of different product categories through a single investigation. The Panel in this dispute noted that there were no inconsistencies with the wide definition of the scope of the product under consideration adopted by the European Commission. The Panel observed:

7.34. It is also worth noting what the provisions considered in this section do not discipline, namely the choice of the product under investigation, in itself. These provisions do not set out rules for selecting the product under investigation, and for example they do not prevent a Member from including a range of products in a single investigation. We thus agree with the panel in Dominican Republic – Safeguard Measures that while the Agreement on Safeguards requires the authority to define the product under investigation, it does not set out requirements such as restricting the product under investigation “solely to those products that are like or directly competitive with each other”.

17. The above WTO panel reports make it clear that an investigating authority has the discretion to define the product under consideration, and the Agreement on Safeguards does not discipline the choice of the product under consideration adopted by the Authority. In the above two WTO disputes, the Panel held that the Agreement on Safeguards does not prohibit the adoption of a wide definition of a product under consideration. Therefore, by logical extension, the Authorised Officer considers that there are no restrictions in adopting a narrow definition of a product under consideration.
18. In view of the above decisions and legislation, the Authorised Officer has a discretion while defining the PUC. The Authorised Officer notes that RVCM content classification is one of the criteria since BIS standards in India including other country’s specifications distinguishes based on this criteria. The purpose of the safeguard measures is to put a check on surge of imports which are injuring the domestic producers. In the facts of the present investigation, the Authorised Officer has distinguished the product based on RVCM content and has defined the PUC as PVC Suspension Resins with RVCM content above 2PPM as it was only this product category in which a sudden, sharp and significant surge of imports was observed. Therefore, the contention that the PUC cannot exclude PVC Suspension Resins with RVCM content upto 2PPM cannot be accepted.
19. The Authorised Officer believes that including PVC Suspension Resin with RVCM **upto 2** PPM would result in granting unnecessary protection to that segment of the Indian industry that is not suffering serious injury on account of a sudden, sharp and significant surge in imports. Therefore, the Authorised Officer proposes to consider that adopting a narrow scope of the product under consideration by restricting the PUC to PVC Suspension Resin with RVCM **above 2** PPM ensures that no excessive protection is granted to a segment which is outside the scope of the investigation.

E.3.2. “Like and directly competitive products” under the Agreement on Safeguards and “like goods” under the Safeguard Measures (QR) Rules 2012

20. Having defined the scope of the product under consideration, the Authorised Officer now turns its examination towards the examination of the goods produced by the domestic industry and whether it can be covered within the scope of the present investigation. The Authorised Officer notes that the PUC excludes PVC Suspension Resin with RVCM **upto 2** PPM, whereas the domestic industry manufactures PVC Suspension Resin with RVCM **upto 2** PPM but not **above 2** PPM.
21. As per Article 2.1 of the Agreement on Safeguards, the ‘domestic industry’ in a safeguard investigation need not be the producer of the product under consideration, but may be the producer of ‘like and directly competitive products’. Article 2.1 of the Agreement on Safeguards reads as under:

*A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that **such product** is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces **like or directly competitive products**.*

⁴ Ibid., paragraph 7.177

⁵ Ibid., paragraph 7.181

⁶ Panel Report, *European Union – Safeguard Measures on Certain Steel Products*, [WT/DS595/R](#) and Add.1, adopted 31 May 2022 (hereinafter “*EU – Safeguard Measures on Steel (Turkey)*”).

22. The above provision uses the terms ‘*such products*’ while referring to the imported goods (i.e. the product under consideration), but uses the words ‘*like and directly competitive products*’ while referring to the goods produced by the domestic industry. In other words, a safeguard measure may be imposed on products, if a surge in imports of *such product* causes serious injury to the domestic industry that is producing ‘*like and directly competitive products*.’ The WTO Panel, in the dispute of US – Safeguard Measure on Washers,⁷ has observed that there need not be a match between the ‘product under consideration’ and ‘like and directly competitive products.’ The Agreement on Safeguards does not mandate that the domestic industry must be the producers of the product under consideration only, but may include the producers that are producing ‘like and directly competitive products’:

We agree with Korea that the definition of the domestic industry affects subsequent stages of an investigating authority's determination (such as the serious injury and causation determinations). However, the Agreement on Safeguards provides a specific definition of the domestic industry in Article 4.1(c), and requires that the subsequent stages of the investigation be conducted based on a domestic industry defined in accordance with this provision. Neither Article 4.1(c) nor any other provision of the Agreement on Safeguards (including the provisions governing the subsequent conduct of the investigation, such as Articles 4.2(b) and 4.2(c)), impose any additional requirements precluding what Korea describes as a 'mismatch' between the PUC and the domestically produced good. Article 4.1(c) requires that the domestic industry be defined on the basis of producers of goods that are 'like or directly competitive' with the PUC. To the extent the domestic industry is defined based on the producers of like or directly competitive products, there is no additional requirement under Article 4.1(c) for a 'match' between the PUC and the domestically produced good. Indeed, accepting Korea's position would mean that the investigating authority would have to exclude a producer of like or directly competitive goods from the scope of the domestic industry because the domestic product, while like or directly competitive, is essentially not the same as (or to use Korea's words, does not 'match') the goods included in the PUC. This is at odds with the text of Article 4.1(c). We consider that if Article 4.1(c) were intended to preclude investigating authorities from defining the domestic industry on the basis of goods that are like or directly competitive but not a 'match', the provision would have been drafted differently.”⁸

23. The above legal proposition is also recognised in Section 9A(4) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, wherein the domestic industry is defined as:

"domestic industry" means the producers of goods (including producers of agricultural goods

(i) as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or

(ii) whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;

24. The Authorised Officer notes that as per Section 9(A)(4) of the Act, read with the Agreement on Safeguards, the domestic industry must be the producers of ‘*like goods or directly competitive goods*’ in India (either whole of the production or major share of production). The product under consideration is PVC Suspension Resin with RVC content **above** 2 PPM and like article manufactured by the domestic industry is PVC Suspension Resin with RVC content **upto** 2 PPM.

E.3.3. Products produced by the domestic industry are directly competitive and substitutable with the product under consideration

25. The Authorised Officer notes that the determination of whether products are ‘like’ is fundamentally ‘a determination about the nature and extent of a competitive relationship between and among products.’⁹ The domestic industry has stated that the subject goods are commonly used in manufacturing various products like pipes and fittings, flexible hoses, films/sheets, bottles, profiles, wire and cables, footwears, etc. PVC with residual VCM below and above 2 PPM are interchangeably used by the consumers in different segments. The Indian industry is not aware of any segment which cannot use PVC with residual VCM below and above 2 PPM interchangeably. Similarly, the questionnaire response filed by the exporters from China PR also mentions that there is no known difference in the subject goods produced by China PR (above 2 ppm) and PVC Suspension Resin produced by the Indian Industry and exported from other countries (upto 2PPM). PVC Suspension Resin produced by the domestic industry and imported from China PR and other countries are

⁷ Panel Report, *United States – Safeguard Measure on Imports of Large Residential Washers*, [WT/DS546/R](#) and Add.1, adopted 28 April 2023 (hereinafter “*US – Safeguard Measure on Washers*”).

⁸ *Ibid.*, paragraph 7.51.

⁹ Panel Report, *US – Safeguard Measure on Washers*, paragraph 7.55.

comparable in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, function and uses, product specifications etc. PVC Suspension Resins with less than 2 PPM of residual VCM and with more than 2 PPM of residual VCM contents are technically and commercially substitutable.

26. The Authorised Officer notes that the domestic industry and other interested parties are in agreement on the fact that PVC Suspension Resin with residual VCM upto 2 PPM and above 2 PPM are technically and commercially substitutable. The Authorised Officer notes that PVC Suspension Resin upto 2 PPM produced by the domestic producers and supplied from various countries are comparable to the product under consideration, despite a difference in the residual VCM content. The other interested parties contended that resin upto 2 PPM goods produced by the domestic producers and supplied from various countries and resin above 2 PPM are used in the same manner, for the same purpose and consumed interchangeably by the consumers. Barring the RVC content, there is no known difference in the resin upto 2 PPM and resin above 2 PPM. The two product categories are comparable in terms of physical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods.
27. While PVC Suspension Resins upto 2 PPM and above 2 PPM are used interchangeably and for the same purpose, there was a difference in pricing behaviour of both the products during the present surge period, leading to surge in imports of PVC Suspension Resins with RVC content *above* 2 PPM only. Considering that the Resin with RVC upto and above 2 PPM are technically and commercially interchangeable and the consumers have used and are using the two interchangeably, the Authorised Officer holds that resin with RVC upto 2 PPM manufactured by the domestic producers and imported into India constitutes '*like goods*' (and directly competitive) to the PVC suspension resin with RVC above 2 PPM being imported into India in terms of Rule 2(e) of the Rules.
28. The All India Plastics Manufacturers' Association (AIPMA) stated that since the products upto 2 PPM and above 2 PPM are like articles, the economic analysis may be done in relation to PVC Suspension Resin as a whole, without any bifurcation of residual VCM. The Authorised Officer notes that the surge in imports has been found only in case of PVC Suspension Resin with RVC above 2 PPM. The Authorised Officer has therefore excluded PVC Suspension Resin with RVC upto 2 PPM from the definition of the product under consideration. The Authorised Officer has examined the increase in imports of the product under consideration, and its impact on the domestic industry. Wherever necessary, the Authorised Officer has examined the import trends of PVC Suspension Resin with RVC upto 2 PPM, and its impact on the domestic industry also.

E.3.4. Claims regarding the RVC content reported by the exporters

29. Certain other interested parties have contended that the RVC content should not be verified based on the national standards but on the certificate of analysis. The Authorised Officer notes that various countries have prescribed different standards of RVC content for PVC Suspension Resins. However, the producers have created and maintained their production facilities based on their own internal standards and needs. It is noted that the Government of China has notified RVC below 5 PPM as the relevant standard. However, it is to be noted that this standard is not mandatory. While some Chinese producers have notified their product as resin with RVC upto 2 PPM, some have notified as resin with RVC below 5 PPM. A producer is free to adopt specifications (within the mandatory range prescribed by the government) as deemed appropriate by the producer.
30. The Authorised Officer has considered whether the certificate of analysis could be adopted as a relevant document to establish RVC contents in the imports reported during the injury period in order to segregate imports of the product into two categories. The Authorised Officer had initiated the investigation vide notification dated 16.09.2022. All the concerned exporters in different countries were required to respond to the initiation notification and provide documents in support of their claim of whether they are exporting PVC Suspension Resin with RVC upto 2 PPM or otherwise. However, only few exporters from China PR have submitted their response.
31. The Authorised Officer notes that specification sheets filed by the cooperating producers/exporters contain pertinent information regarding various relevant technical parameters of the product, as publicly declared by a producer. Specification sheet is a document generally used by producers to communicate to the prospective customers the specifications of the product that a producer produces and sells in the market. The customers buy the material based on the specifications published by the producers in the specification sheet, whereas certificate of analysis is merely a reflection of the product that has actually been supplied. The consumers place the order and negotiate the price based on declared or notified specifications of the product. A non-compliance of a certificate of analysis with specification sheet can allow a buyer to reject the material purchased from the producer. However, a buyer cannot reject receipt of material if the specifications conform to the specification sheets. Certain other interested parties have contended that the specification sheets characterizing PVC Suspension Resin imports with RVC less than 5 PPM does not necessarily mean that those imports are necessarily of PVC Suspension Resin RVC above 2 PPM.

32. The Authorised Officer is required to make its determination on the basis of facts on record of the case. While some of the interested parties have contended that less than 5 PPM does not mean above 2 PPM. The exporters which had reported their exports as PVC Suspension Resins with RVCM below 5PPM were given an opportunity to provide evidence to demonstrate that their exporter were in fact of PVC Suspension Resins with RVCM upto 2PPM. The Authorised Officer has accepted this evidence wherever provided.

E.3.5. Claims regarding the exclusion of PVC Resins manufactured through other processes

33. Some of the interested parties have contended that classification of the PUC is not clear, and exclusion of PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process, based on technology cannot be a factor for exclusion of a product, as held in past investigations.
34. The Authorised Officer notes that as per the definition of the PUC in the initiation notification, PVC Suspension Resins produced through mass/bulk suspension process were excluded from the scope of the PUC. Subsequent to the initiation of the investigation, the producers/exporters have provided information on the basis of the PUC defined in the initiation notification. However, till such a stage none of the parties contended the exclusion of mass/bulk polymerization PVC from the PUC. It was only at a later stage that the interested party has submitted that exclusion of the PUC on the basis of difference in production process is not permissible. However, these interested parties have not provided any evidence to show that PVC Suspension Resin produced through other processes is one and the same, with the same product characteristics.
35. In view of above, Product Under Consideration (PUC) for the present investigation is rightly defined in the initiation notification as below:

"The product under consideration in the present investigation is "Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Resins with Residual Vinyl Chloride Monomer (RVCM) above 2 PPM".

The petitioners have categorized PVC suspension resin into two categories - (a) PVC suspension resin with residual VCM above 2 PPM and (b) PVC suspension resin with residual VCM below 2 PPM. The petitioners have justified the definition of the product under consideration on the basis of Residual VCM content by referring to the BIS standards. The BIS standard IS 1765 8: 2021 states as follows:

"RVCM content of PVC-SR and PVC-PR shall not exceed 2 PPM, However, RVCM content of PVC-SR shall not exceed 5 PPM when manufactured by mass/bulk polymerization process. RVCM content shall be tested in accordance with IS 10151 /ISO 24538."

PVC Resins manufactured through bulk mass polymerization, emulsion polymerization and micro suspension polymerization process are excluded from the scope of the product under consideration. The following types of PVC resins are specifically excluded from the scope of the product under consideration:

- a. PVC Suspension Resins with Residual VCM below 2 PPM*
- b. Cross-linked Poly Vinyl Chloride*
- c. Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC)*
- d. Vinyl Chloride Vinyl Acetate Copolymer (VC-Vac)*
- e. Poly Vinyl Chloride Paste Resin*
- f. Poly Vinyl Chloride Blending Resin"*

36. Whereas *PVC Suspension Resin with Residual RVCM above 2PPM* is the product under consideration for the present investigation, *PVC Suspension Resins with Residual VCM upto 2 PPM* constitutes 'like goods' in terms of Rule 2(e) of the Rules and 'like or directly competitive products' in terms of the Agreement on Safeguards.
37. The Authorised Officer has noted that there appears to be a mismatch between the import data reported by certain cooperating exporters/producers, and the DG Systems data. The Authorised Officer vide email dated 28th April 2023, provided an opportunity to the interested parties to explain the reason for mismatch in the data and correlate their data with the DG Systems data. The producers/exporters, vide reply dated 2nd May 2023, stated that while the Authorised Officer has considered only one HS Code, the exports have been made under four HS Codes, that is, 39041090, 39042110, 39042190 and 39042200. The submission that imports are made under four HS codes was supplied to the Authorised Officer as late as on 2nd May 2023, i.e. almost at the end stage of the investigation. However, the producers/exporters/traders had sufficient opportunity prior to this period as initiation notification mentioned single HS code, NCV of the petition supplied to the interested parties mentioned single HS code. Even neither in oral hearing, nor through written submission or rejoinders, this issue was ever raised. Hence, being the time bound investigation, the Authorised Officer is constrained to not entertain such a claim at such a belated stage of the investigation. It is further noted that the party raising

the above contention had filed in its response earlier that it is only exporting PVC suspension paste resin with RVCM content upto 2PPM, however, later on through its submission, the party contended that the data filed with the Directorate contains information about both the PUC and the Like article. This is self-contradictory and in view of the same the assertions/contentions submitted by the interested party loses its credence.

38. The Authorised Officer notes that these producers/exporters have also stated that they have reported all transactions of PVC Suspension Resins immaterial of RVCM content. The Authorised Officer notes that the exporter had earlier claimed that it produces and exports only PVC Suspension Resins upto 2 PPM which is self-contradictory. In view of the above and due to the mismatch in the data reported by the certain producers/exporters, and in the absence of any justified clarification thereto as to the reasons for the mismatch, the Authorised Officer has considered the import data as per DG Systems.

F. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

F.1. Submissions by the other interested parties

39. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing.
- The applicants account for only 25-30% share in Indian production during the period of investigation and even less during the injury period, leading to suspicion that such figure may be manipulated for such producers to be considered as domestic industry.
 - It must be considered that while the major share is held by the other Indian producers, they are not there before the Authorised Officer claiming injury.

F.2. Submissions by the domestic industry

40. The following submissions were made by the applicants with regard to the domestic industry and standing.
- The petition for imposition of safeguard measures was filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited which account for [27]% of the domestic production in India. Since the production by the applicants constitutes a major share in the domestic production, they constitute domestic industry.
 - All other domestic producers, that is, DCM Shriram, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited have filed support letters.
 - Imposition of measures is also supported by the Chemical and Petrochemical Manufacturers' Association.
 - Since there are no producers of the product under consideration in India, the producers of PVC Suspension Resins with RVCM upto 2 PPM alone can constitute domestic industry.
 - Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicants have provided actual information relating to the production of the like article by all domestic producers in India. Such information has been filed by the domestic producers in their support letter.
 - As opposed to the contention of the other interested parties, the applicants cannot force any other domestic producer to participate in the investigation.
 - The injury to other domestic producers is not relevant as the Authorised Officer is required to analyze injury to only the defined domestic industry.

F.3. Examination of the Authorised Officer

41. The Authorised Officer notes that there is no *per se* 'standing test' under the Agreement on Safeguards, the FT(DR) Act and the Safeguards (QR) Rules. However, the Agreement on Safeguards and the FT(DR) Act defines the domestic industry as the producers as a whole of the like or directly competitive goods or those whose collective output of the like or directly competitive goods constitute a major share of the total domestic production of the said goods in India.¹⁰
42. According to Section 9A4(b) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 –
- “(b) domestic industry means the producers of goods (including producers of agricultural goods) –*
(i) as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or
(ii) whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India.”
43. Similarly, as per Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards, a domestic industry is defined as “*the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a Member, or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.*”

¹⁰ Article 4.1(c), Agreement on Safeguards and Section 9A(4)(b), Foreign Trade (Development and Regulation) Act).

F.3.1. Legal Standard for the definition of the ‘domestic industry’

44. The Authorised Officer notes that in US – Safeguard Measures on Washers, the WTO Panel observed that the domestic industry may either be the producers as a whole of the like or directly competitive products, or (b) the producers whose collective output of the like or directive competitive product constitutes a major proportion of the total domestic production within the meaning of ‘major proportion’ of the total domestic production of those products.¹¹

F.3.2. ‘Major Proportion’ of the total domestic production in the instant investigation

45. The present application was filed by Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCW Limited. Apart from the applicants there are three other domestic producers in India, namely, DCM Shriram Limited, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited. The other domestic producers as well as the association of domestic producers, namely, Chemicals and Petrochemicals Manufacturers’ Association have supported the request for imposition of safeguard measures on imports of PVC with RVCM above 2 PPM into India. Therefore, the application filed by the applicants has the support of 100% of the producers of the like product in India. At the stage of initiation, the Authorised Officer noted that the applicants account for a major proportion of the production of subject goods in India and thus, constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.
46. Some interested parties have contended that the major share of domestic production is held by other producers which are not before the Authorised Officer. The applicants have submitted that their total production constitutes [***] of the total domestic product of the like goods in India. It has also been contended that apart from the applicants, there are three other domestic producers of the ‘like goods’, all of who have supported the petition. The Authorised Officer notes that given that the petitioners account for more than [***] of the production in India out of a total of 5 producers of the ‘like goods’, their production therefore constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article (like goods) in India. Further, the application is supported by all the other Indian producers of the like article (like goods). The application has the support of 100% of the total domestic production in India, and therefore satisfies the standing test.
47. The Authorised Officer issued the notice of initiation and advised all the interested parties to participate in the investigation and provide relevant information. There is no evidence on record to show that the performance of other domestic producers not forming part of the petition has behaved very differently as compared to the performance of the petitioners. The interested parties have not established that non-inclusion of other domestic producers has caused material distortions in the injury claims.
48. In view of the foregoing and having regard to the Rules, the Authorised Officer determines that the production of the petitioners account for a major share in the Indian production, and therefore, petitioners constitute domestic industry within the said Rules.

G. CONFIDENTIALITY**G.1.Submissions by the other interested parties**

49. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the confidentiality.
- a. The applicants have not provided data with respect to various economic parameters, for the most recent period, 1st April 2021 to 30th June 2022, in the non-confidential version of petition, due to which the interested parties are not able to make submissions.

G.2.Submissions by the domestic industry

50. The following submissions were made by the applicants with regard to the confidentiality.
- a. The applicants have provided and circulated the non-confidential version of the application with the most recent data.

G.3.Examination of the Authorised Officer

51. In accordance with Rule 7 of the Rules, information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authorised Officer has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been treated confidential and not disclosed to other interested parties. The parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. In view of Rule 6(7) of the Rules, all the interested parties were advised to circulate the non-confidential version of the submissions made before the Authorised Officer to all the other interested parties participating in the investigation.

¹¹ Panel Report, US – Safeguard Measure on Washers, para. 7.75.

52. Some interested parties contended that the petitioners have not provided the data with respect to various economic parameters for the most recent period. The Authorised Officer notes that the domestic industry has circulated the non-confidential version of the data regarding the economic parameters of the domestic industry on 27th October 2022. These interested parties were allowed opportunity to comment on the same, and these comments have been appropriately considered in the present determination.

H. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

H.1.Submissions by the other interested parties

53. The following submissions were made by the other interested parties with regard to miscellaneous issues.
- The initiation of investigation is not appropriate as the applicants did not bring forth substantive evidence, and insufficient scrutiny was conducted by the Authorised Officer.
 - Approximately 30% members of OPPI fall under MSME category, and find it difficult to participate individually. Nearly, 45% of the processing of the polymers in India is done by the members of OPPI.
 - 90% of the members of AIPMA belong to the MSME sector, and it represents the interests of the users and importers.
 - Plexconcil is an association representing the interests of the importers and end-users of the subject goods from China PR and thus, constitutes an interested party in the present investigation.
 - CCAIA is participating pursuant to being approached by 11 Chinese producers interested in participating in the investigation.
 - The producers/exporters from China PR are mainly exporting the goods less than 2 PPM, and have provided complete technical information in this regard in their response, including the certificate of analysis.
 - Since there is no specific HS code for product under consideration, the notation “ex” should be used in front of the HS Code to indicate that only part of such HS Code is covered in the present safeguard investigation.
 - The measures, if recommended, should be based on average of imports in the last three years and the adequate impact of increase in demand of the subject goods every year in the Indian market.
 - Developing countries including Mexico, Saudi Arabia and Thailand should be excluded from the scope of the proposed measure.

H.2.Submissions by the domestic industry

54. The following submissions were made by the applicants with regard to miscellaneous issues.
- The other interested parties have not highlighted any parameter which is insufficient for initiation of the investigation. The Authorised Officer has initiated the present investigation after *prima facie* satisfaction regarding increased imports, injury and causal link.
 - OPPI should not be treated as an interested party as the association has not taken permission from its members to participate in the present investigation. The Authorised Officer may check the minutes of the meeting submitted by OPPI. One of the domestic producers of the product under consideration is also a member of OPPI and does not believe that any such resolution was passed by members of OPPI.
 - AIPMA has not established that it has been authorized to participate in the present investigation by a resolution passed by its members. While it has claimed that 90% of its members are MSME, it has not clarified the number of members that are actually users of the subject goods.
 - Plexconcil should not be treated as an interested party in the present investigation as it has participated beyond its directive as per MoA, only to fulfil the business interests of some of the key functionaries. The objective of Plexconcil is to promote exports from India and not encourage imports into India. No resolution has been passed by the members of Plexconcil for participation in the present investigation.
 - The members of Plexconcil are not importers and traders of the subject goods, but are manufacturers and exporters of the downstream product, thus, it cannot be treated as an interested party in the present investigation.
 - Chemplast Sanmar Limited, Reliance Industries Limited and DCM Shriram are members of Plexconcil and confirm that no resolution was passed by the association for participation in the present investigation.
 - Plexconcil has not clarified whether its members use the subject goods as a majority input in their production process.

- h. CCAIA has not submitted its list of members. While there are 141 known producers in China, CCAIA has submitted that it has been approached by only 11 producers. It has not submitted the resolution passed by the members to participate in the present investigation and hence, should not be treated as an interested party.
- i. Since some of the participating producers have claimed that they do not export product under consideration (that is RVCM above 2 PPM), they are not interested parties under Rule 2(d), since the law allows consideration of only exporters of the product under consideration. Thus, their submissions regarding other aspects cannot be considered. The same applies for Governments of other countries, that have claimed that no PVC with RVCM above 2 PPM is exported therefrom.
- j. Since the participating exporters are not exporting the product under consideration, they cannot claim a direct or indirect impact of the proposed measures on their operations, so as to be interested in the investigation. In case there is no impact on operations, such parties can participate only after seeking permission of the Authorised Officer.
- k. While a number of associations have participated in the present investigation, none of them have proved that there was a resolution passed authorizing such participation or even that the majority of their members are exporters or importers of product under consideration, as required under Rule 2(d).
- l. The Tribunal in *Automotive Tyre Importers Association v. Designated Authority* held that an association must establish itself as an interested party, since the associations failed to discharge the onus, the Tribunal found that it cannot be considered as an interested party.
- m. Rule 6(5) does not permit participation of responding associations as it states that hearing shall be provided to industrial users and consumer associations, where the product is sold at retail level.
- n. In India, any measure is imposed based on a combined reading of the HS code and the product description. If a product, not falling within the product scope is imported under the same HS code it is automatically out of the purview of the measures.
- o. The quotas to be recommended may be based on average of imports in the last three years but excluding the surge period, that is, Q1 of 2021-22 and the most recent period and considering impact of increase in demand.

H.3.Examination by the Authorised Officer

- 55. Some interested parties contended that the present investigation should not have been initiated, as the conditions laid down under the law for initiation of investigations were not met. The Authorised Officer however holds that the present investigation was initiated based on a duly substantiated application and after *prime facie* satisfaction regarding increased imports, serious injury or threat of serious injury and causal link. A non-confidential version of the application was circulated to the interested parties. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation. Subsequent to the initiation, supporting information/evidence has been sought to the extent deemed necessary, and the same has been adopted for the present determination.
- 56. The applicants have submitted that the associations have participated in the present investigation without following a procedure expected from associations (such as seeking views from their members, minutes of meeting recording resolution of members for participation in the present investigation, and views expressed by their members with regard to present investigation). The applicants have submitted that views expressed by these associations should therefore not be considered as views of their members and should be considered as views expressed by select few members or persons of these associations. The Authorised Officer notes that considering that these associations have been well recognised in the Government and are known to be participating before various forums, it is expected that these associations have expressed the views as would constitute the views of majority of their members. The Authorised Officer has therefore considered it appropriate to address the views and concerns expressed by these association.
- 57. The applicants have strongly objected to participation of Plexconcil. The applicants have submitted that Plexconcil has participated in the present investigation without establishing whether their members at large desired the Council to oppose the proposed measures, how their members would be adversely impacted, as far as exports from India are concerned. The applicants also contended that some of the key persons in Plexconcil have their own business interests as consumers of the product and therefore have used the platform of the association available to them to oppose the proposed measure, which, according to the applicants, is inappropriate and should not be allowed. Authorised Officer notes that Plexconcil is an association formed to promote exports of plastic products from India. According to Rule 2(d), an interested party includes an exporter or a foreign producer, the Government of exporting country, a producer of like goods in India and a trade or business association, majority of members of which produce or trade like goods or directly competitive product

in India. Further, consumers of the product are already represented by their associations, viz. Organization of Plastic Processor of India and The All India Plastics Manufacturers' Association.

58. The Authorised Officer also notes that, apart from making broad assertions, Plexconcil has not provided information showing possible adverse effects of proposed measures on exports from India. It is also noted that proposed measures are only in respect of resin with RVCM above 2 PPM and the interested parties themselves contended that resin with RVCM below and above 2 PPM are interchangeably used. If the surge period is excluded, it is seen that about 90% of the imports of the product are of resin upto 2 PPM. Therefore, the measure, if imposed, may not have a significant impact on the members of Plexconcil. However, the Authorised Officer has taken note of all the submissions made by the Council and other associations and have recorded these findings after due consideration of these submissions, in the interest of justice.
59. The interested parties have submitted that the notation "ex" should be used in front of the HS Code to indicate that only part of such HS Code is covered in the present investigation. The Authorised Officer notes that any measures may be imposed considering the product description and the HS Codes. In case a product is imported under the same HS code, which does not fall within the scope of product under consideration in the present investigation, it will automatically be excluded from the scope of the measures imposed. However, in view of the submissions made by the interested parties, and as a matter of abundant precaution, the Authorised Officer clarifies that the proposed measures are only in respect of PVC suspension resin with RVCM above 2 PPM. Resin with RVCM upto 2 PPM is beyond the scope of the proposed measures.
60. With regards to the submissions that majority of Chinese producers export subject goods with RVCM less than 2 PPM and submitted their certificate of analysis, the Authorised Officer notes that the subject goods with RVCM upto 2 PPM is not the subject matter of the present investigation and thus, any producer producing / exporting PVC with RVCM content upto 2 PPM will be excluded from levy of measures in the present investigation.
61. With regards to the quotas for quantitative restrictions, the Authorised Officers has addressed the same in the relevant section of this final findings.

I. IMPORTS IN INCREASED QUANTITIES

I.1. Submissions made by the other interested parties

62. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the volume of imports into India.
 - a. Only imports from China have increased, while the total imports have declined.
 - b. Safeguard measures can be used only in exceptional circumstances and are aimed at combating the overall increase in imports. Since imports from only one country have increased, while overall imports have decreased, the criteria to impose safeguards measures is not met.
 - c. The applicants have exaggerated the increased imports of the subject goods, and deliberately invented serious injury to the domestic industry.
 - d. The claim of surge in imports is based on assumption and is factually incorrect since information submitted by Chinese exporters shows that they have not exported subject goods above 2 PPM.
 - e. The statement of imports of PVC Suspension has been presented by the applicants regardless of the RVCM content which has created ambiguity regarding the product scope considered for volume of imports.
 - f. The imports from China increased on account of shipment delays from Japan and Korea, and lower turnaround time for China. While it took 30 days to source the product from China, it was taking 75-90 days from Japan, and 60-70 days from Taiwan and Korea.
 - g. Since as per the applicants the product under consideration is produced and exported only from China, imports from Indonesia should be excluded.
 - h. The surge shown is only from China PR and thus, imports from Indonesia should be excluded from the purview of the present investigation.
 - i. There were no exports of product under consideration from Taiwan during the investigation period and thus Taiwan should be excluded.

I.2. Submissions by the domestic industry

63. The following submissions were made by the applicants with regard to volume of imports into India.

- a. The applicants have provided import data for both the product under consideration and the like article. Since both the products can be used interchangeably, the demand has been determined taking into account the imports of the product under consideration, like article and sales of like article by the domestic producers in India. However, import volume is based only on the imports of the product under consideration.
- b. The imports from Indonesia and Taiwan may be excluded in case the producers establish that the product exported by them is PVC Suspension Resins with RVCN upto 2 PPM, or that the imports from these countries are less than 3% of the imports of the subject goods.
- c. There has been a sudden, sharp and significant increase in imports into India in absolute terms as well as in relation to Indian production.
- d. There is an urgent need of imposition of measures as the imports of the product under consideration have increased significantly in the most recent period. In Q1 of 2022-23, the total imports of product under consideration are more than the total imports in 2021-22.
- e. The volume of imports in India have increased in the most recent period as compared to the previous quarters as well as the same period in the previous year.
- f. Imports of the product under consideration has increased significantly in relation to total imports into India, consumption in India, domestic sales of domestic producers and imports of PVC suspension resins with RVCN upto 2 PPM.
- g. Imports of PVC Suspension Resins in totality have also increased substantially in the most recent period.
- h. Contrary to the submissions of the other interested parties, the imports of the product under consideration as well as total imports of PVC Suspension Resins have increased in India.
- i. As opposed to the contention of the other interested parties, only the increase in imports is relevant for imposition of safeguard measures, and not the number of countries from which imports have increased.

I.3. Examination of the Authorised Officer

64. Under the provisions of Section 9A of the Act, safeguard measures may be imposed where a product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. As per Rule 2(c) of the Quantitative Restrictions Rules, “increased quantity” includes increase in import whether in absolute terms or relative to domestic production.

I.3.1. Meaning of “increased quantity”

65. As per Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992, safeguard duty may be imposed under the following conditions.

“(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any goods are imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry, it may, by notification in the Official Gazette, impose such quantitative restrictions on the import of such goods as it may deem fit :”

66. Thus, an increase in imports is the basic prerequisite for the application of a safeguard measure under the FT(DR) Act and the Safeguard (QR) Rules. Further, to determine whether imports of the product under consideration have “increased in such quantities” for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. Rule 2(c) of the Quantitative Restrictions Rules defines increased imports as under.

“(c) “increased quantity” includes increase in import whether in absolute terms or relative to domestic production;”

67. Article 2.1 of the Agreement on Safeguards permits the application of a safeguard measure only if the imports of the product are in such increased quantities in absolute and relative terms so as to cause injury to the domestic industry. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:

“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both

*Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been **recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough**, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."*

68. The Panel on US — Wheat Gluten, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

"8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

69. In US — Line Pipe, the Panel found, in a statement not reviewed by the Appellate Body, that "there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination":

"[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this question we recall our discussion regarding the meaning of 'recent', and our finding that 'recent' does not imply an analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides 'that such product is being imported ... in such increased quantities'. The Agreement uses the adjective 'increased', as opposed to 'increasing'. The use of the word 'increased' indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product 'is being imported' at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met."

70. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above-mentioned law and WTO jurisprudence.

I.3.2. Methodology adopted for segregation of import data based on RVC content

71. The Authorised Officer notes that from the DG Systems import data, it is not possible to identify the RVC content of PVC Suspension Resins from individual entries since the item description of the individual entries does not mention the specific RVC content. Therefore, the Authorised Officer has not been able to segregate the raw import data of PVC Suspension Resins provided by DG Systems into **above** and **upto 2PPM**. The Authorised Officer has therefore relied on the information provided by the interested parties to quantify the volume of imports of PVC Suspension Resins which are above 2PPM and the volumes which are upto 2PPM. The Authorised Officer notes that several interested parties have participated in the investigation by filing responses to the questionnaire and providing the relevant information. The Authorised Officer has accepted claimed volumes of export of PVC Suspension Resins upto 2PPM RVC content only to the extent that such claimed volume of imports of the cooperating producer/exporters are captured by the DG Systems import data.
72. The Authorised Officer has received information from producers/exporters regarding exports to India. The producers/exporters have provided information indicating the volume of PVC Suspension Resins with RVC content upto 2PPM exported to India by them. The producers/exporters have filed 'specification sheets' and 'certificates of analysis' to corroborate their claimed volume of exports of PVC Suspension Resins with RVC content upto 2PPM. Specification sheet is a document generally used by producers to communicate to the prospective customers the specifications of the product that a producer produces and sells in the market. The customers buy the material based on the specifications published by the producers in the specification sheet, whereas certificate of analysis is merely a reflection of the product that has actually been supplied. The consumers place the order and negotiate the price based on declared or notified specifications of the product. A non-compliance of a certificate of analysis with specification sheet can allow a buyer to reject the material purchased from the producer. However, a buyer cannot reject receipt of material if the specifications conform to the specification sheets. The Authorised Officer has relied on the specification sheets and the certificate of analysis to classify import data of PVC Suspension Resin based on RVC content.

73. The Authorised Officer has observed that there are broadly two channels of imports of the PVC Suspension Resin to India:
- a. Direct Channel: whereby the foreign producer of the subject merchandise directly sells their goods to customers in India.
 - b. Indirect Channel: whereby producers of the subject merchandise sell their goods to customers in India through merchant exporters/traders.
74. With respect to exports made through direct channels, and for those exports made, the cooperative producers who have filed the exporter's questionnaire response, the Authorised Officer has been able to verify the volume of exports of PVC Suspension Resins with *upto* 2PPM RVC content from their sample specification sheets or the certificate of analysis submitted thereto and has excluded the same from the total imports of PUC into India. Merchant Exporters/traders who have cooperated and claimed that they are exporting PVC suspension resin upto 2PPM in the said investigation and submitted their export data to this extent with sample specification sheets or certificate of analysis, the Authorised Officer has considered such exports as upto 2PPM and have excluded the same from the imports of PUC to India.
75. However, some of the participating producers/exporters have indicated that they have made sales of PVC Suspension Resin with *upto* 2PPM RVC content to India through other merchant exporters/traders which accounts for indirect sales channel. However, these traders have not cooperated and on behalf of these traders the producer/exporter is claiming that the exports are of PVC suspension Resin *upto* 2PPM. However, in absence of cooperation from these other traders, the Authorised Officer cannot confirm that the exports made by these traders are of the same product, as traders are free to export products produced by different producers which includes participating and non-participating producers producing the PUC as well as the like article since Chinese national standard for PVC suspension is below 5PPM and therefore the Authorised officer in view of the above facts has considered all such exports through indirect channel as the imports of PUC on the basis of facts available.
76. In order to assess the volume of imports of product under consideration and PVC Suspension Resins with RVC content upto 2 PPM the Authorised Officer has sorted the data based on the standards established in the country of origin, the specification sheet and on the basis of the evidence of the product actually supplied by the producer / exporter to India. In the case of China and USA, the respective Governments have specified the standard of PVC Suspension Resins with RVC content of upto 5 PPM. Accordingly, the Authorised Officer has considered all exports from such countries are that of the product under consideration unless a contrary proof has been furnished by any producer/exporter in the form of specification sheets, certificate of analysis or any other relevant document.
77. In case of imports from USA, none of the producers/exporters have participated in the present investigation and since the National standard of USA is same as that of China PR, the Authorised Officer has included these imports from USA in the total imports of PUC basis on the facts available.
78. In case of Taiwan, the Authorised Officer has determined the RVC content of imports based on the evidence on record. It is noted that the Authorised Officer has accepted the claims of the participating producers/exporters of Taiwan and accordingly has deducted such volume of imports considering it to be PVC suspension resin with RVC content upto 2PPM while calculating total volume of imports of PUC from Taiwan to India. In case of Russia, the domestic industry has furnished evidence in form of specification sheet of one of the producer based in Russia to claim that the producers of Russia produce PVC suspension resin with RVC content above 2 PPM and if a producer is mentioning in its specification sheet that it produces PVC suspension resin above 2 PPM that is relatable to the fact that even Russian National standard allows production of PVC Suspension Resin above 2PPM and as none of the producers/exporters have participated in the subject investigation to establish contrary to the facts available, the Authorised Officer has considered such imports from Russia as PVC suspension Resin above 2PPM i.e. the PUC.
79. It is further noted that the quantitative restriction is only against the imports of PVC suspension resin with RVC content above 2PPM therefore the producers/exporters producing or exporting PVC suspension resin with RVC content upto 2PPM would not be impacted by the proposed measure.
80. Governments of Saudi Arabia, Thailand and Mexico have stated that as per Article 9.1 of the Safeguard Agreement, "Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country member as long as its share of imports of the product concerned in the importing member does not exceed 3 per cent.". The Authorised Officer noted that as per Proviso to Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, no such quantitative restrictions shall be imposed on any goods originating from a developing country so long as the share of imports of such goods from that country does not exceed three per cent or where such goods originate from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such countries taken together does not exceed nine per cent of the total

imports of such goods into India. It is noted that since the domestic industry has not been able to provide any evidence contrary to the claim made by the Governments of Saudi Arabia, Thailand and Mexico, therefore the Authorised Officer has accepted the claim of the Governments of the above said countries and considered it as 'like article' and not the PUC.

81. The Authorised Officer has relied on DG system data and accepted the export figures provided by the participating exporters to carry out analysis for this investigation and wherever there was a data mismatch between producer's /exporter's data and the DG System's data, the Authorised Officer has relied and based its examination and analysis on the DG Systems data.

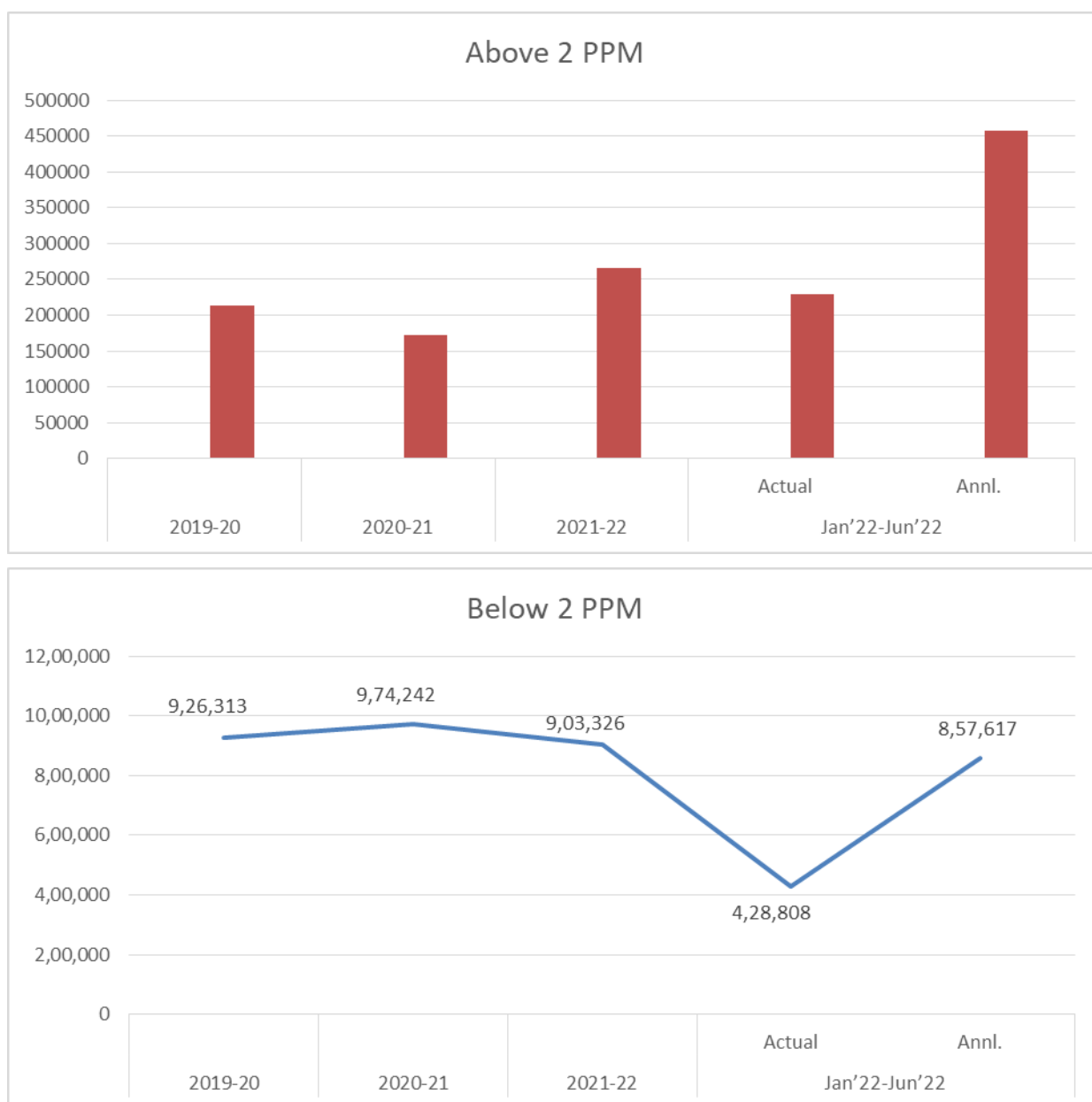
I.3.3. Increase in imports in absolute terms

82. The applicants have claimed that the product under consideration is being imported into India for several years. However, there has been a sudden, sharp and significant increase in imports in the most recent period.
83. Some interested parties have submitted that the total imports of PVC Suspension Resins in India have not increased. The same has rather declined. The Authorised Officer notes that Article 2 of the Agreement on Safeguards provides for conditions for invoking Safeguard Measures. Article 2.1 of the Agreement explains the increase in imports of product into the territory of the members.

"1. A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products."

84. Article 2.1 of the Agreement states that a Member may apply safeguard measures when "such product" is being imported into the territory in increased quantities and under such condition as to cause or threatens to cause serious injury to the domestic industry. Since the product under consideration in the present investigation is only PVC Suspension Resins with RVCM content above 2 PPM, as per the requirements of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards, only the volume of imports of the product under consideration has to be examined. However, the Authorised Officer has also examined the total imports of PVC Suspension Resins in India, including upto 2 PPM wherever necessary. Further, the Authorised Officer has examined imports of PVC suspension resin with RVCM both upto and above 2 PPM also individually:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22	
					Actual	Annl.
PUC (PVC Suspension Resins with RVCM above 2PPM)	MT	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
Like article (PVC Suspension Resins with RVCM upto 2PPM)	MT	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808	8,57,617
Total Imports	MT	11,39,263	11,45,767	11,69,293	6,58,006	13,16,011
Increase in imports						
PUC	MT		(41,424)	94,442		1,92,427
Like article	MT		47,929	(70,916)		(45,709)
Total Imports	MT		6,505	23,526		1,46,718



85. Imports of the product under consideration (i.e., PVC Suspension Resins with RVCM content above 2PPM) has increased substantially in absolute terms over a very short period. The imports of the PUC have shot up suddenly during January to June 2022. Import volumes have doubled in the most recent period as compared to 2019-20 to 2020-21. Overall imports of the PUC have increased by almost 115% from the base year. It is clearly evident that there has been a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC.
86. On the other hand, it is noticed that import volumes PVC Suspension Resins with RVCM content upto 2PPM has declined. In fact, the increase in total imports of PVC Suspension Resins is entirely attributable to the sudden, sharp and significant increase in imports of the PUC only. The imports of PVC Suspension Resins with RVCM content *upto* 2PPM show no increase in imports, and have therefore been excluded from the scope of the measure.
87. The Authorised Officer also analysed the imports in Jan'2020-Jun'2020, Jan'2021-Jun'2021 period in order to ascertain whether the same shows absence of surge in Jan'2022-Jun'2022 when compared with the previous corresponding period. Table below shows the volume of imports in different periods:

Particulars	UOM	Jan'20-Jun'20	Jan'21-Jun'21	Jan'22-Jun'22
Above 2 PPM	MT	1,13,329	1,99,689	2,29,197
Upto 2 PPM	MT	4,40,445	4,89,983	4,28,808

88. It is seen that the imports of the product under consideration have increased by almost 15% in the most recent period when compared to the same period in the previous year i.e., January 2021-June 2021 and increased by 102% when compared to January 2020-June 2020. Imports of PVC Suspension Resin with RVC content upto 2PPM during the period January 2021-June 2021 have more or less remained the same as compared to the same period in the previous year. There has been a decline in import volumes of these goods in the January 2022-June 2022 period. It is thus concluded that the imports of product the under consideration have increased in absolute terms in the most recent period.

I.3.4. Imports in relative terms

89. It was examined whether the imports of product under consideration constitute increased imports in relation to Indian production, demand in India, sales of domestic producers in India, total imports of product under consideration and like article into India.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22	
					Actual	Annl.
Imports of PUC	MT	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
Total Indian production (like article)	MT	***	***	***	***	***
Trend	MT	100	95	99	52	105
Demand in India	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	101	56	112
Total Imports in India	MT	11,39,263	11,45,767	11,69,293	6,58,006	13,16,011
Sales of domestic producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	100	54	109
Imports of PUC in relation to						
Ø Indian production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	127	207	207
Ø Indian demand	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	122	189	189
Ø Total imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	121	184	184
Ø Sales of domestic producers	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	129	200	200

90. It is seen that:
- The subject imports have increased consistently and significantly in relation to gross domestic production, from ***% in base year to ***% in the most recent period.
 - The subject imports have increased consistently and significantly in relation to gross domestic demand, from ***% in base year to ***% in the most recent period.
 - The subject imports have increased consistently and significantly in relation to gross imports into India, from ***% in base year to ***% in the most recent period.
 - The subject imports have increased consistently and significantly in relation to sales of the domestic producers, from ***% in base year to ***% in the most recent period.

91. It is thus seen that the subject imports have increased consistently and significantly in relation to imports into India, Indian production, gross domestic consumption and sales of the domestic producers. The interested parties claimed that the imports from China had increased on account of delays and higher turnaround time for shipments from other countries. However, the Authorised Officer notes that the imports of the product under consideration have not only increased in relation to total imports, but also Indian production, demand and sales of domestic producers.

J. UNFORESEEN DEVELOPMENTS

J.1. Submissions by the other interested parties

92. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the unforeseen developments.
- The unforeseen developments leading to increase in imports provided by the applicants relate to China only.
 - There is no link between unforeseen developments and surge in imports, which is a requirement affirmed by WTO Panel in India – Iron and Steel products.
 - Surge in imports is due to expiry of anti-dumping duties on imports of homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) from China PR, USA and Thailand in February 2022 and not on account of unforeseen developments.

J.2. Submissions by the domestic industry

93. The following submissions were made by the applicants with regard to the unforeseen developments.
- Increase in imports is due to unforeseen developments such as Russia-Ukraine conflict, soaring global freight rates and stable Chinese internal freight costs as well as disparity between consumption and production in China PR.
 - Russia-Ukraine conflict led to increase in oil prices and cost of production of petrochemicals (including VCM). The cost of production of PVC Suspension Resins using VCM increased. The Chinese producers use coal to manufacture product under consideration, which is available in China at prices below international market price. Accordingly, the cost of production in China PR did not increase.
 - While the global freight rates increased leading to increase in cost of procuring imported raw material, the Chinese producers were insulated from such price increase as coal was available to them domestically.
 - The major demand of product under consideration is on the eastern part of China PR which faced multiple lockdowns due to which the demand declined. However, the production of product under consideration is on western part which did not face as many lockdowns. This led to increase in exportable surplus in China PR.
 - Since most of the producers of the product under consideration are situated in China PR, the unforeseen developments would naturally pertain to China PR. In fact, the applicants have claimed that the product under consideration is only imported from China PR.
 - The other interested parties have not disputed the factual aspects of the unforeseen developments relied on by the applicants. While the anti-dumping duty on imports from China, USA and Thailand expired, only imports from China have increased and not from other countries.
 - Contrary to the submissions of the other interested parties, increase in imports is not due to expiry of anti-dumping duty but due to unforeseen circumstances which are applicable to a certain set of producers which are engaged in manufacturing PVC with RVCM above 2 PPM. This is evident from the fact that imports of PVC with RVCM upto 2 PPM from China as well as from other countries have reduced.

J.3. Examination of the Authorised Officer

94. Article XIX of GATT obligates the investigating authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the domestic industry. Further, Rule 9(1) of the Rules also provides that increased imports must be as a result of unforeseen developments as under:

“The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a causal link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury.”

95. The Authorised Officer notes that the increase in imports must be on account of developments that were unforeseen or unexpected. Further, the development must have been unforeseen at the time of incurring the obligations, that is, accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, and providing tariff concessions.
96. The applicants have submitted that the unforeseen development leading to increase in imports of the product under consideration in India was Russia-Ukraine conflict, increase in global freight rates and excess undisposed production in China. The Authorised Officer has examined the developments identified below.

J.3.1. Russia-Ukraine Conflict

97. The information provided by the domestic industry shows that due to the Russia-Ukraine conflict, the oil prices increased. Due to the increase in oil prices, the cost of production of petrochemicals increased globally. This resulted in increase in cost of production of PVC Suspension Resins manufactured through ethylene route. The Authorised Officer noted that the crude prices increased during the period January 2022 to June 2022.
98. PVC Suspension Resins can be manufactured either through ethylene route or carbide route. While majority of the producers globally manufacture PVC Suspension Resins through ethylene route, some of the producers in China and a number of countries (including India) manufacture through carbide route as well. While the cost of production of the manufacturers producing through ethylene route increased globally, the cost of production of such manufacturers through carbide route and where the coal was available domestically within the country was not impacted by the Russia-Ukraine conflict. The applicants have submitted that coal is available domestically in China at cost below the international market prices which further led to continued lower cost of production of such manufacturers in China. The claim made by applicants has not been disputed by other interested parties, including the producers in China, Government of China and associations representing such producers.
99. The Authorised Officer notes that PVC Suspension Resin with RVCM content above 2PPM is primarily manufactured through the carbide route (where prices of coal have remained stable), whereas PVC Suspension Resin with RVCM content upto 2PPM is primarily manufactured through the ethylene route (where prices have been impacted by the Russia-Ukraine conflict). As a result of increase in VCM costs, the price of PVC Suspension Resin increased. This led to increase in imports of product under consideration in India, as these producers of resin above 2 PPM did not face these cost increases.

J.3.2. Increase in Global Freight Rates

100. The domestic industry has submitted that there has been a substantial increase in freight rates globally post COVID-19 pandemic. It was claimed that the domestic industry manufactures PVC Suspension Resins through ethylene route. The raw material of the goods manufactured by the domestic industry, i.e. "VCM" is majorly imported. It has been contended that on account of the substantial increase in global freight rates, the cost of the raw materials, i.e. "VCM" into India increased, as a result of which the cost of production of the domestic industry increased. The applicants submitted that the producers of resin above 2 PPM were however insulated from such increase in cost of production, as this product was produced from coal, which was locally availability to the concerned producers at prices much below the international market prices for coal. The Authorised Officer does not however find this claim of the domestic industry convincing since any increase in freight rates, which has allegedly impacted the cost of the applicants' raw material, would have equally impacted the landed value of the product under consideration imported into India – thereby neutralising the injurious effects of such imports on the domestic industry. Therefore, the Authorised Officer is unable to accept the contention of the applicants.

J.3.3. Excess undisposed Production in China PR

101. The applicants submitted that (a) there was a disparity between consumption and production of the product under consideration in China due to COVID-19 related lockdowns, (b) the product is majorly consumed in the eastern part of China which faced significant number of lockdowns due to COVID-19, whereas the product under consideration is majorly produced in the western part of China, which did not face as much lockdowns as was faced in the eastern part. This led to shutdown of the downstream industry, resulting in decline in demand of the product under consideration in China, without proportionate reduction in production.
102. Due to this imbalance, the production of the product did not decline commensurate to decline in demand, resulting in significant material available with these producers at a cost much lower than the cost of producers through ethylene route. Further, manufacturing of PVC Suspension Resins is a continuous process leading to inventory build-up, if not sold in the market. The domestic industry submitted that inventory build-up beyond certain limits is not even an option with any producer and therefore producers have to continuously sell the product.
103. Some interested parties have submitted that the increase in imports of the product under consideration is due to expiry of the anti-dumping duty on PVC Suspension Resins. It is however seen that anti-dumping duty was in

place on imports of PVC Suspension Resins from USA, Thailand and China, and the same was in force on imports of PVC Suspension Resins with RVCM content of both upto and above 2 PPM. However, it is seen that imports of PVC with RVCM content above 2PPM have increased, whereas imports upto 2PPM have declined. If the increase of imports of the PUC were attributable to the expiry of the anti-dumping duty on PVC Suspension Resins, it would imply that there must have also been a corresponding increase in imports of PVC Suspension Resins with RVCM content upto 2PPM, however, this is not the case. In any case, the interested parties have not rebutted the claim of the applicants concerning the unforeseen developments identified by them. Thus, it cannot be considered that the increase in imports is on account of expiry of anti-dumping duty.

104. Having regard to the facts on record, it is concluded that imports of the PUC have increased as a result of unforeseen developments.

K. SERIOUS INJURY AND/OR THREAT OF SERIOUS INJURY

K.1.Submissions by the other interested parties

105. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury to the domestic industry.
- a. The applicants have demonstrated factors which could indicate a threat of serious injury, but the same is limited to imports from China.
 - b. The claim of serious injury of the applicants is contrary to published information and conclusions drawn by the Authorised Officer in recent investigations.
 - c. Economic parameters of the domestic industry, both volume and price, have improved, especially in 2021-22 and 2022-23, demonstrating absence of serious injury or threat of injury. Thus, any finding of injury or threat of injury would not be sustainable as held by Appellate Body in US – Line Pipe.
 - d. Capacity, production, sales, capacity utilization, market share, number of employees and productivity has increased. Inventories have declined and losses have converted to profits.
 - e. Post POI as well, the industry is doing very well and there is no threat of injury to the applicants.
 - f. There is no causal link as there is no increase in imports, and performance of applicants has improved.
 - g. While the investigation period was considered as 1st April to 30th June 2022, the applicant is trying to mislead the Authorised Officer by relying on quarter-wise data. Period of investigation should be considered as total, and not in segments.
 - h. Since data for July to September 2022 is beyond the period of investigation, it should not be examined. The Authorised Officer is bound to examine injury and causal link for the period of investigation only.
 - i. No request for change in period of investigation can be considered after initiation.
 - j. Information for January to June 2022 as a whole must be relied upon instead of quarterly information.
 - k. The information for July to September 2022 cannot be accepted, as the source, basis or supporting evidence of the same is not clear.

K.2.Submissions by the domestic industry

106. The following submissions were made by the applicants with regard to injury to the domestic industry.
- a. The domestic industry had filed the petition contending threat of serious injury which was imminent and foreseeable and not actual serious injury.
 - b. Post filing application, the domestic industry has already started suffering injury due to imports of the product under consideration.
 - c. While the price of VCM has increased since February 2022, the landed price of the product under consideration has declined. The domestic industry has been forced to compete with low-priced imports by reducing its prices in a situation wherein its cost of production has increased.
 - d. The domestic industry has been forced to reduce its prices in order to maintain its customer base. The average prices to large customers have declined significantly.
 - e. The imports of the product under consideration are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
 - f. The price quoted by the Chinese producers is much below the prices of the domestic industry, which would further suppress / depress the prices of the domestic industry.

- g. The landed price of the product under consideration is below the selling price of the domestic industry as well as the landed price of imports of like article. As the difference between the prices of the product under consideration and like article increased, the volume of imports of the product under consideration also increased.
- h. Since there is demand-supply gap in India and global over-capacities, the foreign exporters ship high quantities to the Indian market. The low prices of such imports create a price strain on the Indian producers.
- i. The domestic industry has not suffered injury in terms of volume parameters because of the production process and the compulsions on the industry to run the plants at optimum capacity utilization, on accounts of long-term contractual obligations to lift raw material on a regular basis since VCM cannot be shipped through normal containers and the specially manufactured ships for transporting VCM have to maintain their fixed rotations between ports. In case of default in picking raw material, there will be financial implications as well as uncertainty in procuring raw material in the future and it would create a ripple effect in the global PVC industry as the ships will not be able to maintain regular rotations to other ports. Further, VCM is stored in specialized tanks and there is a limit to inventories that can be held by a producer.
- j. The inventories of the domestic industry have increased substantially.
- k. Had the domestic industry not reduced prices, it would have lost market.
- l. The imports of the product under consideration have also taken away the market of other imports (of like product) in India.
- m. While the profits of the domestic industry improved from losses in 2020-21, they have declined significantly in the most recent period. When seen on a quarterly basis, the profits have declined by ***% in Q4 of 2021-22 as compared to Q3 of 2021-22 and by ***% in Q1 of 2022-23 as compared to Q4 of 2021-22.
- n. Contrary to the submissions of the other interested parties, one of the applicants has suffered losses during Q1 of 2022-23 and both the applicants suffered losses in Q2 of 2022-23.
- o. Cash profits as well as profit margins have declined during the most recent period.
- p. The profits as a percentage of selling price have declined from [***]% in Q3 of 2021-22 to [***]% in Q1 of 2022-23.
- q. The injury to the domestic industry is due to low-priced imports of product under consideration and not due to any other factors.

K.3.Examination of the Authorised Officer

107. The Authorised Officer is required to examine whether the increased imports of the product have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products. As per Section 9A(4) of the Act, serious injury means an injury causing significant overall impairment in the situation of a domestic industry, while threat of serious injury means a clear and imminent danger of serious injury. Rule 8(a) of the Quantitative Restrictions Rules provides as under for determination of injury.

“The Authorised Officer shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:

- (a) in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Authorised Officer shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the goods concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment;”*

108. In view of the above legal principle, the parameters relating to injury have been analysed hereinbelow.
109. The product under consideration, that is, PVC Suspension Resins with RVCN content above 2 PPM and the like article, that is, PVC Suspension Resins with RVCN content upto 2 PPM are used interchangeably and for the same purposes. Accordingly, the Authorised Officer has taken into consideration, for the purpose of injury assessment, imports of both upto and above 2 PPM, separately and examined whether imports of PVC suspension resin above 2 PPM have caused or threatening to cause serious injury to the domestic industry. Further, the Authorised Officer examined whether imports of resin upto 2 PPM could have been a cause of the claimed injury.

K.3.1. Assessment of demand/consumption

110. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been determined as the sum of domestic sales of like product produced by the Indian producers, and imports of like product into India and imports of product under consideration into India.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22	
					Actual	annualised
Domestic industry – Sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	116	63	126
Other producers – Sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	95	94	51	102
Imports of PUC	MT	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
Imports of like article	MT	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808	8,57,617
Demand/ consumption	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99%	101%	56%	112%

111. It is seen that the demand for the product has increased throughout and in the most recent period. Further, demand in the most recent period (on annualised basis) was higher as compared to the demand in the base year. However, so significant was the increase in the volume of imports of the subject product that whereas the demand increased by *** MT in the most recent period as compared to the base year, the subject imports increased by *** MT, which amounts to around 87% of the increase in demand. Thus, the growth in consumption was largely encapsulated by imports of the subject product.

K.3.2. Evolution of prices over the period

112. Import price of the subject and non-subject imports of PVC resin was examined over the entire period. The Table below demonstrates the factual position. It is seen that the difference between the landed price of the PUC and the like article during the most recent period increased as compared to the base year and the previous year. Further, there has been an increase in the price difference between the PUC and the like article since 2021 – 22 and this pattern has continued in the most the recent period.

Landed Price	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22
PUC	₹/MT	65,754	81,281	1,21,784	1,27,503
Like article	₹/MT	68,504	80,141	1,23,615	1,31,951
Difference	₹/MT	-2,749	1,140	-1,831	-4,448

K.3.3. Price undercutting

113. It was examined whether imports of the subject product were priced below the selling price of the domestic industry and causing price undercutting in the market.

Particulars	Unit	PUC	Like article
Net sales realisation	₹/MT	***	***
Landed price	₹/MT	1,27,503	1,31,951
Price undercutting	₹/MT	***	***
Price undercutting	%	***	***
Price undercutting	Range	5-15%	1-5%

114. It is seen that there is positive price undercutting in relation of both the PUC as well as the like article. However, the price undercutting in respect of the PUC is higher than the price undercutting in respect of the like article. Furthermore, the Authorised Officer notes that price undercutting cannot be seen in isolation, and must instead be examined in tandem with other factors. It is noted that despite a small positive price undercutting in relation of the like article, the market share, and the absolute and relative volume of imports of the like article has declined. In addition to the above, as clearly noted, the surge of imports is only in the segment of PVC resin having VCM content above 2 PPM and therefore, when the price undercutting is correlated with volume and other injury parameters, it cannot be said that PVC resin upto 2 PPM is causing an injury on the overall performance of the domestic industry. However, in the case of the PUC, the price

undercutting is significant and surge is already noted and therefore, it is noted that the imports of the PUC is the real cause of injury for the domestic producers.

K.3.4. Price suppression / depression

115. The Authorised Officer examined whether imports of the subject products were suppressing or depressing the prices of domestic industry in the market.

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	113	162	166
Landed Price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	124	185	194
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	130	185	183

116. It is seen that in the most recent period (January-June, 2022), whereas the cost of sales of the like article manufactured by the domestic industry increased by ₹ *** per MT, the selling price has declined by ₹ *** per MT. Although, the landed value of the imported PUC has increased, it is noted that, despite such increase, the landed price of the PUC is below the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry. The imports are thus depressing the prices and preventing the price increase that would have otherwise happened in absence of such low-priced imports of the PUC.
117. The applicants have further submitted that the average selling price to large customers have reduced due to low-priced imports of the product under consideration. The Authorised Officer notes that post October 2021, the selling price of both the applicants to its largest customers have declined substantially.

K.3.5. Market Share

118. The market share of imports of the product under consideration, imports of like article and domestic producers in India was as follows.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	114	114
Other producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	92	89
Domestic producers as a whole	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	98	96
Imports of subject product	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	122	189
Imports of like article	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	97	82
Total demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	114	114

119. It is seen that the market share of the product under consideration has increased significantly in the most recent period, whereas the market share of domestic producers as a whole and other domestic suppliers of the PUC declined in the most recent period. The domestic industry has maintained its market share by lowering its selling price. The domestic producers have not been able to take advantage of the growth in consumption which has largely been captured by the imports of the PUC.
120. The domestic industry further submitted that the sales and market share of the domestic industry must be seen in the light of the nature of the production process. The domestic industry submitted that procurement of VCM requires very special and different conditions. VCM is transported in special vessels. These are dedicated vessels engaged in transportation of VCM only. Therefore, it is infeasible to stop procurement of VCM. Purchase decisions of VCM are not linked to sales volumes or selling price of PVC. Purchases happen

independent of sales. There are limited suppliers of VCM and a typical purchase is large in volume, whereas the sales of PVC are in small volumes. Given the large volume of individual purchases of VCM, the purchases are well planned and in advance. By contrast, sales volumes are for supplies on immediate basis, most often within the month. Further, any producer has very limited storage facility for both VCM and PVC. Therefore, consumption of VCM and production of PVC is a compulsion. Further, once produced, no producer can hold PVC inventories for a long period. The producers of PVC Suspension Resins have storage facilities for a very limited volumes of both VCM and PVC. Thus, it is not an option for the domestic industry to withhold prices and face inventory pile up either for VCM or PVC. Further, the domestic industry does not have an option to hold purchases of VCM.

K.3.6. Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales

121. The Authorised Officer has analysed the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22	
					Actual	Annualised
Installed capacity	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	103	52	103
Production	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	115	58	117
Capacity utilization	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	112	113	113
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	103	116	63	126

122. It is seen that the domestic industry's performance in respect of these parameters has not deteriorated. The applicants have submitted that the volume parameters of the domestic industry have not been impacted due to the nature of the industry. It is noted that the increase in domestic sales of the domestic industry represents a very insignificant part of the increase in total demand. Whereas the total demand of the PUC and the like article increased by 10 % in the most recent period. The share of the domestic industry's sales in the increase in demand is only about 1% of the increase in total demand. At the same time, the share of increase in imports of the PUC in this growth in demand was almost 80%. Thus, the growth in demand was largely captured by the imports of the PUC due to which the domestic industry was not able to take advantage of the growth in demand.

K.3.7. Inventory

123. The inventory position of the domestic industry over the period of investigation was as below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22	
					Actual	Annualised
Average Inventories	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	35	197	197

124. It is seen that the inventories with the domestic industry increased substantially in the most recent period, showing ***% increase in the most recent period as compared to the previous year. Even though the sales of domestic industry have slightly increased in the 'most recent period', due to surge in imports of the PUC, the domestic industry was not able to take advantage of the full growth in demand because of which the inventories of the domestic industry have accumulated. The domestic industry submitted that the domestic industry as such cannot hold significant level of inventories.

K.3.8. Employment and Productivity

125. Employment and productivity situation of the domestic industry was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
No. of employees	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	118	120
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	97	97
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
Trend	Indexed	100	100	115	117

126. It is seen that the performance of the domestic industry with regard to number of employees and productivity improved over the period of investigation.

K.3.9. Profit / Loss

127. The profitability of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
Profits/Losses	₹/MT	(***)	***	***	***
	Indexed	(100)	288	386	246
Cash profits	₹/MT	(***)	***	***	***
	Indexed	(100)	612	788	546
Profit as a % of selling price	₹/MT	(***)	***	***	***
	Indexed	(100)	221	208	134

128. It is seen that domestic industry was suffering losses in the base year. The domestic industry was incurring losses during the base year, however the domestic industry was making profits from the year 2020-21 till June 2022. However, it is seen that there is a decline in profitability of the domestic industry during the most recent period, which is an indication of imminent injury to the domestic industry. Further, the selling price of the domestic industry was also below the cost of sales in the base year due to which the domestic industry suffered losses in the base year. It is further seen that while the profitability of the domestic industry improved in 2020-21 & 2021-22, the profitability parameters in terms of per unit profits, cash profits per unit and profits as a percentage of selling price declined in the most recent period as compared to 2020-21 and 2021-22.
129. Since the applicants had contended that the surge in imports in the most recent period were threatening serious injury to the domestic industry and the profit parameters of the domestic industry were showing a decline in the most recent period, the profits in the most recent period were examined further by considering performance in the most recent period (January.-June, 2022) on quarterly basis.

K.4.Parameters showing threat of serious injury

130. It was examined whether increased imports were threatening further serious injury to the domestic industry. The Authorised Officer notes that Section 9A(4) provides that threat of serious injury means a clear and imminent danger of serious injury. The Agreement on Safeguards also provides that “threat of serious injury” shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.

K.4.1. Rate of increase in imports

131. The Authorised Officer notes that the volume of imports of the product under consideration have increased at a very high rate over the period.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22	
					Actual	AnnL.
Subject imports	MT	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197	4,58,394
Rate of increase	%	-	-19%	55%	-	72%
As compared to base year	%	-	-19%	25%	-	115%

132. It is seen that the volume of imports increased substantially in previous year and most recent period. Further, the imports have almost doubled in the most recent period, as compared to 2019-20. Thus, the rate of increase in imports was very high.

K.4.2. Decline in prices of product under consideration in comparison to PVC with RVC content upto 2 PPM.

133. The Authorised Officer examined the trend in the import price of the PUC and like article over the injury period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
Landed Price					
PUC	₹/MT	65,754	81,281	1,21,784	1,27,503
Like article	₹/MT	68,504	80,141	1,23,615	1,31,951
Difference	₹/MT	-2,749	1,140	-1,831	-4,448

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-Jun'22
Import volumes					
PUC	MT	2,12,949	1,71,525	2,65,967	2,29,197
Like article	MT	9,26,313	9,74,242	9,03,326	4,28,808
Share of PUC imports in relation to gross imports	%	19%	15%	23%	35%

134. It is seen that the price difference between the like article and product under consideration has increased significantly. While the imports of like article were earlier commanding predominant share in India, due to the increase in difference between the landed price, the imports of the PUC have started commanding the majority of imports into India, when viewed in the light of number of suppliers and supplying countries.

K.4.3. Price undercutting

135. As noted in the relevant section of this findings, the price undercutting is positive and significant. The applicants have submitted that due to decline in prices of the product under consideration, the domestic industry has been forced to reduce price to maintain its market share.
136. The above clearly shows that the customers switched to the cheaper subject product, leading to increase in its demand, and decline in non subject imports.

K.4.4. Decline in profitability of the domestic industry during the post-POI period.

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	Jan'22-Jun'22	July-Sept 22
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	113	162	166	135
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	130	185	183	(130)
Profit/Loss	₹/MT	(***)	***	***	***	(***)
		(100)	287	386	246	(266)

137. The Authorised Officer has also examined the performance of the domestic industry in the post-POI period. As seen from the table above, the cost of sales of the domestic industry was above the selling price during the base year. In subsequent years (ie. 2020-21 to June 2022), the cost of sales was below the selling price, and the domestic industry appears to have been profitable. However, it is noticed that during the third quarter of 2022 – which is the period immediately after the surge of imports has taken place – the cost of sales of the domestic industry is higher than the selling price, and hence the domestic industry is incurring losses during the post-POI period examined. These losses have been incurred despite the fact that there has been about a ***% reduction in cost of sales during the third quarter of 2022 as compared to the cost of sales during the first and second quarters of 2022. It is also noticed that there has been a steady decline in profitability of the domestic industry from January 2022 to September 2022. This is a clear indication that the surge in imports is having an impact on the profitability of the domestic industry. It is therefore seen that there exists a clear and imminent threat of serious injury due to the surge in imports.

K.4.5. Global over-supply and exportable surplus in China

138. It is seen that the increase in imports of the product under consideration into India is due to unforeseen developments which includes disparity between production and consumption in China. Due to the onset of COVID-19 pandemic, while the consumption declined in China, the production of product under consideration remained stable. Due to this, the producers in China were faced with significant exportable surplus. Additionally, the PVC Suspension Resins market is such that there is a global oversupply of the product. At the same time, there is significant demand-supply gap in India, and therefore, the Indian market is a huge market opportunity for any PVC producer globally. The Indian market clearly is susceptible to distortion in a situation of significant market fluctuations, posing a threat of serious injury in case low priced goods are diverted to India.

K.4.6. Continued existence of unforeseen developments

139. As noted in the relevant section of this findings, the increase in imports of the product under consideration is due to unforeseen developments comprising of disparity in production and consumption in China caused by

Covid-19, conflict between Russia and Ukraine. It is noted that both these factors continue to prevail in the market.

140. From the foregoing, it is evident that the increase in imports has not only caused serious injury to the domestic industry, but is also threatening to cause further injury.
- The volume of imports has increased significantly in absolute and relative terms.
 - The rate of increase in imports is very high, and the imports have increased by 20 times as compared to the base year.
 - There is a global oversupply for the product. The Chinese producers (of subject and non-subject goods) hold significant surplus capacity.
 - The imports are undercutting the prices of the domestic industry significantly, and caused a very significant depressing effect on the prices of the domestic industry, and prevented the price increases that would have increased in the market.
 - The prices offered by the domestic industry to major customers have declined significantly.
 - The price of the subject imports is significantly lower than that of PVC with RVCM content upto 2 PPM.
 - The market share of the subject imports has increased over the period, while domestic producers and other imports lost market.
 - While capacity utilization, production and sales of the domestic industry did not deteriorate, the domestic industry was facing accumulation of inventories and steep decline in their profitability.
 - The profitability of the domestic industry has declined over the period, and further deteriorated into losses in the subsequent period of Jul-Sep'22.

L. CAUSAL LINK

141. As per Rule 8(b) of the Rules, the Authorised Officer is required to determine whether increased imports were a cause of the serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. In this regard, the observations by the WTO Panel in Korea- Dairy which sets forth the basic approach for determining "causation" has been noted. Therefore, for the purpose of causal link assessment, the Authorised Officer evaluated all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the domestic industry and ascertained whether the increased imports of the subject products were one of the causes of serious injury and threat of serious injury to the domestic industry. In addition, the Authorised Officer ascertained whether factors other than increased imports were a cause of injury to the domestic industry. While there are no laid down "other factors" that are required to be evaluated by the Authorised Officer, the Authorised Officer considered whether factors such as imports of PVC suspension resin upto 2 PPM, developments in technology, export performance, productivity, contraction in demand, possible dumping of the product, were principal cause of injury to the domestic industry.

L.1.1. Volume and value of imports of PVC resin with RVCM upto 2 PPM

142. It is noted that the volume of imports of like article has slightly declined over the period, along with market share thereof. The price of PUC is lower than the price of imports of like article and the cost of sales of the domestic industry. As noted above, the price undercutting in respect of the PUC is higher than the price undercutting in respect of the like article. Furthermore, the Authorised Officer notes that price undercutting cannot be seen in isolation, and must instead be examined in tandem with other factors. It is noted that despite a small positive price undercutting in relation of the like article, the market share, and the absolute and relative volume of imports of the like article has declined. Therefore, the price undercutting in relation to the like article has not had an impact on the domestic industry's sales. However, in the case of the PUC, the price undercutting is significant since it has resulted in an improvement of its own market share and sales volumes.

L.1.2. Possible dumping of the product

143. There is no evidence of possible dumping of the product. The domestic industry provided calculations showing that the injury margin for the last one year period (possible investigation period of a dumping case) or even for last six months period (minimum investigation period of a dumping case) was negative. None of the interested parties contended that dumping of the product was a cause of injury to the domestic industry.

L.1.3. Contraction in demand

144. The Authorised Officer notes that there is no contraction in demand of the subject goods in the country. Thus, the domestic industry has not suffered any injury on this account.

L.1.4. Pattern of consumption

145. There is no claim that there has been a change in the consumption pattern for the goods.

L.1.5. Conditions of competition and trade restrictive practices

146. The Authorised Officer notes that the investigation has not shown that conditions of competition or the trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

L.1.6. Developments in technology

147. The Authorised Officer notes that there was no significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

L.1.7. Productivity

148. The Authorised Officer notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

L.1.8. Export performance of the domestic industry

149. The Authorised Officer notes that the injury analysis is only limited to domestic performance and the effect of the export performance is excluded from the same.

L.1.9. Performance of other products

150. The Authorised Officer has only considered the data relating to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.
151. Keeping in account the Rules and the principles laid down, the Authorised Officer has examined the causal link between imports of the product under consideration in India and threat of serious injury or injury faced by the domestic industry. The Authorised Officer notes as follows.
- There has been a significant increase in imports in the most recent period in absolute terms as well as in relation to production, domestic consumption, total imports, domestic sales of domestic industry and imports of like article in India.
 - The surge in imports of subject goods was so significant that the overall imports of PVC suspension resin have also shown increase even when imports of resin upto 2 PPM have shown decline in recent period.
 - The market share of the product under consideration has increased in India.
 - There was steep decline in the prices of the subject resin. The prices declined very significantly even in a period of less than one month. The imports of product under consideration were undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce the prices despite facing increase in costs.
 - While the volume parameters of the domestic industry have not suffered, the profitability parameters have witnessed a decline. The profits, cash profits and profits as a percentage of selling price have declined significantly. The decline in profits was so significant that the domestic industry faced financial losses in July-September 2022 period.
 - The inventories of the domestic industry increased significantly.
152. Some interested parties contended that there is no causal link, as imports of the product under consideration have not increased and the performance of the domestic industry has improved. The investigation has however shown that there was significant increase in the imports of the product under consideration, which were priced much lower than non-subject PVC imports. Given significantly higher price of non-subject imports, the Authorised Officer considers that imports of non-subject imports could not have been the principal cause of the steep price decline and consequent deterioration in performance of the domestic industry. The Authorised Officer considers that it is price undercutting by the subject goods which has forced the domestic industry to reduce its prices and margins in the most recent period. Due to reduction in prices, the profitability of the domestic industry declined significantly. Accordingly, the Authorised Officer finds that the injury to the domestic industry is caused by the increase in imports.

M. ADJUSTMENT PLAN**M.1. Submissions by the other interested parties**

153. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the adjustment plan.
- The applicants have not submitted a viable adjustment plan along with a project report and the plan is merely of one page, based on hypothetical assumptions.

- b. Safeguard duty cannot be recommended in absence of an appropriate adjustment plan, as has been the practice of the Authorised Officer in the case of Phthalic Anhydride, Cold rolled flat products of stainless steel, Non alloyed ingots of unwrought aluminium and Flexible Slabstock Polyol.

M.2. Submissions by the domestic industry

154. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the adjustment plan.
- Chemplast plans to bring down the cost of production by undertaking various measures such as [***].
 - DCW plants to undertake measures to [***].
 - Contrary to the submissions of the other interested parties, the applicants have submitted a viable adjustment plan.
 - Since the increase in imports is due to the cost of production in China being lower on account of the unforeseen developments, the adjustment plan provided by the applicants constitutes of measures to reduce cost of production in order to make domestic industry competent viz-a-viz imports of product under consideration.
 - As opposed to the contention of the other interested parties, there is no particular format or length required for an adjustment plan and the legal requirement is for a positive adjustment plan to compete with imports as held by the Panel in Korea- Dairy Products.

M.3. Examination of the Authorised Officer

155. The WTO Agreement on Safeguards requires an adjustment plan by the domestic industry in order to impose Safeguard Measures. In this regard, the Agreement on Safeguards provides as follows:

"Recognizing the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit competition in international markets"

156. Article 5.1 of the Agreement on Safeguards provides that a Member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.1 of the Agreement on Safeguards mandates a WTO member country to apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.4 mandates that in order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. The provisions are *pari materia* with Rule 9(1), Rule 10, Rule 13 and Rule 4(d)(ii) of the Quantitative Restrictions Rules. In addition, Rule 5(2) of the Rules provides as under:

"(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form appended to these rules and be supported with-

(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to increase in competition due to imports"

157. In the present case, the applicants have submitted adjustment plan to adjust with the unforeseen developments resulting in increased imports. Both the applicants have individually submitted adjustment plans to reduce their cost of production in order to become competitive vis-a-vis the imports of the product under consideration. Since the increase in imports is due to the impact of unforeseen circumstances on the cost of production of producers globally barring those engaged in producing subject PVC resin, the Authorised Officer considers that an adjustment plan aimed at reducing the cost of production should be reasonable and pragmatic. However, the Authorised Officer has considered imposition of safeguard measures only for a period of one year given the fact that the impact of COVID – 19 is fizzling out and the world, including China PR is on the way of restoration of normalcy. Further, countries are also taking measures to adjust to the supply chain issues arising out of Russia – Ukraine conflict. Therefore, the Authorised Officer is recommending imposition of quantitative measures only for a period of one year. Further, given the fact that the measure has been imposed only for a period of one year, it has not been considered necessary to make determination regarding the appropriateness of adjustment plan brought by the applicants.

N. PUBLIC INTEREST

N.1. Submissions by the other interested parties

158. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the public interest.
- OPPI, which is an association of plastic processors and plastic raw material manufacturers in India, strongly opposes the imposition of safeguard measures on PVC Suspension Resins as it will result in finished goods manufactured by small units expensive and uncompetitive.

- b. There exists a demand-supply gap and imposition of measures would distort market, giving monopolistic advantage to domestic producers who can only meet 50% of the total demand.
- c. If the safeguard measures are imposed, the imbalance in demand and supply would increase the prices of end product, reducing their demand and sales of end users.
- d. Imposition of measures would be against public interest as it would allow domestic producers to form cartel, dominate the market and create barriers for market entry, it will cut the regular supply to the users, allow to inflate prices and lead to market asymmetry.
- e. Imposition of measures would adversely impact thousands of end-users which are MSMEs and are a major employment generator. It will lead to increase in raw material prices for the fragmented small-scale industry.
- f. The value chain of raw material for PVC is inverted and imposition of measures will have an adverse impact. There are a few producers of PVC and thousands of end-users.
- g. The anti-competitive practices of the applicants have made the condition of the end users more critical. The applicants are misusing the trade remedial measures by seeking measures for several products.
- h. Since imposition of measures is not in the public interest, the investigation must be terminated, as done by the Authorised Officer in Methyl Acetoacetate.
- i. The imposition of measures would result in an increase in prices.
- j. The pipe demand in construction and agricultural sector was slowly increasing after Covid, which would be impacted by any measures imposed.

N.2.Submissions by the domestic industry

159. The following submissions were made by the domestic industry with regard to the public interest.
- a. Public interest must be seen in light of the interests of producers, consumers and public at large.
 - b. Contrary to the submissions of the other interested parties, the imposition of measures will not impact the prices of the downstream industry as the measures are for imposition of quantitative restrictions and not safeguard duties.
 - c. As opposed to the contentions of the other interested parties, the downstream industry remained competitive in the past, that is, prior to the surge in imports, when it was procuring the subject goods at a much higher price.
 - d. Anti-dumping duty in force till February 2022 did not adversely impact the downstream industry, or the exports by the downstream industry.
 - e. Contrary to the contentions of the other interested parties, there cannot be a monopolistic advantage to the domestic industry as there are five producers in India and a number of exporters competing in the Indian market.
 - f. Imposition of safeguard measures will not hamper the availability of the subject goods in India as the measures will be applied only on imports of PVC Suspension Resins with RVCN above 2 PPM and the like article will be freely imported in India. Prior to the most recent period and April-June 2021, 96% imports were that of PVC Suspension Resins with RVCN upto 2 PPM, which will continue.
 - g. The producers of PVC Suspension Resins with RVCN upto 2 PPM even from China PR will be able to export freely post recommendation of measures.
 - h. Recommendation of quantitative restrictions can take into account the present as well as the future demand in India.
 - i. Contrary to the submissions of the other interested parties, there was no imbalance of demand-supply in India prior to the surge period. The measures will ensure a situation similar to that prior to the surge period.
 - j. The other interested parties have not submitted any evidence regarding any anti-competitive practices by the applicants.
 - k. The users have not suffered due to unavailability of raw material prior to the surge in imports of product under consideration. Hence, there can be no adverse impact of imposition of safeguard measures.
 - l. The value chain of most products subject to trade remedial measures is inverted, since the number of users is invariably greater than the number of producers. However, this cannot deny the producers genuine remedy.

- m. Any measures recommended by the Authorised Officer, are post a detailed investigation and not just on request of the domestic industry. Thus, there can be no misuse of trade remedial measures.
- n. Since imports of PVC Suspension Resins with RVCM above 2 PPM is harmful for the environment, imposition of measures will regulate such imports and protect the environment from unnecessary harm.

N.3.Examination of the Authorised Officer

160. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:

“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”

- 161. In view of the aforesaid, there is a need to examine whether imposition of safeguard measures shall be in public interest. Though Article 3.1 does not provide any guidance on the manner of evaluation, the same, however, requires, inter alia, evaluation of impact of the safeguard measures on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties.
- 162. With regards to the submissions of the other interested parties that the imposition of safeguard measures will render the users uncompetitive, the Authorised Officer notes that the present investigation is with regard to imposition of Quantitative Restrictions measures and that too only on certain PVC Suspension Resins, that is PVC with RVCM content of above 2 PPM. Thus, the imports of PVC with RVCM content upto 2 PPM would continue to be freely imported. Since no safeguard duties will be recommended pursuant to the present investigation, the prices of the users will not be hampered. In any case, the Authorised Officer notes that there was an anti-dumping duty in place on imports of PVC Suspension Resins from China PR, Thailand and USA till February 2022. There is no evidence adduced by any party that the users of the subject goods were adversely impacted during such period of anti-dumping duty. Thus, any increase in prices is not likely to render the users uncompetitive.
- 163. With respect to the demand-supply gap in India, the Authorised Officer notes that the measures will be imposed only on those producers which export PVC Suspension Resins with RVCM above 2 PPM, and the no measures will be imposed on imports of like article in India. The Authorised Officer notes that prior to the surge period, about 77% imports were that of the like article, and thus any demand-supply gap can be fulfilled by such imports. In any case, the measures recommended will take into the account the current demand-supply gap as well as the anticipated growth in future demand. Thus, imposition of safeguard measures will not hamper the availability of subject goods in India.
- 164. Some of the interested parties have submitted that imposition of measures would allow the domestic industry to form a cartel and create a monopolistic competition in India. The Authorised Officer notes that there are a number of producers of like articles in India. Further, the domestic producers are competing not just with each other but also with imports of like article in India. In a situation where 35 – 45 % of the consumption was being met by non-subject imports and no measures are being recommended for imports of these like article, a healthy competition between the domestic producers and imports will continue to prevail in India.
- 165. With regards to alleged anti-competitive practices of the domestic industry in India, the Authorised Officer notes that no evidence has been placed on record regarding such practices. Furthermore, considering that the present domestic industry met only 10-20% of the demand in India during the relevant period. It is also noted that there are three other domestic producers besides the two applicants. Thus, there is sufficient competition in the domestic market and issues of creation of monopoly by the domestic industry is unlikely.

O. CONCLUSION

166. On the basis of the examination and analysis made above, the Authorised Officer concludes the following:

- (i) There has been a significant increase in imports of the product under consideration in absolute as well as relative terms.
- (ii) The increase in imports of the product under consideration is due to unforeseen developments.
- (iii) The imports of product under consideration were undercutting the prices of the domestic industry and caused a strain on the selling price of the domestic industry in the domestic market. The domestic industry has been forced to reduce its prices to maintain its customer base.

- (iv) The market share of imports of the product under consideration has increased in India.
- (v) The domestic industry has started suffering serious injury in the most recent period, as profits, cash profits and profits as a percentage of selling price of the domestic industry declined significantly. Further, the inventories of the domestic industry increased significantly in the most recent period.
- (vi) The serious injury to the domestic industry is due to imports of product under consideration.
- (vii) Imposition of safeguard measures, in the form of quantitative restrictions, would be in public interest. It will prevent serious injury to the domestic industry, while having an insignificant and bearable impact on the downstream industry as the demand of the subject goods would continue to be met by way of imports of like article in India.
- (viii) The total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period is [***] MT. The sales of the domestic industry and other Indian producers amounted to about [***] of the total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period, whereas the imports of PVC Suspension Resins with RVCM content upto 2PPM have amounted to about [***] of the total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period. The Authorised Officer notes that any potential demand-supply gap of PVC Suspension Resins in India may be filled by imports from countries which have been excluded from the application of the measure, or from imports of PVC suspension resins with RVCM content upto 2PPM.

P. RECOMMENDATION

167. In view of the aforementioned analysis, it is concluded that;

- (i) The product under consideration, that is, PVC Suspension Resins with RVCM above 2 PPM, has been imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry manufacturing like or directly competitive products.
- (ii) The domestic industry has started suffering serious injury in the most recent period.
- (iii) The existing circumstances justify imposition of quantitative restrictions in order to prevent the domestic industry from further serious injury.

168. Accordingly, the Authorised Officer recommends the following measures:

- (i) The imports of the product under consideration are regulated and permitted not beyond the levels as mentioned in the Table below. This quantum has been derived in terms of Rule 9(1) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, based on an average of imports in the three representative years during the period of investigation, that is, 2019-20, 2020-21 and 2021-22. Further, the quotas recommended in the table below are after keeping in view the demand-supply gap in India and the demand growth during the period from April 2019 to June 2022 (39 months).
- (ii) The product under consideration, if produced in other developing countries (barring that mentioned in Table below), shall not be subject to the measures recommended since the investigation has not revealed any imports from other developing countries. The product produced in developed countries shall not be subject to the recommended measures, subject to evidence provided in the form of certificate of analysis or otherwise, that the RVCM content of the product imported is less than 2 PPM.
- (iii) The Directorate General of Foreign Trade ("DGFT") had issued a Notification bearing file no. 01/92/180/106/AM-11/PC-VI/PRA dated 31st January 2013 wherein it had notified a list of developing countries under Section 9A(4)(a) of the FTDR Act, 1992. This notification was based on the Notification issued by Department of Revenue. However, the Authorised Officer has noted that the list of developing countries has been subsequently revised by the Department of Revenue vide Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February 2016. As the imports from the developing countries listed in the said Notification No. 19/2016-Custom (NT), dated 5th February 2016, other than China PR do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of "PVC Suspension Resins with RVCM above 2 PPM" originating from such developing countries (other than China PR) will not attract Quantitative Restrictions in terms of Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
- (iv) The Authorised Officer recommends imposition of Quantitative Restrictions only on imports of PVC Suspension Resins with RVCM **above** 2 PPM. The producers / exporters manufacturing PVC Suspension Resins with RVCM upto 2 PPM will not be subject to any restrictions. While the Authorised Officer has relied upon the specification sheets, COA and submissions made by the parties in order to evaluate whether the producer had exported the product under consideration (i.e., **above** 2 PPM resin) or the directly competitive article (i.e., **upto** 2 PPM resin), for the reasons specified above, for the purposes of implementation, it would be appropriate to consider the specifications of the product on the basis of

certificate of analysis, which may be presented with each import consignment to decide whether the import is of the product under consideration or the directly competitive article.

- (v) The imports would be permitted through the EDI ports only to facilitate electronic/ real-time monitoring of the allocated quota. The quota would be monitored on quarterly basis. The total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the next quarter. Any unutilized quota for a quarter shall be added to next quarter. Further, any excessively utilized quota for a quarter shall be deducted from the quota for the next quarter. This would ensure that the exporters and the associated importers would be able to regulate the volumes smoothly. Thus, allocation of quota in such a manner would ensure that users, importers and exporters do not suffer any undue hardships. If necessary, further modalities for governing such Quantitative Restrictions may be notified, in accordance with relevant legal provisions.
- (vi) Accordingly, the Authorised Officer, in accordance with Section 9A(l) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, recommends imposition of quantitative restrictions on the imports of the subject goods for a period of one year from the date of the notification under the FTDR Act.

Quotas (in MT)**

Quarter	1 st	2 nd	3 rd	4 th
Total PUC*	54,203	54,920	55,646	56,382
Imports from China	20,494	20,765	21,039	21,317
Imports from Taiwan	15,100	15,299	15,502	15,707
Imports from USA	9,690	9,818	9,948	10,079
Imports from Russia	8,920	9,038	9,157	9,279
Imports from other developing countries	Countries as per list below are exempt from imposition of safeguard measures**			
Imports from other developed countries	No known imports of the product under consideration above 2 PPM			

*Based on imports during 2019-20, 2020-21 and 2021-22 and as defined in para 12 (j) of this report

****The Authorised Officer has determined the quota by taking an average of import volumes of the PUC in India for three years preceding the most recent period. The figure arrived has been apportioned on a quarterly basis by considering the growth of demand over the period.**

169. The total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period is [***] MT. The sales of the domestic industry and other Indian producers amounted to about [***] of the total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period, whereas the imports of PVC Suspension Resins with RVCM content upto 2 PPM have amounted to about [***] of the total domestic demand of PVC Suspension Resins in India during the most recent period and have varied in the range of [35% – 45 %] in the previous years. The Authorised Officer notes that any potential demand-supply gap of PVC Suspension Resins in India can be fulfilled by imports from countries which have been excluded from the application of the measure, or from imports of PVC suspension resins with RVCM content upto 2 PPM.

List of developing countries, in accordance with Notification No. 19/2016-Custom (NT) dated 5th February 2016

1. Afghanistan
2. Albania
3. Algeria
4. Angola
5. Armenia
6. Azerbaijan
7. Bangladesh
8. Belarus
9. Belize
10. Benin
11. Bhutan
12. Bolivia (Plurinational State of)

13. Bosnia and Herzegovina
14. Botswana
15. Brazil
16. Bulgaria
17. Burkina Faso
18. Burundi
19. Cabo Verde
20. Cambodia
21. Cameroon
22. Central African Republic
23. Chad
24. Colombia
25. Comoros
26. Congo
27. Costa Rica
28. Côte D'Ivoire
29. Cuba
30. Democratic People's Republic of Korea
31. Democratic Republic of the Congo
32. Djibouti
33. Dominica
34. Dominican Republic
35. Ecuador
36. Egypt
37. El Salvador
38. Eritrea
39. Ethiopia
40. Fiji
41. Gabon
42. Gambia
43. Georgia
44. Ghana
45. Grenada
46. Guatemala
47. Guinea
48. Guinea Bissau
49. Guyana
50. Haiti
51. Honduras
52. Indonesia
53. Iran (Islamic Republic of)
54. Iraq

55. Jamaica
56. Jordan
57. Kazakhstan
58. Kenya
59. Kiribati
60. Kyrgyzstan
61. Lao People's Democratic Republic
62. Lebanon
63. Lesotho
64. Liberia
65. Libya
66. Madagascar
67. Malawi
68. Malaysia
69. Maldives
70. Mali
71. Marshall Islands
72. Mauritania
73. Mauritius
74. Mexico
75. Micronesia (Federal State of)
76. Mongolia
77. Montenegro
78. Morocco
79. Mozambique
80. Myanmar
81. Namibia
82. Nepal
83. Nicaragua
84. Niger
85. Nigeria
86. Pakistan
87. Palau
88. Palestine
89. Panama
90. Papua New Guinea
91. Paraguay
92. Peru
93. Philippines
94. Republic of Moldova
95. Romania
96. Rwanda

97. Saint Lucia
98. Saint Vincent and the Grenadines
99. Samoa
100. Sao Tome and Principe
101. Senegal
102. Serbia
103. Sierra Leone
104. Solomon Islands
105. Somalia
106. South Africa
107. South Sudan
108. Sri Lanka
109. Sudan
110. Suriname
111. Swaziland
112. Syrian Arab Republic
113. Tajikistan
114. Thailand
115. The former Yugoslav Republic of Macedonia
116. Timor-Leste
117. Togo
118. Tonga
119. Tunisia
120. Turkey
121. Turkmenistan
122. Tuvalu
123. Uganda
124. Ukraine
125. United Republic of Tanzania
126. Uzbekistan
127. Vanuatu
128. Viet Nam
129. Yemen
130. Zambia
131. Zimbabwe

ANANT SWARUP, Authorised Officer